हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

13 जून, 2005

खण्ड, अंक 2

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार, 13 जून, 2005

पृष्ठ संख्या

शोक प्रस्ताव	1
तांराकित प्रश्न एवं उत्तर	2
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तांराकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	24
वर्ष 2003–06 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा	28

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 13 जून, 2005

विधान सभा की बेठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन सेक्टर– 1, चण्डीगढ में 2.00 बजे मध्याह्न पश्चात हुई। अध्यक्ष (सरदार एच०एस०चडा) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, अब मुख्यमंत्री जी शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष जी, 9 जून को हरियाणा में एक भीषण तूफान कई इलाको मे आया। इससे प्रदेश मे कई जाने गयी यहा तक कि, एक चार साल का बच्चा भी उस तूफान में मारा गया। इस तूफान में कुछ जानवर भी मारे गये। काफी नुकसान हमारा इस तूफान से हुआ। जिनकी इस तूफान में जाने गयी हैं उनके बारे में मैं एक शोक प्रस्ताव सदन मे रखता हूं– –

यह सदन 9 जून, 2006 को राज्य के विभिन्न भागों मे आए भीषण तुफान में मारे गये लोगों के दुखद एव असामायिक निधान पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। ''

डा० सुशील इन्दौरा (ऐलनाबाद एस०सी०): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमत्री जी शोक प्रस्ताव लाए हैं। जो भीषण तूफान 9 जून को आया था उसमें कई जाने भी गयी हें और उससे हमारे प्रदेश को बहुत नुकसान भी हुआ है। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी के नेता श्री ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से भी शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और साथ ही एक बात की तरफ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान भी आकृष्ट करना चाहूंगा कि यह एक ऐसी परिस्थिति हुई कि अचानक एक हादसे के तौर पर यह तूफान आया। इस तूफान से खास तौर से जो मेरा जिला हे या जो सिरसा पार्लियामैंट की कांस्टीच्यूसी के फतेहाबाद आदि ऐरियाज पड़ते हैं, वे काफी प्रभावित रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वहां पर जाकर आये हैं जिसके लिए मैं इनका आभार भी व्यक्त करता हूं। मेरा सरकार से निवेदन है कि जो इस तूफान से वहां पर नुकसान हुआ है उसके बारे में गहराई से सोचते हुए सरकार को उचित कारवाई करने का काम करना चाहिए।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): स्पीकर साहब, हरियाणा में आए भीषण तूफान की चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। इस तूफान से जान और माल दोनो की हानि हुई। में मुख्यमंत्री जी द्वारा लाए गए शोक प्रस्ताव के अनुमोदन मे बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, 24 घंटे के अदर माननीय मुख्यमंत्री जी खुद वहां पहुंच गए और सरकार ने न केवल वहां

पर हुए जान और माल के नुकसान का पूर्ण मुआवजा दिया बल्कि मुख्यमंत्री जी ने एक पूरा पैकेज वहां के लिए दिया जबकि कई नेता जिनके जिले के अंदर जान और माल की हानि हुई, वे मनाली की वादियो मे घूम रहे थे। एक नया उदाहरण समाज सेवा का भी और सरकार की जिम्मेवारी का मो हमारी सरकार ने स्थापित किया है। अध्यक्ष महोदय, जहां हम शोक संतप्त परिवारो के साथ संवेदना व्यक्त करते हैं वहीं मैं यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो इस बारे में चर्चा की तो मुख्यमंत्री जी के और सरकार के नोटिस में यह मामला है। खुद अपने हाथ से प्रभावित परिवारो के एक एक सदस्य को मुख्यमंत्री जी राशि देकर आए हैं और उनके आसू पोंछकर आये हैं। सरकार इस मामले को लेकर संवदेनशील है और हम अपनी जिम्मेदारी पर खरा उतरेंगे।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, the leaders of different parties have expressed their views and I also associate myself with their feelings and express deep sense of sorrow on the untimely demise of the various people, who lost their lives in the storm in different parts of the State.

Now, I would request you to observe silence for two minutes while standing as a mark of respect to the memory of the deceased.

(At this stage the House stood in silence for two minutes as a mark of respect to the memory of the deceased).

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: ऑनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होगे।

Issuing of N.O.Cs. for Petrol Pumps

***3. Shri Karan Singh Dalal:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state—

(a) the number of petrol pumps for which N.O.Cs. were issued by the State Government for setting up of petrol pumps along the National Highways, State Highways and other roads from January, 2000 to February, 2005 in the State;

(b) whether prior permission from the Ministry of Environment and Forests Government of India was required under Forest Conservation Act, 1980 for changing the use of forest areas/lands to non-forest use or setting up of petrol pumps along the roads; and

(c) the number of petrol pumps for which permission of Government of India, Ministry of Environment and Forests has been obtained before issuing N.O.Cs. to petrol pumps as mentioned in part (a) above ?

उप मुख्यमंत्री (श्री चन्द्र मोहन):

(क) राज्य मे राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों तथा अन्य सड़कों के साथ लगते पैट्रोल पम्पो की स्थापना के लिए जनवरी, 2000 से फरवरी, 2005 तक जिला मैजिस्ट्रेटों द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न प्रकार से है– –

1	राष्ट्रीय राजमार्ग	242

2	राज्य राजमार्ग	297
3.	अन्य सडकें	208
	कुल	747

(ख) ही, श्री मान

(ग) 5 मामलो मे अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से पहले पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्व अनुमति ली गई थी।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब मे जैसा माना है कि 747 पेट्रोल पम्पस को माननीय जिलाधीशों ने एन०ओ०सीज०इशू की और केवल पांच केसिज में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायर्न एंड फौरैस्ट, गवर्नमैंट ऑफ इंडिया से इजाजत ली गई। इस प्रकार से इसमें कानून के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है ओर पर्यावरण के साथ भी खिलवाड़ किया गया है एक तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूगा कि जिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटस ने इन पैट्रोल पम्पस को स्थापित करने के लिए एन०ओ०सी०इशू किए उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है? दूसरे, अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यह भी बताएं कि जहां फरवरी, 2003 तक 747 पैट्रोल पम्पस को एन०ओ०सीज० दिए गए तो पहली मार्च से 21 मार्च, 2005 तक जब नयी विधान सभा के लिए वोटों की गिनती होनी

थी, उस वक्त कितने एन०ओ०सीज० इस तरह से पैट्रोल पम्पस को स्थापित करने के लिए इस प्रदेश मे इशु किए गए?

Mr. Speaker: You put the question. You will get the reply. (Interruptions).

श्री चंद्र मोहनः अध्यक्ष महोदय, 1 मार्च से 31 मई, 2005 तक जो कुल हा स्थलो के लिए एन०ओ०सीज० इशू किए गए उनका विवरण इस प्रकार है राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 22, राज्य राजमार्गों के लिए 25, अन्य सड़क एवं नगर पालिकाओं के लिए 40 यानि कुल 87, मार्च, 2006 में 73, अप्रैल, 2005 में 5 तथा मई, 2006 में 9 स्थलो के लिए अनापत्ति, प्रमाणपत्र जारी किए गए।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि 1 मार्च से 21 मार्च तक भी अंधाधुध तरीके से कानून को ताक पर रख कर रिश्वत लेकर पिछली सरकार के समय उस समय के मुख्यमंत्री ने व उनके परिवार ने लोगों को ये अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए। ये लोग पैसा लेकर के डी०सी० को टैलीफोन किया करते थे। ये लोग यह भी नहीं देखते थे कि एन०एच०ए०आई० ने एन०ओ०सी० दिया है या नहीं दिया है। इस वजह से भी पर्यावरण का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जिन्हे एन०ओ०सीज० इशू हुए हैं उन पैट्रोल पम्प के मालिकों ने बाकायदा चौधरी देवी लाल ट्रस्ट के नाम से रिश्वत के तौर पर चौक से पेमेन्ट की हुई है तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से

मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या वे उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जिन्होंने दबाव में आकर कानून को ताक पर रखकर प्रदेश के पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री जी ने बताया कि हमारी नयी सरकार बनने से पहले जनवरी, 2000 और मार्च, 2005 के बीच मे 87 मे से 73 पैट्रोल पम्पो को एन०ओ०सीज० दिए गए। इस हिसाब से आप स्वयं अन्दाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से पैट्रोल पम्प को एन०ओ०सीज० दिए गए। हालांकि पैट्रोल पम्प को एन०ओ०सी० देना सरकार का काम नहीं है यह काम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का होता है और जैसा कि दलाल साहब ने भी कहा, हम सभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कौ यह लिख रहे हैं कि इन चार चीजों के बारे में क्लीयरैंस चाहिए। ये हैं नेशनल हाई–वे, सी०एल०यू०। फायर सेफटी और ट्रैफिक कन्ट्रोल। इनके लिए हम उनको स्टीपुलेटिड टाईम दे रहे हैं और उनको ये डायरेक्शंज दे रहे हैं दिन इन सभी चीजों की क्लीयरेंस वे स्टीपुलेटिड टाईम में पूरी करवाये। जिन पैट्रोल पम्प की क्लीयरैंस नहीं आयेगी, उनके खिलाफ हम कारवाई करेगे।

श्री अमीर चन्द मक्कड: स्पीकर सर मैं माननीय मुख्यमत्री जी से जानना चाहूंगा कि अभी पैट्रोल पम्प हाई–वेज के साथ लगाने की बात चल रही थी तो क्या ऐसे पैट्रोल पम्प शहर के अन्दर भी लगाने की अनुमति सरकार दे रही है या नहीं?

क्योकि हांसी शहर में 2004 मे जीत कालोनी के अन्दर एक प्लाट मे वेट्रोल पम्प लगाया गया है।

Mr. Speaker: It is not possible to reply particular one station. This question relates to entire state.

श्री अमीर चन्द मक्कड: स्पीकर सर मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या उस पैट्रोल पम्प के बारे मे भी जोकि म्यूनिसिपल कमेटी की जमीन को घेर कर प्लाट में गलत ढग से लगाया गया है, सरकार इन्क्वायरी करवायेगी? (इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

श्री एस०एस० सुरजेवाला: स्पीकर सर, जो यह इतने एन०ओ०सीज० पैट्रोल पम्प लगाने के लिए चुनाव के दौरान वोट पड़ने के बाद दिए गये हैं इन सबमे सरासर अनियमितताएं हैं। न तो उनके पास भारत सरकार की इन्वायर्नमैन्ट एवं फोरैस्ट मिनिस्ट्री की क्लीयरेंस है और न ही उनके पास नेशनल हाईवे अथोरिटी की क्लीयरैंस हैं। जब तक ये इनसे क्लीयरेंस नहीं ले लेते तब तक क्या इन पैट्रोल पम्प के एन०ओ०सीज० को सस्पैंड किया जायेगा?

श्री चन्द्रमोहन: माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आदरणीय श्री सुरजेवाला जी ने सवाल किया है मैं उनको बताना चाहूंगा कि हम इसके लिए उनको कुछ समय देगे। अगर उसके बाद भी वे क्लीयरेंस की शर्तों को पूरा नहीं करते तो उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जायेगा।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और उप– मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार उन पैट्रोल पम्पो के मालिकों से अब यह कहने जा रही है कि जो परमिशन उन्होने उस समय नहीं ली वह अब ले लें ? लेकिन अध्यक्ष महोदय, अब तक तो बहुत बडा नुकसान हो चुका है, कानून की उल्लघंना हो चुकी है और रिश्वत का लेन–देन हो चुका है। में आपके माध्यम से फिर मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जहां कानून की उल्लघंना हुई है और जहां मेनडेटरी प्रोवीजन को तोड़ा गया है क्या ऐसे पैट्रोल पम्पस के मालिको के खिलाफ और उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होने जान–बूझकर रिश्वत ली एवं चौधरी देवीलाल ट्रस्ट में लाखो रूपया लोगों से डरा धमका कर जमा करवाया और एन०ओ०सीज० दिए, कार्यवाही की जाएगी? क्या उस ट्रस्ट की इंक्वायरी करवायी जायेगी कि कितने पैट्रोल पम्प मालिको ने पैसे दिए? क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी जो कानून तोड़ चुके हैं, जिन्होने इस तरह के एन०ओ०सीज० इश्यु करवाये? जैसा कि श्री सुरजेवाला जी ने कहा कि एन०ओ०सीज० आप अब मांग रहे हें आप उनसे कहें कि वो परमिशन लायें और आप उन्हें एन०ओ०सी० दें। क्या ऐसे पैट्रोल पम्प मालिकों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ताकि भविष्य मे ऐसी अनियमितताएं न हों और प्रदेश का पर्यावरण खराब न हो।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा: जैसा मैंने कहा कि उनको थोड़ा समय और देंगे और हर केस का इंडीविज्यूल केस के रूप मे फैसला करेंगे।

श्री रणबीर सिंह महेन्द्रा: अध्यक्ष महोदय, क्या उन एन०ओ०सीज० को उप–मुख्यमंत्री जी विदड्रा कर सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट विदड्रा कर सकते हैं?

श्री चन्द्र मोहन: अध्यक्ष महोदय, मैं अपने काबिल दोस्त को बताना चाहूंगा कि सरकार इनको विदड्रा कर सकती है।

तारांकित प्रश्न सं० 9

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योकि इस समय माननीय सदस्य श्री धर्मपाल सिंह मलिक सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Setting up of a Medical College in Bhiwani

***29. Dr. Shiv Shankar Bhardwaj:** Will the Minister for Health be pleased to State—

(a) whether, there is any proposal under consideration of the Government to set up a Medical College in Bhiwani; and

(b) if so, the time by, which the aforesaid proposal is likely to be materialize?

स्वास्थ्यमंत्री (बहिन करतार देवी):

(क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) –

डा० शिव शंकर भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, दक्षिणी हरियाणा में कोई मैडीकल कालेज नहीं है, सरकार की प्रतिबद्धतता लोगों के स्वास्थ्य के लिए है। भिवानी एक ऐसा स्थान हे जहां सिविल हस्पताल है जो कि सारे एशिया का डिस्ट्रिक्ट लैवल का सबसे बड़ा हस्पताल है इसमें सारे डिपार्टमेंटस हैं मेडीसिन. सर्जरी, गायनी, आइज, स्किन और ब्लड बैंक आदि। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि इस होस्पिटल को मेडीकल कालेज बनाया जाए। इस पर सरकार का बहुत ज्यादा पैसा खर्च होने वाला नहीं है क्योंकि वहां पर सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार है। इसलिए मेरी स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि यहां पर एक मैडीकल कालेज बनाया जाए। ऐसा होने से स्वास्थ्य के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धतता हे, वह पूरी हो जाएगी।

बहिन करतार देवीः अज्ज महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहती हूं कि यह ठीक है कि भिवानी में उभ बैड का अस्पताल है लेकिन वहां पर मैडीकल कालेज बनाने के लिए 25 एकड़ जमीन चाहिए जबकि वहां जमीन केवल 4 एकड़ ही है। अभी तक राज्य में 3 मैडीकल कालेज हैं जिनमे से एक प्राइवेट मेडीकल कालेज मुलाना मे है और बाकी के दो मैडीकल कालेज एक अग्रोहा में और दूसरा पी०जी०आई०, रोहतक में सरकारी तौर पर काम कर रहे हैं।

श्रीमती सुमिता सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से कहना चाहती हूं कि जब केन्द्र में एन०डी०ए० की सरकार थी तो सैन्टर के स्वास्थ्य मंत्री सी०पी० ठाकुर जी करनाल के पास कुंजपुरा में कल्पना चावला के नाम से एक मैडीकल कालेज खोलने की अनाउसमैंट करके गए थे, लेकिन उस अनाउसमैंट के बाद हमें कोई जानकारी नहीं है कि इसके लिए भूमि अधिकृत की गई है या नहीं और न ही इस बारे में हमे कोई ओर जानकारी है इसलिए मैं मंत्री महोदया से जानना चाहूंगी कि क्या करनाल में कोई मैडीकल कालेज खोलने के बारे में सरकार विचार कर रही है?

बहिन करतार देवीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि अभी इस बारे में विभाग के पास केन्द्र सरकार की तरफ से कोई सूचना नहीं आई है।

श्री नरेश यादवः अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदया ने बताया कि भिवानी में 300 बेड का अस्पताल आलरेडी है और मैडिकल कालेज खोलने के लिए उन्होंने जमीन का ही प्रोवीजन बताया है तो मैं इस बारे मे कहना चाहूंगा कि हमारे दक्षिएणी हरियाणा कै एरियाज में जैसे रिवाड़ी, भिवानी, नारनौल और महेन्द्रगढ़ में कोई मैडीकल कालेज नहीं है। अटेली और बाछौद की पंचायत 100 एकड़ जमीन देने के लिए तैयार भी है, वहां अभी मुख्यमंत्री महोदय जी जाकर आए हैं, वहां हवाई पट्टी भी हे, वहां की पंचायत जमीन देने को तैयार हे, वहां आस पास कोई मैडीकल

कालेज नहीं है, इसलिए अगर जमीन ही आधार है और पंचायत जमीन देने को तैयार है तो मै मंत्री महोदया से कहना चाहूँगा कि वहां मैडीकल कालेज बनाया जाए। नारनौल से जयपुर 150 किलोमीटर, नारनौल से दिल्ली 130 किलोमीटर, नारनौल से अग्रोहा, हिसार 250 किलोमीटर पड़ता है। रोहतक में भी एक मैडीकल कालेज और यूनीवर्सिटी है, हिसार मे 2 यूनिवर्सिटीज और मैडीकल कालेज है, करनाल के नजदीक पी०जी०आई० चण्डीगढ़ पड़ता है, हमारा एरिया सबसे दूर है और शहीदों का एरिया है यहां के सैकड़ों जवान कारगिल की लड़ाई मे शहीद हुए हैं।

Mr. Speaker: Yadav Ji, don't deliver the speech. Only put the supplementary. You straightway put the question.

श्री नरेश यादवः अध्यक्ष महोदय, शहीदों के इस इलाके की चिरकालीन मांग है कि नारनौल में कोई मैडीकल कालेज और साथ में अस्पताल बनाया जाए। इससे भिवानी के लोगों को भी फायदा हो जाएगा। चूंकि जयपुर के मैडीकल कालेज मे बहुत भीड़ हो जाती है इसलिए राजस्थान के लोगो को भी बहुत फायदा हो जाएगा।

Mr. Speaker: Yadav Ji, don't deliver the speech. Only put the supplementary. You straightway put the question.

श्री नरेश यादवः अध्यक्ष महोदय, हमारी यही मांग है कि हमे एक मैडीकल कालेज दे दिया जाए क्योंकि दक्षिणी हरियाणा को अभी तक कुछ नहीं मिला।

श्री रामकिशन फौजीः अध्यक्ष महोदय, अभी यहां भिवानी में मेडीकल कालेज खोलने की बात कही गई है, मैंने पिछले हाउस में भी यह कहा था। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, भिवानी भी दक्षिणी हरियाणा में आता है और वहां गरीब लोग रहते हैं तथा वहां पर बहुत सी मौतें समय पर चिकित्सा न मिलने के कारण हो जाती हैं

Mr. Speaker: It is known to everybody. Put the supplementary. (Interruptions) Yadav ji, Take your seat.

श्री राम किशन फौजीः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि हमारी सरकार गरीबो की सरकार है क्या भिवानी में 25 एकड जमीन खरीदकर वहां कोई मैडीकल कालेज बनाया जायेगा ? क्योकि वहां से मरीजों को रोहतक तक लाने में काफी समय लग जाता है और समय पर चिकित्सा न मिलने के कारण कई मौते हो जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री बड़े फ्राखदिल हैं हमें आशा है कि वे हमारी इस मांग को मानेगे।

बहिन करतार देवीः अध्यक्ष महोदय, जो पर्टिकुलर प्रश्न था उसका जवाब तो मैं पहले ही दे चुकी हूं। जहां तक मेरे भाई दक्षिणी हरियाणा की बात कर रहे हैं इस बारे में मैं बताना चाहूंगी कि रोहतक भी दक्षिणी हरियाणा मे आता है और रोहतक मे जो

पी०जी०आई० है उसके दर्ज को बढान कै लिए सरकार विचार कर रही है। अध्यक्ष महोदय, डिमांड रखना अलग बात है और प्रश्न पूछना अलग बात है। प्रश्न का जवाब मै पहले ही भै चुकी हूं। इसके अलावा यादव साहब का एक प्रश्न और लगा हुआ है उसका जवाब भी मैं अभी बता देती हूं।

श्री अध्यक्षः नहीं नहीं मैडम, उस प्रश्न का जवाब आप उसी समय देना जब संबंधित प्रश्न का नम्बर आये।

बहिन करतार देवीः ठीक है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ मैं यह भी बताना चाहूंगी कि मैडीकल कालेज बनाने के लिए केवल जमीन की ही बात नहीं है बिल्डिंग बनाने पर भी खर्चा होता है, स्टाफ का भी खर्चा होता है। इसके अलावा दूसरे खर्चे ही होते हैं। अग्रोहा मेडीकल कालेज का काम काफी दिनो से चल रहा है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। केवल हौर कह देने से मैडीकल कालेज नहीं बनता। इसमें काफी कुछ देखना होता है।

आई०जी० शेर सिंहः अध्यक्ष महोदय, जैसे मेडीकल कालेज रोहतक में है, आज के युग में पैसा हर जगह अपनी भूमिका अदा कर रहा है इसी कारण अच्छे डाक्टर हमारे मैडीकल कालेजों से अपनी नौकरी छोड़कर दूसरी जगहो पर जा रहे हैं। और जो बचे हैं वे भी जाने की कोशिश मे रहते हैं मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इन डाक्टरों को अपने मैडीकल कालेजिज में ही रोकने के लिए उनकी तनख्वाह

बढ़ाने के बारे में विचार कर रही है ? अगर सरकार उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ायेगी तो जो अच्छे–अच्छे डाक्टर हैं वे हमारे मैडीकल कालेजों से नौकरी छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जायेंगे।

Mr. Speaker: It is a suggestion, not the question.

Construction of Tehsil Building in Narnaund city

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): जी, हां

***25. Sh. Ram Kumar Gautam:** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Tehsil Building in Narnaund City, district Hisar ?

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी ने समय की बात की है इस बारे मे मैं इनको बताना चाहूंगा कि नारनौंद शहर में जहां पर तहसील बनाई जानी है उस जगह पर पानी इकट्ठा होता है और हमें लगता है कि यदि उस जगह पर बिल्डिंग बना दी जायेगी तो वह बिल्डिंग कहीं नीचे न बैठ जाये। इनकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर बिल्डिंग बनाने के लिए सरकार की तरफ से 74. 82 लाख रुपये रखे हुए हैं और एफ०डी० से भी एपूवल मिल गई है। लेकिन जो मेन समस्या इसमें आ रही है वह जगह की है वह जगह जोहड़ टाईप है जहां पानी एकत्रित होता है। विभाग को अंदेशा है कि यदि वहां बिल्डिंग बनाई जायेगी तो कहीं वह बिल्डिंग नीचे न धंस जाये।

यदि मेरे साथी की नॉलेज मे कोई और जगह है तो ये बता दें, हम वहां बिल्डिंग बनवा देंगे। वैसे हम भी जगह देख रहे हें।

श्री राम कुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, पानी वहा पर खडा रहता है लेकिन वहां ड्रेनेज न होने की वजह से पानी एकत्रित होता है। यह जगह बहुत बढ़िया है और हार्ट आफ सिटी है। ऐसा नहीं है कि वहां से पानी नहीं निकाला जा सकता। दो—चार दिन का काम है वहां से पानी निकल सकता है। यदि वहां से पानी निकाल दिया जाये तो उससे अच्छी और जगह नहीं होगी।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैंने इनको पहले भी बता दिया है कि पैसा हमारे पास है लेकिन साईट की दिक्कत है। वह साईट जहां पर तालाब है, उसका हम भराव करवाएंगे। डिपार्टमैंट को केवल इस बात का अन्देशा है कि कहीं बिल्डिंग की जमीन न बैठ जाए इसलिए उसको ठीक प्रकार से देखकर उस पर कार्यवाही करेगे।

Sh. Ram Kumar Gautam: Speaker Sir, I would like to know Form the Hon'ble Minister that how much time will you consume ?

Widening of Road from Kutub Minar to Aaya Nagar

***48. Shri Sukhbir Singh Sohana:** Will the Chief Minister be pleased to State--

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to widen the road from Kutub Minar to Aaya Nagar Border with the Consultation of Delhi Government; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized ?

Chief Minister (Shri Bhupinder Singh Hooda):

(a) The road mentioned as Kutab Minar to Aaya Nagar Border falls under the territorial jurisdiction of National Capital Territory of Delhi and is under the control of Municipal Corporation of Delhi. This road leads to Gurgaon. The State Government has requested the Government of Delhi to further widen it to accommodate the increasing traffic. It has been learnt that the Government of Delhi has appointed M/S RITES as a consultant to prepare a proposal for upgradarion of this stretch.

(b) Sine the road falls under the jurisdiction of Government of Delhi, no time frame can be given for completion of the project at this stage. However, matter will be further persued with Government of Delhi.

श्री सुखबीर सिंह सोहनाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को बताना चाहूंगा कि इस सड़क को चौड़ा न करने से सारी स्टेट को बहुत नुकसान हो रहा है क्योकि वहां पर सुबह–शाम तीन–तीन घण्टे तक ट्रैफिक का जाम लगा रहता है। अभी पैट्रोल पम्प को एन०ओ०सीज० देने की बात हो रही थी। महरौली–गुडगांव रोड के ऊपर इनके बहुत

ज्यादा कमर्शियल लाईसैंस दे दिए गए हैं और कई पैट्रोल पम्पस वह। पर चल रहे हैं। वहां पर ट्रैफिक कण्ट्रोल नहीं होता है। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ट्रैफिक जाम रहता है तथा शाम को 5 बजे से रात के नौ बजे तक ट्रैफिक जाम रहता है। जो मल्टी नैशनल कम्पनियां है वे वहां पर आना–जाना पसन्द नहीं करती है। यहा पहुंचने की बजाय नोएडा मे आदमी अपने ऑफिस मे दस मिनट मे पहुंच जाता है। मैं सी०एम० साहब से यह कहना चाहूगा कि जितनी जल्दी हो सके दिल्ली गवर्नमैंट से बात की जाए। इसके साथ ही रंगपुर राजोखरी की तरफ से एक रोड और है उसका भी जल्दी से जल्दी निर्माण करवाया जाए। जब तीन एण्ट्रोज गुड़गांव की हो जाएंग?इताएं तो मैं यह समझता हूँ कि इससे ट्रैफिक कण्ट्रोल हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिए जो भी समय निर्धारित किया जाना है वह निर्धारित किया जाए।

मुख्यमन्त्री (श्री भुपेन्द्र सिंह हुडा): अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैंने बताया है कि यह मामला दिल्ली गवर्नमैंट से कनैक्टिड है और हमारे पास जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार एम०सी०डी० को राईट्स ने रिपोर्ट दी है और उसके लिए दिल्ली गवर्नमैंट ने जमीन ऐक्यायर करनी है क्योंकि वहां पर कुल 36 मीटर चौड़ी सडक है उसको बढ़ाकर 90 मीटर तक करना है उसके लिए जमीन ऐक्वायर की जानी है और हम पूरे प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी ही इस काम को पूरा किया जाए। जो ये ट्रैफिक की बात कर रहे हैं

वह सारी बात हमारे ज्ञान में हैं हम इसके लिए दूसरा रास्ता निकाल रहे हैं जैसे 26 और 26–ए सैक्टर से एक पेराफेरी रोड हमने बनायी है उस पर काम शुरू हो गया है उस पर सादे तीन करौड रुपये खर्च होने का अनुमान है। (विघ्न)

Repair of the Distrlbutaries of Mahindergarh Canal

***21. Sh. Naresh Yadav:** Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether it is a fact that the distributaries of Mahindergarh Canal in Ateli and Nangal Chaudhary Block has been damaged badly, if so, the steps taken or proposed to be taken to repair these distributaries?

राजस्व मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव): जी हां, श्रीमान् जी।

अटेली डिस्ट्रीव्यूटरी व नोलपुर डिस्ट्रीव्यूटरी जोकि क्रमशः अटेली व नांगल चौधरी खण्ड को पानी देती हैं, महेन्द्रगढ़ नहर से निकलने वाली नारनौल ब्रांच की शाखाएं हैं। दोनों डिस्ट्रीब्यूटरियां व उनकी सहायक प्रणालियां खराब हालत में होने के कारण अपनी अधिकृत क्षमता से प्रवाह करने में असमर्थ हैं। अटेली डिस्ट्रीव्यूटरी, सलीमपुर माइनर, नोलपुर डिस्ट्रीव्यूटरी और नागर माइनर अपनी लम्बाई के कुछ भाग तक ही चलती है। सिंचाई विभाग द्वारा अटेली डिस्ट्रीव्यूटरी, नोलपुर डिस्ट्रीव्यूटरी, सलीमपुर माइनर, अटेली माइनर, अटेली सब माइनर, नागर माइनर, शामपुर माइनर, धनताल माइनर। बुधवाल सब माइनर, खेडी माइनर, रामपुरा सब माइनर और बेहली सब माइनर की गाद

निकालने, तटबन्धों को मजबूत करने तथा लाईनिग की मरम्मत करने का एक कार्यक्रम बनाया जा रहा है। इस प्रणाली को पूर्ण पुनर्वास की आवश्यकता है।

श्री नरेश यादवः अध्यक्ष महोदय, मै माननीय मन्त्री महोदय का धन्यवाद तो तब करूंगा जब वह। पर काम की कुछ शुरूआत हो जाएगी सबसे पहले मैं सरकार और मन्त्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा कि पहली बार पानी नांगल चौधरी के आखिरी छोर तक पहुंचा है पिछली सरकार ने इसके लिए खूब प्रयास किए लेकिन पानी वहां तक नहीं पहुंचा क्योंकि उस सरकार के प्रयास ईमानदार नहीं थे। पहली बार कांग्रेस की सरकार ने, भूपेन्द्र सिंह हुडा की सरकार ने ईमानदारी से प्रयास किया और दक्षिणी हरियाणा आखिरी छोर तक यानी नांगल चौधरी, नांगल दरगू तक पानी पहुंचा है (इस समय मेजें थपथपाई गई) अब जिस तरीके से, जिस स्पीड से नहरो में पानी बढ़ रहा है, आ रहा है और 20–20 दिन चल रहा है वह बहुत अच्छी बात है, स्पीकर सर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि अटेली और नांगल चौधरी मे नहरे अटी पड़ी है, दबी पड़ी है वहां पर कैसे काम चलेगा? यहां पर फाईनांस मिनिस्टर जी भी बैठे हुए हैं, मंत्री जी आप इनसे यहीं पर जितना पैसा चाहिए है वह ले लें। हमारे यहां पर पानी का लैवल 1400 फीट नीचे चला गया है, उसको भी उपर लाने का प्रयास करें।

Mr. Speaker: Mr. Yadav, put the supplementary

straightway. Don't deliver the speech.

श्री नरेश यादवः अध्यक्ष महोदय, दक्षिणी हरियाणा में वाटर लेवल को उपर लाने का एक ही तरीका है कि नहरो में पानी आए। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से सवाल है कि वहां पर जितनी भी नहरे और नालें टूटे हुए हैं उनकी कब तक रिपेयर हो जाएगी ? आप इसके लिए समय निर्धारित कर दें ?

Mr. Speaker: Mr. Yadav, this is not the way. Please sit down.

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूगा कि पिछले 15 सालों से नहरो के रख रखाव का काम नहीं हुआ था और न ही उनकी मरम्मत की गई थी। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इन्होंने कहा है कि अटेली डिस्ट्रीव्यूटरी, सलीमपुर माइनर, नोलपुर डिस्ट्रीव्यूटरी और नागर माइनर में पानी जा रहा है। पहले तकरीबन इनमे 60 प्रतिशत नहरो में टेल पर पानी नही पहुंच रहा था। इस सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से पानी को टेलो तक पहुंचाने की योजना बनाई है लेकिन यह सब फंडज की अवेलेबिलिटी पर निर्भर करता है यह काम करने मे 2 वर्ष लगेगे। हम यह सब काम इन स्टेजिज करेंगे क्योकि इसमें काफी पैसा इन्वालव्ड हैं, इसमे 2.00 करोड़ रुपए इन्वालव्ड हैं। इसके अलावा एक बात मैं कहना चाहूंगा कि बी०एम०एल० कैनाल से हांसी लिंक ब्रांच के बीच एक लिंक कैनाल बनाने की जो बात है। मैं खासकर उस के लिए मुख्यमंत्री जी का

धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने यह योजना बनाई है अब बी०एम०एल० कैनाल से हांसी लिंक ब्रांच के बीच इस नयी कैनाल बनाने के बाद नहरों में 24 दिनो तक पानी चला करेगा। उस वक्त दक्षिणी हरियाणा की स्थिति सुधर जाएगी। हम यह सब काम फंडज की अवेलेबिलिटी के आधार पर और योजनाबद्ध तरीके से ही करेंगे।

श्री राधे श्याम शर्मा अमरः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने नांगलदुर्ग तक पानी पहुंचाया है। लेकिन मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वह पानी गांवो मे कब पहुंचेगा? अध्यक्ष महोदय, वहां पर आगे कोई भी नाला खुदा हुआ नहीं है जिसकी वजह से पानी आगे नहीं पहुंच पा रहा है। अब लोग वहां पर यह कह रहे हैं कि यह तो हमारा ड्रामा है। पीछे से तो पानी छोड़ दिया लेकिन आगे नाले खुदे हुए नहीं हैं इसलिए पीछे से पानी छोड़ने का कोई फायदा नहीं है। माननीय मंत्री जी, निजामपुर क्षेत्र, नांगल दुर्ग क्षेत्र और बुरवाल का क्षेत्र है, उसकी नहरों की खुदाई और पाईप लाईन बनाने का काम कब तक शुरू करवाएंगे? अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो मंत्री जी दो करोड़ और दो साल वाली बात कर रहे हैं तो हम किसी भी एन०जी०ओ० से वह काम दो करोड़ की बजाए डेढ करोड़ में करवा देंगे और अगर डेढ़ करोड़ का इनका एस्टीमेटस है तो हम वह काम एक करोड़ मे करवा देंगे। इसके अलावा इन्होने जो

टाईम पीरियड दो साल का बताया है तो उसको एक साल में करवा देंगे। क्या मंत्री जी किसी एन०जी०ओज. को यह काम देने का काम करेंगे?

केप्टन अजय सिह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब मे स्पष्ट कर दिया है कि पानी की मात्रा कम है और एस०वाई०एल० का पानी अभी हमे नहीं मिला हे। इसके बावजूद मुख्यमंत्री जी की मेहरबानी की वजह से ही बी०एम०एल० कैनाल ओर हांसी लिंक ब्रांच के बीच कैनाल बनेगी। यह स्कीम 2.60 करोड़ रुपए की है। इसको बनने मे 2 वर्ष लगेंगे। मैं यह आश्वासन देता दूं कि जैसे ही हमें फंडज अवेलेबल होगे तो जिन माईनर्ज का इन्होने जिक्र किया है उनमें से कुछ माईनर्ज पर हम जरूर काम करेंगे।

श्री दिलू रामः स्पीकर सर, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये नहरे जब से पक्की बनी हैं तब से किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। मेरे हल्के में कम से कम 10 टेलें लगती हैं लेकिन उन टेलों से 10– 10 और 12– 12 किलोमीटर दूर पानी खड़ा है। आज सरकार कहती है कि हमने टेलों पर पानी पहुंचा दिया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे वहां पर पैडी का एरिया है और वहां पर वाटर लैवल इतना नीचे चला गया है जिससे वहां पर किसान बहुत ही दुखी है। 12 सालो से आज तक वहां की नहरों की टेलो पर पानी नहीं पहुंचा है। मैं सरकार से यह आश्वासन चाहता हूं कि क्या वहां टेलों पर पानी पहुचेगा?

कैप्टन अजय सिंह यादवः स्पीकर सर, वैसे तो यह प्रश्न मेन सवाल से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी मैं उनको बताना चाहूंगा कि अगर इनको कोई स्पैसिफिक दिक्कत है तो ये लिखकर हमें दे दे, जहां–जहां भी नहरों में टेल पर पानी नहीं पहुंच रहा है वहां–वहां हम कोशिश करेंगे कि उन नहरो मे टेल पर पानी पंहुचे।

श्रीमती शकुन्तला भगवाडियाः स्पीकर सर, यह बात सही है कि पहले नहरो में बहुत कम पानी जाता था और अब नहरों में काफी समय तक पानी चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, सुबासेड़ी, भगवानपुर, खुरमपुर, टीकला, पनवाड़, प्राणपुरा, रानोली, रनसी मानजरी एवं पॉवटी गांवों की नहरें तो पहले से ही खुदी हुई हैं लेकिन ये सारी नहरें अटी पडी हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या इनको ठीक करवाकर ये इनमें पानी पहुंचाएंगे ?

केप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, पिछले 15 सालो के अंदर जो हालात हुए हैं उसी का परिणाम हैं कि नहरें पूरी तरह से टूटी पड़ी हुई हैं और खास तौर से जे०एल०एन० सिस्टम के अदर की नहरों मे तो बिलकुल भी पानी नहीं जाता था लेकिन अब पहली बार 250 करोड़ रुपये इस वर्ष में हमने इसके लिए रखे हैं। जहां जहां इनको दिक्कत आ रही है ये हमें लिखकर दे दें, उनको दिखवा लिया जाएगा और जिन नहरों मे पानी टेल

पर नहीं पहुंच रहा है उन नहरों मे हम पानी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Please, take your seat. (Interruptions)

श्री भरत सिंहः अध्यक्ष महोदय, आज केवल दक्षिणी हरियाणा की ही बात की जा रही है, सरकार को बाकी हरियाणा की बात भी सोचनी चाहिए। अम्बाला से लेकर पानीपत जिले तक की नहरों मे पहले ताजेवाला से पानी छोडा जाता था। हजारो जगली जानवर आज यमुना मे नहाना चाहते हैं लेकिन वे परेशान हैं क्योकि यमुना सूखी पड़ी हुई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूगा कि जब इतना पानी दक्षिणी हरियाणा के लिए छोड़ा जा रहा है तो क्या दो तीन दिन के लिए पानी यमुना में नहीं छोड़ा रन। सकता ताकि यहां के लोग और जानवर इस गर्मी में परेशानी से बच सके? (इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

Merger of Primary School Teachers

***59. Shri Sher Singh:** Will the Minister for Education be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to merge Primary School Teachers with the Education Department appointment of whom was made by the Zila Parishad, during the last year ; and

(b) whether it is a fact that the teachers

mentioned in part (a) above have not paid their salary since January, 2005, if so, the reasons thereof, togetherwith the time by which the payment of the salary is likely to be made to them ?

Education Minister (Sh. Phool Chand Mullana):

(a) The matter is under consideration.

(b) The salary of 3606 JBT teachers appointed by Zila Parishads in July, 2004 has been paid. However, the salary of 2856 teachers recruited by Zila Parishads in December, 2004 has not been paid so far, for want of financial sanction. The issue of payment of salary will be resolved shortly.

आई०जी० शेर सिंह स्पीकर सर, काफी टीचर अभी जे०बी०टी० मे भर्ती किए गए हैं। पिछली सरकार द्वारा भी तथा हमारी इस सरकार द्वारा भी शायद पहली क्लास से अंग्रेजी विषय को पढ़ाना अनिवार्य किया जा रहा है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या ये सभी टीचर अंग्रेजी पढ़ाने के लायक हैं और अगर पढ़ाने लायक नहीं है तो क्या इनके इस बारे में कोई कोर्स करवाने का प्रावधान किया जाएगा ?

श्री फूलचन्द मुलाना: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अंग्रेजी तो हम पहली क्लास से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं और यदि अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाने के काबिल नहीं है तो सरकार ने विचार किया हे कि जे०बी०टी० की

ट्रेनिंग करने के लिए प्लस टू के बजाए बी०ए० पास बच्चों का जे०बी०टी० में दाखिला करेंगे।

Setting up of 33 kv Sub-station, Sherla and Singhani

***39 Shri Somvir Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the time by which the 33 kv Sub-station, Sheria in district Bhiwani will be started/completed the foundation stone of which was laid down on 16-12-2004; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up 33kv Sub-station at Singhani in district Bhiwani; if so, the time by which said proposal is likely to be implemented ?

Chief Minister (Shri Bhupinder Singh Hooda):

(a) The 33kv Sub-station, Sherla is likely to be commissioned by December 2006.

(b) There is a proposal under consideration to create 33kv Sub-station at Singhani in district Bhiwani.

श्री सोमवीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, इस सब–स्टेशन क्य फाउंडेशन स्टोन 2004 के दिसम्बर महीने में रखा गया था। करीब 6 महीने इस काम को हो गये हैं। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस देरी का क्या कारण है? इसके अलावा जो भिवानी जिले में सिंघानी के अंदर 33 के०वी० सबस्टेशन बनाने के लिए प्रपोजल भेजी हुई है। चीफ इंजीनियर,

हिसार को यह प्रोपोजल भेजे हुए 2 साल से ज्यादा समय हो गया है मैं जानना चाहूंगा कि इस प्रोपोजल को मंजूर करने मे कितना समय और लगेगा 9 इसके अलावा जो ढिगावा से सिंघानी गाट को बिजली आती है उसका पावर स्टेशन कितना ओवरलोडेड है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): स्पीकर साहब, जैसा इन्होंने जिकर किया हे तो इसका Foundation stone was laid down on 16-12-2004. It takes one and a half year for commissioning and erection. It will take time. It will be completed by 2006. About Singhani, this is at preliminary stage. Village has offered land but feasibility report has not come . If, we order for the feasibility report, it will take 3 months and if it is found positive then we will take up it.

राव दान सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि हमारा क्षेत्र टयूबवैल पर कृषि के लिए आधारित है वहां पर एक सेलग गांव है जो कि कई गांवों का बड़ा समूह है जहां पर काफी लम्बे समय से एक सब–स्टेशन लगाने की मांग चली आ रही है। मुख्यमंत्री जी अभी पिछले दिनों जब वहां दौरे पर थे तब भी उनके समक्ष यह मांग आई थीं। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी कोई प्रपोजल प्रस्तावित है कि आने वाले समय के अंदर वहां पर 33 के०वी० का सब–स्टेशन लगाया जाएगा।

Shri Bhupender Singh Hooda: It is not the part of

question.

श्री सोमवीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैंने ढिगावा का 133 के०वी० का पावर हाउस है उसके बारे में पूछा था, यह 1988 के अंदर बना था। वहां से बिजली सिंघानी गांव को आती हैं, मैंने जानना चाहा था कि ढिगावा का पावर हाउस कितना ओवरलोडिड है?

Mr. Speaker: It is not possible to tell about a particular station.

Check the Unemployment in the State

***36. Dr. Sita Ram:** Will the Minister for Finance be pleased to state the steps so far taken or proposed to be taken to check the problem of increasing unemployment in the State ?

Finance Minister (Shri Birender Singh): Sir, a statement is placed on the Table of the House.

Statement

The Government has announced its new Industrial Policy, which has become applicable with effect from 6th June 2005. The basic objective of the Industrial Policy is to create maximum employment opportunities in the manufacturing and service sectors by developing high-class infrastructure, simplification of rules and regulations governing industry and incentives/concessions to the industry in the backward/ rural areas. The State Govenment also plans to develop economic hubs at strategic locations for the overall growth of the

economy. It is estimated that these steps would create employment for about one million persons in the next ten years.

The Rural Development Department is implementing various Centrally Sponsored Poverty Alleviation Programmes in the rural areas, under the Swaranjayanti Gram Swarozgar Yojana and Sampooran Grameen Rozgar Yojana (SGRY). The target groups consist of the families living below the poverty line. The programmes are implemented in accordance with the prescribed guidelines issued by the Ministry of Rural Development, Government of India. Under the Swaranj ayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY), 14,132 beneficiaries were provied with financial package in the shape of subsidy and bank loan, to the tune of Rs. 1566.71 lacs during 2004-2005. The Govt. of India had merged the schemes of Jawahar Gram Samridhi Yojana and Employment Assurance Scheme from the year 2001-2002 onwards and had launched a new scheme known as Sampooran Grameen Rozgar Yojana (SGRY). This scheme has been designed to provide additional wage employment in the rural areas and also creation of durable community assets at the village level. The SGRY is open to all rural poor who are in need of wage employment and desire to do manual and unskilled work in the rural areas. During the year 20042005, a total number of 18, 135 works were undertaken generating 70.12 lac Mandays on which an expenditure of Rs. 6794.28 lacs was incurred.

The State Urban Development Society, Haryana is implementing Swarna Jayanti Shahari Rozgar Yojana (SJSRY) with the object of providing Self-Employment and Wage-

Employment to the Below Poverty Line (BPL) urban people. During the year 2004-2005, 1845 persons were provided loan and subsidy and 0.35 lac Mandays were generated.

From March 2005 to May 2005, the Haryana Scheduled Castes Finance and Development Corporation has assisted, 2,173 Scheduled Caste persons for taking up Self-Employment schemes by providing them financial assistance of Rs. 511 lacs, which includes Rs. 168 lacs as subsidy. The Corporation proposes to assist 15,000 Scheduled Caste persons by providing them a total financial assistance of Rs. 4971 lacs for Self-Employment schemes during the current financial year 2005-2006.

Haryana Backward Classes and Economically Weaker Section Kalyan Nigam proposes to provide self-employment to 5,000 persons during 2005-2006.

Fisheries Department has provided technical and financial assistance to new 116 fish farmers during the year 2004-2005 and also provided indirect part-time employment to 158 persons involved in fish seed supply, fish harvesting and fish marketing activities. The department plans to provide direct full time employment opportunities to an additional 500 persons by adopting fish farming as a profession during the year 2005-2006.

Development and Panchayats Department has spent Rs. 1427.50 lacs approximately for generating 15,86,111 Mandays of employment. The department proposes to generate 30,87,500 Mandays of employment at an estimated cost of Rs. 2778.75 lacs during the year 2005-2006.

Animal Husbandry and Dairy Development Department established 2,112 dairy units during 2004-2005 and a target of 2500 Dairy Units has been laid down for the current financial year involving self-employment of 2500 persons.

The number of seekers who were placed in gainful employment through Employment Exchanges during 2004-2005 is 2,850. The number ofjob seekers on the live register of the Employment Exchanges in the State, as on 30-4-2005 was 9,83,553. The number of Conselling/Vocational/Career Guidance Groups organised during the year 2004-2005 is 4,788, in which 2,14,462 participants took part. An amount of Rs. 543.59 lacs was disbursed from 1-4-2004 to 30-4-2005 as Unemployment Allowance. The number of eligible applicants as on 30-4-2005 stood at 1,32,651.

डॉ० सीता रामः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपने जवाब मे बताया है कि हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम ने 2005–206 वित्त वर्ष के दौरान स्वरोजगार योजना के लिए केवल 49.71 करोड़ रुपया अनुसूचित जाति के 15 हजार व्यक्तियों की सहायता के लिए रखा है। इन्होंने इसके अलावा कहीं कोई जिक्र नहीं किया कि बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाएगा क्योंकि चुनाव के दौरान इन्होने बड़े जोर शोर से कहा था कि सरकार आने के बाद बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा।

Mr. Speaker: Dr. Sahib, don't deliver the speech. Please put the supplementary.

डॉ० सीता रामः सर, मैं क्यैश्चन ही पूछ रहा हूं। चुनाव के समय यह प्रचारित किया गया था कि सरकार आने के बाद बेरोजगारो को रोजगार दिया जाएगा। कृपा करके यह बताने का कष्ट करें कि इसके बारे मे 'कोई अलग से स्टैप्स उठाए गए हैं या नहीं?

श्री बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य ने जानना चाहा था कि अनइफ्लौयमैंट को चौक करने के लिए सरकार क्या–क्या प्रयत्न कर रही है। इसके बारे में मैंने जो व्यौरा दिया है इन्होंने उसमें से केवल एक पार्ट का हवाला दे दिया कि शिडयूल्ड कास्ट्स के लोगो की सहायता के लिए 49.71 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। ये सारी सटेटमैंट को जब पढ़ेंगे तो उससे इनको पता लगेगा कि हर क्षेत्र के अंदर बेरोजगारी की जो समस्या है वह किसी एक साधन से नहीं निपटी जा सकती। हमने 6 जून को जो औद्योगिक नीति की घोषणा की है, उसमे अगर ये झांककर देखेगे तो पाएंगे कि उससे 10 लाख के करीब रोजगार उपलव्य होगे। इनके समय मे उद्योग पलायन कर गए थे और उद्योगपतियां के घरो कै या बिल्डिंगों कै सामने व –4 फुट गहरी खालिया खुदवा दी गई थी ताकि उनका सामान न जा सके, न आ सके। जब तक पैसे की बात तय नहीं हो जाती थी तब तक उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता था। आज हम हरियाणा के अन्दर एक ऐसा वातावरण तैयार कर रहे हैं जिसमें उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और बाहर से निवेश के लिए हमारा अन्दाजा है कि

नई औद्योगिक नीति के अनुसार 2 लाख करोड़ रुपये तक के निवेश की हम कोशिश करेगे। यह तो एक पक्ष है दूसरी तरफ कृषि को उन्नत बनाने के लिए, कृषि के धन्धे को एक लाभकारी धन्धा बनाने के लिए भी हमने पग उठाये हैं। जैसे डाईवर्सीफिकेशन है ओर अच्छी मार्केटिंग फैसिलीटीज हैं उनको हम बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि ये दो क्षेत्र ऐसे है जिनसे कि मैं समझ हूं कि 70 प्रतिशत तक बेरोजगारी की समस्या हल हो सकती है। इसके अलावा जो सरकारी नियुक्तियां हैं उनमे जिस प्रकार से पहले धांधलेबाजी होती थी, उसको खत्म करने के लिए और पारदर्शिता स्थापित करने लिए हमने हरियाणा स्टाफ सिलैक्शन कमीशन को भंग कर दिया है। इसकी वजह से एक अशान्ति और एक ऐसा वातावरण तौजवानों में पैदा हो गया था कि उनको यह लगता था कि हमारा नम्बर नोकरी के लिए कभी नहीं आयेगा। इस सरकार ने आश्वासन दिया है और आज के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं जब ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होते थे तब भी यह कहते थे कि हमारा यह लक्ष्य है कि हर हाथ को काम मिले और इस बात को हमने अपने चुनाव घोषणा–पत्र में भी रूखा था। हम अपने निश्चय पर आज भी दृढ़ है। आप देखेंगे कि आने वाले समय में बेरोजगारी को दूर करने के लिए हम काम करेंगे और इसमें हम कामयाबी हासिल करेगे, ऐसा हमारा विश्वास है।

डा० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि अभी–अभी इन्होंने

बेरोजगारी को दूर करने के बारे मे कहा है। दो–तीन दिन पहले एक लेडी कांस्टेबल ने आत्महत्या की थी क्या वह भी इनके आश्वासन का हिस्सा है या नहीं?

श्री बीरेन्द्र सिंहः अगर ऐसा कोई आत्महत्या का दोष किसी पर जाता है तो वह श्री ओमप्रकाश चौटालाः और उसकी पार्टी पर जाता हे आज की कांग्रेस की सरकार पर नहीं जाता।

श्री राधेश्याम शर्मा अमरः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस तरह जो आत्म हत्याएं हुई हैं वह इसलिए हुई है क्योंकि पिछली सरकार ने भर्तियों में गड़बड़ी की थी। क्या मंत्री जी या सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी या नहीं?

श्री बीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, जब इस वर्ष का बजट पेश हुआ था उस दिन प्रैस के सामने मुख्यमंत्री जी ने सरकार का पक्ष रख दिया था। आज भी हमारा वहीं पक्ष है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से और हडबड़ाहट से एवं जिस राजनीतिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर वोट हासिल करने के लिए ये नियुक्तियां की गई थी, उसमें पूरी पद्धति को अडोप्ट नहीं किया गया था इसलिए यही कारण है कि हमे इन नियुक्तियो को विदड्रा करना पड़ा।

मुख्यमन्त्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुडा): अध्यक्ष महोदय, जो यह चर्चा की गई है इस बारे मे मैं सदन को बताना चाहूंगा। में

इस बारे में पहले भी कह चुका हूं कि जिस प्रकार से ये भर्तियां की गई हैं उससे इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है इसलिए श्री ओमप्रकाश चौटाला को पूरे हरियाणा सै और उन लोगो से माफी मांगनी चाहिए। उस बिल के ओबजैक्टस और रीजनज में यह लिख दिया कि एच०आई०एस०एफ० का यह खर्चा इण्डस्ट्रीज, बैंक, बोर्ड और कोरपोरेशज वहन करेगे और जब एक्ट रखा गया और वह पास किया गया तो उसमें यह लिखा कि नोटिफिकेशन होगी, एक डी०जी०पो० बनेगा, रूल्ज बनेगे लेकिन कोई कुछ प्रोवीजन नहीं किया गया। यह सरकार आने के बाद हमने पूरा प्रयास किया कि इन बच्चों के भविष्य के साथ जो पहले खिलवाड़ किया गया है वह आगे न 'हो। हम किसी के बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते। हमारी सरकार ने पूरा प्रयास किया और सारी इण्डस्ट्रीज, बैंक, बोर्ड और कारपोरेशंज को लिखा और उनसे पूछा कि क्या उनको इस फोर्स की जरूरत है या नहीं? लेकिन किसी की तरफ से कोई रिक्वायरमैंट नहीं आई। हमारी सारी कोशिश करने के बाद भी सरकार के दास कोई रास्ता नहीं निकला इसलिए हमें इस भर्ती को निरस्त करना पड़ा। उस समय मैंने कहा था कि हम जल्दी ही पुलिस रिकुटमेंट करेंगे, दूसरे विभागो की भी रिकुटमैन्ट करेगे। उस भर्ती में इन बच्चो को जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनके साथ खिलवाड नही करेगे। उनको इस भर्ती में लीवरेज दी जायेगी। पहली सरकार ने कभी लीवरेज नहीं दी थी, यह बात सारी असैम्बली को पता है कि जब श्री ओमप्रकाश चौटाला ने यह

बात असैम्बली में कही थी कि इस भर्ती का खर्चा इण्डस्ट्रीज, बैंक, कारपोरेशंज वहन करेगी। परन्तु बहुत से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। यह सरकार किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। यह सरकार जो कार्य करेगी, पक्के करेगी। ये बच्चे हमारे बच्चे हैं हम उनके हितों का पूरा ध्यान रखेंगे। ?

Mr. Speaker: This is the last supplementary. **I** will not allow after that. Indora Ji, please go ahead.

डॉ० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हम बच्चो के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। अगर मुख्यमंत्री महोदय को यह विसंगतियां लगती थीं तो बजाय इन विसंगतियों को दूर करने के सरकार ने क्यो ऐसा कदम उठाया कि उन बच्चों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा? (विघन)

Mr. Speaker: Dr. Sahib, it is not the supplementary. Please take your seat. Mr. Indora, it is not the way.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुडाः इन्दौरा साहब, आप लोगो ने ही उनको बाहर निकाला और उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। यह सब तुम्हारी कार्यवाही है। चुनाव से पहले लोगों को झूठे सपने दिखाकर हरियाणा के लोगो के भविष्य के साथ

खिलवाड़ करने का काम आप लोगो द्वारा ही किया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि माननीय इन्दौर। जी और उनके नेता की आत्मा आज उनको कनोटती जरूर होगी क्योकि इन्होंने 27 हजार कर्मचारियो की बर्खास्तगी की। उन कर्मचारियों के परिवार आज दयनीय हालत में दर–दर की ठोकरें खा रहे हैं। इन्दौरा जी और उनकी पार्टी के नेता आज तो मगरमच्छी आसू बहाते हैं लेकिन उस वक्त ये कहां गए थे जब कर्मचारी उनके पास आते थे? इन्दौर। जी और उनकी पार्टी के नेता और इनकी पार्टी के लीडर उनको लाठियो से पिटवाते थे। 27–27 हजार कर्मचारियो की बर्खास्तगी इन्होंने की। I am on the floor, you have been in the Parliament. I am still speaking. I have not said down earlier. (Interruptions) मगरमच्छी आसू अगर किसी ने बहाए, हरियाणा के लोगों के साथ अगर किसी ने अन्याय किया तो वह लोकदल के साथियों ने किया, इन्दौरा जी और इनके नेता ने किया, जिससे स्टेट एक्सचेकर पर 47 करोड़ रुपये का खर्च पड़ा। इन्होने बच्चों की नियुक्तियां की और उनको बहकाया, इसलिए इनको खुद को, इनकी पूरी पार्टी को उन अभिभावको से, हरियाणा के नौजवानों से और उन बच्चों से माफी मांगनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

तारांकित प्रश्न संख्या–49

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री उदयभान सदन मे उपास्थित नहीं थे।)

Cooperative Sugar Mill, Panniwala Mota

***4. Shri Karan Singh Dalal:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the year-wise total quantity of sugar produced by the Cooperative Sugar Mill, Panniwala Mota in district Sirsa, since its inception;

(b) the year-wise number of crushing days of the aforesaid Sugar Mill since its inception till to-date;

(c) the year-wise details of the sugarcane growing area of Sirsa district bonded to the Sugar Mill referred to in part (a) above since its inception ;

(d) the year-wise details of the income earned and expenditure incurred by the Sugar Mill referred to in part (a) above since its inception till to-date; and

(e) whether there is any proposal under consideration of the Government for closing the Sugar Mill as referred to in part (a) above ?

Chief Minister (Shri Bhupinder Singh Hooda): Statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) **Total** quantity of Sugar produced by the Coop. Sugar Mill Panniwala Mota in district Sirsa since inception of

the Mill is given as under:—

Year	Quantity of sugar produced in Qtls.
2001-02	83,694
2002-03	1,32,820
2003-04	47,780
2004-05	Ni
Total	2,64,294

(b) The year-wise crushing days of the mill till to-date are given as under:—

Year	Crushing days by Mill till date.
2001-02	66
2002-03	86
2003-04	40
2004-05	Nil
Total	192

(c) The year-wise details of the sugarcane growing area of Sirsa district bonded to the Sugar Mill Panniwala Mota since its inception given below:—

Year	Sugar cane growing area (in Acres)
2001-02	4,831
2002-03	16,372
2003-04	4,220
2004-05	342
2005-06	200
Total	25,965

(d) The year-wise details of income earned and expenditure incurred by the Sugar Mill Panniwala Mota since its inception till to date are given below:—

Year	Amount in Lacs Rs.	
	Income earned	Expenditure incurred
2001-02	1189.60	1245.62
2002-03	2862.14	3306.00
2003-04	2842.89	3465.55
2004-05	2128.13	2263.93
2005-06	591.92	659.66
(Upto 31-5-2005)		

Total	9614.68	10940.76

(e) Not yet, Sir.

श्री कर्ण सिह दलालः अध्यक्ष महोदय, जो जानकारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सदन के पटल पर रखी है उससे यह साफ प्रतीत होता हे कि यह जो पत्रीवाला मोटा, सिरसा में चीनी की मिल लगाई गई है उस मिल के लिए न गन्ना था और उस वक्त कृषि विभाग, जौ कि चीनी मिल लगाने के लिए अपनी राय देता है, के अधिकारियो ने साफ तौर पर कोओपरेटिव मिनिस्टर और मुख्यमंत्री महोदय को लिखकर कहा कि यह जगह चीनी मिल लगाने के लिए ठीक नहीं है क्योंकि उस एरिया मे गन्ना नहीं होता। उस वक्त जानबूझकर केवल अपने राजनीति के मुद्दे को ध्यान मे रखते हुए वहां मिल लगाई गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 2 –3 बातें पूछना चाहता हूं। पहला तो यह कि इस मिल पर कितना पैसा खर्च हुआ, दूसरा जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने सदन के पटल पर जानकारी दी कि वर्ष 2004– 2005 में चीनी की मिल में कोई पिराई नहीं हो रही तो कितने मुलाजिम इस मिल के अन्दर सरकारी खजाने से तनख्वाह ले रहे हैं ?

Mr. Speaker: Do not combine all those. You will get another opportunity. Do not connect all these questions.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, में आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि यह मिल 126 एकड जमीन पर है और इसकी कोस्ट आफ प्रोजैक्ट 46.71 करोड़ आई

है। जैसा कि कर्ण सिंह दलाल ने कहा और पहले सवाल भी उठा था कि पिछली सरकार ने ऐसे कई कार्य किए। उस सरकार में न केवल बच्चो के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया बल्कि हरियाणा के राजकीय कोष के साथ भी खिलवाड़ किया गया। इसलिए आज वह चीनी मिल 43 करोड़ रुपये का कुल घाटा अब तक दे चुकी है। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि जहां कहीं भी चीनी मिल लगाई जाती है वहां कम से कम साल मे 130 दिन गन्ना आना चाहिए, 160 दिन से कम तो बिलकुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन उस चीनी मिल मे कभी भी 66 दिन से ज्यादा गन्ना नहीं आया। 2003–04 मे तो केवल 40 दिन हीं गन्ना पिराई के लिए आया और वह भी बाहर से लाया गया था। अध्यक्ष महोदय, जहा तक कर्मचारियों का प्रश्न है, उस चीनी मिल में 312 कर्मचारी हैं जो इस समय अपने घर पर बैठे हुए हैं। सरकार ने फैसला लिया है कि उन कर्मचारियों को कहीं दूसरी चीनी मिलो में एडजैस्ट किया जायेगा और इस मिल को कोई प्राईवेट पार्टी लीज पर लेने के लिए तैयार होगी तो यह मिल लीज पर दे दी जायेगी।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, एक तो यह चीनी मिल कानून को ताक पर रखकर बिना जरूरत के लगायी गई जिससे सरकारी खजाने पर बहुत भारी बोझ पड़ा। कुल मिलाकर पिछली सरकार की इस तरह की करतूतों से हरियाणा की जनता पर 22.50 हजार करोड़ रुपये का कर्ज खड़ा हो गया। अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से यह चीनी मिल पिछली सरकार ने स्थापित

की, इसमें कर्मचारियो की भर्ती की जो घर बैठे तनख्वाह लेते रहे और जिससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ा तो क्या मुख्यमंत्री जी बतायेंगे कि क्या इसके लिए उस वक्त के दोषी कोओपरेटिव मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और जो अधिकारी इसमें शामिल थे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, This is not a part of the question लेकिन जहां तक इस मिल का सवाल है हमारे काबिल दोस्त बैठे हुए हैं अगर चौधरी देवी लाल ट्रस्ट इस मिल को लेने कै लिए तैयार है तो सरकार पाच करोड़ रुपये के घाटे तक कर्मचारियों सहित यह मिल उनको देने के लिए तैयार है।

श्री एस०एस० सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, पिछली सैप्लीमैंट्री के सवाल में मुख्यमंत्री जी ने बताया कि पिछली सरकार के मुख्यमंत्री ने स्टेट को बहुत सी जगहों पर चुना लगाया है। चाहे पन्नीवाला मोटा चीनी मिल का मामला हो, चाहे सिरसा यूनिवर्सिटी दमा मामला हो या कोई और मामला हो, हर जगह पिछली सरकार के मुख्यमंत्री ने हरियाणा की जनता को चुना लगाने का कार्य किया। मेरा प्रश्न यह है कि पिछली सरकार के मुख्यमंत्री ने अपने राजनैतिक स्वार्थ को साधने के लिए कानून को ताक पर रखकर गैर कानूनी तरीके से जो कार्य किये जिससे सरकारी खजाने पर और प्रदेश की जनता पर भारी बोझ पड़ा तो क्या हमारे मुख्यमंत्री महोदय उन सभी प्रकरणों की इन्क्वायरी

करवा ले जो भी दोषी है उनकी जायदाद से नुक्सान की रिकवरी कराने का कार्य करेगे ताकि भविष्य में कोई इस तरह का कार्य न करे?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मेरे भाई ये जो सवाल उठा रहे हैं इनका मे एक ही जवाब दे सकता हूं कि हाल न पूछो मेरे कारोबार का, इस अन्धी नगरी में आईना बेच रहा हूं।

Small Scale Industries

***10. Shri Dharam Pal Singh Malik:** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the names of places in urban and rural areas in the State separately where new Small Scale Industries were established during the year 2000 to 2005;

(b) the details of the Government financial assistance to the aforesaid industries ; and

(c) the number of industries out of those referred to in part (a) above are in working condition ?

श्री अध्यक्षः इस क्वैश्चन के बारे में मन्त्री जी की तरफ से टाईम एकस्टैंड करने के बारे मे रिक्वेस्ट आई है जो ग्रान्ट कर दिया गया है। लैटर इस प्रकार हैः–

Interim Reply

Lachhman Dass Arora Industries & Urban Development

Minister, Haryana, Chandigarh.

Dated 8-6-2005

Sub: Exemption of reply to Started Question No. 10.

Dear Bhai Sahab,

I would like to draw your kind attention to the Starred question No. 10 asked by the Hon'ble MLA, Sh. Dharam Pal Singh Malik regarding names of places in the urban and rural areas in the State, separately where new small scale industries were established during the year 2000-2005 alongwith details of financial assistance provided by the Government and the number of such industries which are now in working condition.

The information to this question is voluminous as more than 5000 SSI units were established in the urban and rural areas of the State in the last five years. To know how many of these are working at present, it needs a survey. Therefore, for giving comprehensive and correct reply, it is necessary to make collection of complete information which would require a survey to be conducte. Thus, at present it is not feasible to give proper reply to this question and atleast a period of six months is required to complete and compile this voluminous information. Under the circumstances, I request you to please grant exemption for giving reply to this question.

Yours sincerely,

(Lachhman Dass Arora)

Sh. Harmohinder Singh Chatha, Speaker,

Haryana Vidhan Sabha, Chandigarh.

Construction of Bus Stand in Narnaund City

***26.Shri Ram Kumar Gautam:—**Will the Minister for Transport be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct bus stand in Narnaund City, district Hisar ?

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Yes, Sir.

श्री राम कुमार गौतम: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि नारनौद में इस बस अड्डे की आधारशिला रखे हुए दस साल हो गये लेकिन आज तक भी इस का निर्माण नहीं हुआ है इसलिए मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह बस अड्डा कब तक बनकर तैयार हो जायेगा? समय सीमा के बारे में बताया जाये कि इसका काम कब शुरू किया जायेगा और कब तक यह बनकर तैयार हो जायेगा, वहां जगह भी मौजूद है?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथी को बताना चाहूगा कि इनसे पहले जो वहां से विधायक थे वे इनके पड़ोस में बैठी पार्टी से थे और उन्होने नारनौंद बस अड्डे का काम रूकवा दिया था। यह रिकार्ड की बात है। यह पहली बार नहीं हुआ, यह उनकी रिवायत का एक हिस्सा है। हमने इसकी

जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया था, उस कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है। हम जल्दी से जल्दी इसका निर्माण कार्य शुरू करवाकर अगले वर्ष के अंत तक इसका निर्माण कार्य पूर्ण करवा देंगे। सरकार की तरप? से इस बस अड्डे का ठेका देने की प्रक्रिया शुरू करवा दी हे।

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय परिवहन मन्त्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या कलायत में बस स्टैंड के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को यह बताना चाहूंगा कि कलायत मे बस स्टेंड बनाना मन्जूर कर लिया गया है और इसके कार्य को प्राथमिकता के आधार पर हम करवाएंगे और जल्दी ही यह बस स्टैंड बन कर तैयार हो जाएगा।

Setting up of a Medical College or Hospital

***22. Shri Naresh Yadav:** Will the Minister for Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a Medical College or Government Hospital on the pattern of All India Institute of Medical Sciences Delhi in district Mohindergarh?

स्वास्थ्य मन्त्री (बहिन करतार देवी): नहीं, श्रीमान् जी।

श्री नरेश यादवः अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मन्त्री महोदया से महेन्द्रगढ़ जिले में एक मेडीकल कॉलेज बनाने के बारे में सवाल पूछा था लेकिन मन्त्री महोदया ने केवल 'नो सर ' कह कर जवाब दे दिया। मैं माननीय मन्त्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यहां पर मेडिकल कालेज बनवाया जाएगा?

बहिन करतार देवीः अध्यक्ष महोदय, मैंने भिवानी मे मेडकल कालेज खोलने से संबंधित प्रश्न पर जवाब देते समय ही बता दिया था कि महेन्द्रगढ़ में कोई मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

श्री नरेश यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय हैल्थ मिनिस्टर महोदया को बताना चाहता हूं कि मन्त्री महोदया ने केवल 'नो सर' कह दिया। अध्यक्ष महोदय, हमारा पूरा दक्षिणी हरियाणा सैनिकों का इलाका है और हमारे काफी भाई फौज, पुलिस तथा फोर्सिज में काम करते हैं। वहां पर उनके बच्चे अकेले रहते हैं और इलाज के अभाव मे उन्हें बहुत मुश्किल होती है। हमारे यहां पर अगर किसी व्यक्ति का कोई एक्सिडेंट हो जाता है तो इलाज के अभाव में वे व्यक्ति दम तोड़ देते है। इसके साथ ही मै यह कहना चाहूंगा कि वहां पर मेडिकल कॉलेज तथा मेडिकल होस्पीटल की मांग वर्षा से चली आ रही है। हमारा इलाका सबसे ज्यादा दूर है। हमारे चारो तरफ राजस्थान का इलाका लगता है। दक्षिणी हरियाणा के बीच के क्षेत्र मे मेडिकल कॉलेज तथा मेडिकल होस्पीटल अगर बन जाए तो हमारे लोगों का बहुत ही भला होगा।

हमारे दक्षिणी हरियाणा के साथ–साथ उत्तरी–पूर्वी राजस्थान का ऐरिया भी कवर हो जायेगा। सारे अस्पतालों में मरीजो की भीड बहुत बढ़ गई है। हमारे ऐरिया के लोग मरीजों को जयपुर या रोहतक लेकर जाते हैं जो कि 150 किलोमीटर दूर पड़ते हैं। मैं माननीय हैल्थ मिनिस्टर साहिबा से यह जानना चाहता हूं कि वहां पर मेडीकल कॉलेज तथा मेडीकल होस्पीटल क्यो नहीं बन सकता है ? क्या वे वहां पर मेडीकल कॉलेज तथा मेडीकल होस्पीटल बनवाने का कष्ट करेगे (विघन) क्या इस मामले में सरकार की कोई कमी है या पैसे की कमी है ? (विघन)

Providing of Text Books

***60. Shri Sher Singh:** Will the Minister for Education be pleased to state:-

(a) whether the text books prescribed for April, 2004 under the Sarva ShikshaAbhiyan was being supplied upto February, 2005; if so, the action taken against the Agency who supplied the text books lately; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to provide the text books in time (April) in future ?

शिक्षा मंत्री (श्री फूलचंद मुलाना):

(क) मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हरि याणा द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत मुफ्त पाठ्य–पुस्तके अधिकतम

मुद्रित करके फरवरी, 2004 से जुलाई, 2004 तक सप्लाई की गई यद्यपि कुछ पुस्तको की सप्लाई बाद में जारी रही।

(ख) वर्तमान वर्षे के लिए मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग ने कक्षा 2 की एक पाठ्य–पुस्तक तथा कक्षा 4 की एक पाठ्य प्रस्तक जिसकी सप्लाई 15–7–05 से पहले होने की उम्मीद है को छोड़कर 5वीं कक्षा तक की सभी पुस्तको की सप्लाई कर दी है। छठी से आठवीं तक की आठवीं के लिए निजी पार्टियों से मुद्रण करवाने की निविदा अनुमोदित कर दी गई है तथा सप्लाई जुलाई 2005 की समाप्ति से पूर्व होने की उम्मीद है।

श्री अध्यक्षः अब क्वैश्चन आवर समाप्त होता है।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नो के लिखित उत्तर

Vacant Posts of Lineman, A.L.M., A.F.M. etc.

***40. Shri Somvir Singh:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that some posts of Lineman, A.L.M., A.F.M., A.S.S.A U.D.C. and S .D.O. are lying vacant in the Bhiwani Sub-Division; and

(b) If so, the time by which the aforesaid posts are likely to be filled up?

मुख्य मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा):

(क) हां श्रीमान एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(ख), कुछ रिक्तियों अन्य उप–मण्डलों के फालतू स्टाफ में से समजन करके भरी जाएंगी। बाकी स्टाफ की भर्ती के लिए कार्यवाही यथा समय की जाएगी।

विवरण

कार्यकारी अभियन्ता सिटी मण्डल भिवानी के अधीन 5 परिचालन उप–मण्डल हैं जिनमें से 3 उप–मण्डल जिनके नाम हैं सिटी उप–मण्डल भिवानी, सब–अर्बन नं० 1 भिवानी तथा सब–अर्बन नं०2 उप–मण्डल भिवानी, भिवानी शहर में स्थित है।

सिटी उप–मण्डल भिवानी तथा सब–अर्बन उप–मण्डल नं० 1 भिवानी, भिवानी शहर के शहरी क्षेत्र को बिजली की आपूर्ति करते हैं जबकि सब–अर्बन उप–मण्डल नं० 2 भिवानी सिटी के सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रो को बिजली की आपूर्ति करता है।

उप–मण्डल अनुसार खाली पदों की स्थिति निम्न प्रकार से है:–

पद	सिटी उप–मण्डल भिवानी	सब–अर्बन न ०1 उप–मण्डल, भिवानी	सब–अर्बन नं० 2 उप–मण्डल भिवानी

	एस	डब्लयू	रिक्त	फालतू	एस	डब्लयू	रिक्त	फालतू	एस	डब्लयू	रिक्त	फालतू
एल०एम०	11	23		12	12	27	-	15	30	29	1	
ए०एल०एम०	24	24	-	-	27	35		8	71	41	30	-
ए०एफ०एम०	5	6		1	5	7		2	7	1	6	-
ए०एस०एस०ए०	3	4	-	1	5	11		6	-	3	-	3
यू०डी०सी०	4	3	1		4	5		1	4	2	2	-
एस०डी०ओ०	1	1	-		1	1			1	-	1	-

'एस ' स्वीकृत पद दर्शाता है। 'डज्यू ' कार्यरत दर्शाता है।

Cases of Lootlng, Murder, Arson and Rape in the State

***37. Dr. Sita Ram:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the district wise number of incidents of looting, murder, arson and rape occurred in the State to-date since the formation of this Government; and

(b) the number of cases in which the offenders have been apprehended together with number of such cases which have not been solved so far ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): (के व (खा) वांछित सुथना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

(क) राज्य मे इस सरकार के गठन से अब तक लूट, हव्य, आगजनी एवं बलात्कार की घटनाओ की जिलावार संख्या।

जिला	लूट	हत्या	आगजनी	बलात्कार
पंचकूला	1	2	0	4
अम्बाला	6	5	1	5
यमुनानगर	2	8	3	5
कुरुक्षेत्र	6	5	2	7
कैथल	1	5	0	4
हिसार	11	5	3	4
सिरसा	8	4	2	5
भिवानी	9	16	3	2
जीन्द	8	9	2	2
फतेहाबाद	2	7	1	2
गुड़गावां	20	21	2	12
फरीदाबाद	8	15	3	12

नारनौल	4	2	1	8
रिवाड़ी	9	11	5	3
रोहतक	15	13	2	3
सोनीपत	7	18	2	4
करनाल	10	17	1	11
पानीपत	14	8	2	18
झज्जर	14	12	3	3
रेलवेज	5	2	0	0
कुल	**160**	**185**	**38**	**114**

(ख) उन मुकदमो की संख्या जिनमे दोषी पकडे गए व जो हल नहीं हुए।

जिला

मुकदमे जिनमें अपराधी पकड़े गए मुकदमे जो हल नहीं हुए

	लूट	हत्या	आगजनी	बलात्कार	लूट	हत्या	आगजनी	बलात्कार

पंचकूला	0	2	0	4	1	0	0	0
अम्बाला	6	5	0	4	0	0	1	1
यमुनानगर	1	5	3	5	1	3	0	0
कुरुक्षेत्र	5	5	1	6	1	0	1	1
कैथल	1	5	0	4	0	0	0	0
हिसार	9	5	2	4	2	0	1	0
सिरसा	6	4	0	5	2	0	2	0
भिवानी	9	11	2	2	0	5	1	0
जीन्द	3	9	2	2	5	0	0	0
फतेहाबाद	1	7	1	2	1	0	0	0
गुड़गावां	12	17	1	7	8	4	1	5
फरीदाबाद	5	13	3	10	3	2	0	2
नारनौल	3	2	1	5	1	0	0	3

रिवाड़ी	9	8	3	3	0	3	2	0
रोहतक	7	10	1	3	8	3	1	0
सोनीपत	4	14	0	4	3	4	2	0
करनाल	5	15	0	11	5	2	1	0
पानीपत	5	7	0	15	9	1	2	3
झज्जर	8	9	3	3	6	3	0	0
रेलवेज	3	1	0	0	2	1	0	0
कुल	**102**	**154**	**23**	**99**	**58**	**31**	**15**	**15**

Power Generating Capacity of Power Plant Mujeri

***50. Shri Udai Bhan** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the power generating capacity of the power plant set up by the NTPC in village Mujeri of district Faridabad;

(b) the total quantum of power being purchased by the Haryana Government; and

(c) whether the Haryana Government has made any correspondence with the Central Government or the management of NTPC for increasing the capacity of the said plant; if so, the details thereof?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा):

(क) जिला फरीदाबाद के मुजेड़ी गांव मे एन०टी०पी०सी० द्वारा स्थापित पावर प्लान्ट की बिजली उत्पादन क्षमता 432 मैगावाट है।

(ख) इस प्लान्ट द्वारा उत्पादित शतप्रतिशत बिजली हरियाणा राज्य द्वारा खरीदी तथा प्रयोग मे लाई जाती है।

(ग) इस प्लान्ट की निश्चित क्षमता 432 मैगावाट की है। इस परियोजना की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस मामले को भारत सरकार के साथ लिया जा रहा है।

वर्ष 2005–2006 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा

Mr. Speaker: Hon'ble Members, Now, discussion on Budget Estimates will start.

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान (बेरी): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मेरा खायंट आफ आर्डर हे। एक बहुत ही आपत्तिजनक बात मैं उठाना चाहता हूं। यह ठीक है कि we can not take any action against him क्योकि वे आर०एस०एस० के चीफ हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं उनके बारे में सब जानते हैं। उन्होंने एक बहुत ही गलत

बयान दिया है कि politics is like prostitution. उन्होंने हमारे डैमोक्रेटिक सैटअप पर अटैक किया है। इससे ज्यादा गलत बात कुछ और नहीं हो सकती है। उन्हौंने सारे डैमोक्रेटिक सैटअप पर और हमारे सारे इन्स्टीच्यूशन पर अटैक किया है। मैं यह चाहता था कि यह सब रिकार्ड में आए और इस किस्म की बात जो उनके द्वारा दी गई है वह बहुत ही आपत्तिजनक और चिन्ताजनक बात है। उन द्वारा ऐसी गलत बाते न की जाएं जिससे हमारा सारा ढांचा हिलता हो। यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

डॉ० सुशील इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्यायंट आफ आर्डर है। सुबह जब मुख्यमंत्री महोदय शोक प्रस्ताव लेकर आए थे तो उसी विषय में मैंने एक कालिंग अटैशन मोशन दिया हुआ है। वहां पर जो नुक्सान हुआ था उस बारे मे मैंने आपके पास एक कालिंग अटैंशन मोशन दिया है। मैं उस बारे में आपकी रूलिंग चाहता हूं।

Mr. Speaker: You have received the reply. Now I will not allow you.

डॉ० सुशील इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बारे में स्टेटमैंट देने को तैयार है?

Mr. Speaker: You have received the reply.

उद्योग मन्त्री (श्री लक्षमण दास अरोडा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि सी०एम० साहब खुद

वहां पर जाकर आए हैं क्या आज से पहले ऐसा कभी हुआ है ? वहां पर मरने वालों के परिवारों को वित्तीय सहायता भी दी गई है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Mr. Indora, continuing talking like this is not going to favour you.

डॉ० सुशील इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बारे मे स्टेटमैंट देने को तैयार है? (शोर एवं विघ्न)

Mr. Speaker: Everybody to take seat. Discussion on Budget has already taken place. R.S. Kadian, you may continue your speech.

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान: स्पीकर साहब, इस महीने की 9 तारीख को वित्तमंत्री श्री बीरेन्द्र सिंह जी ने वर्ष 2005–06 के लिए जो बजट पेश किया उस पर डिस्कशन के लिए सर्वप्रथम मुझे बोलने के लिए समय दिया है इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले वित्तमंत्री जी का और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियो को मुबारिकबाद देना चाहता हूं कि उनको इन बजट अनुमानों को तैयार करने के लिए बहुत भारी मशक्कत करनी पड़ी। उन्होने बजट की अच्छी बातों को और छोटी मोटी कमियों को बहुत ही बोल्डली तरीके से दर्शाया है। स्पीकर सर, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पहले जब कभी भी बजट पेश होता था तो डिस्कशन

के लिए 12– 14 घंटे से ज्यादा का समय नहीं दिया जाता था। उस वक्त हर मैम्बर की रिक्वैस्ट आती थी कि बजट की डिस्कशन पर और समय दिया जाना चाहिए। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।) उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी आनरेबल मैम्बर को इतनी महारत हासिल नहीं है कि वह एक दिन में ही बजट पर डिस्कशन में भाग ले सके। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि बजट पर होने वाली डिस्कशन के लिए अध्यक्ष महोदय ने 4 दिन का समय दिया है और इसके लिए अध्यक्ष महोदय बधाई के पात्र हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। किसी भी सरकार का बजट उस सरकार का आईना होता हे। इस बजट के पढ़ने से यह साफ तौर पर जाहिर होता है कि सरकार एक सही दिशा में काम करने के लिए तत्पर है।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नोटिस में लाना चाहता हूं कि हमारा विपक्ष सदन में बजट पर हो रही डिस्कशन के प्रति कितना गम्भीर है क्योकि बजट पर डिस्कशन के लिए तीन–तीन दिन रखे गए हैं और विपक्ष सदन से अभी से गायब है।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान: उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार इस प्रदेश को ठीक दिशा में ले जाएगी जहां न भय होगा, न भूख होगी, न भ्रष्टाचार होगा, न भेदभाव होगा ओर पूरा प्रदेश चहुमुखी विकास की दिशा मे आगे बढ़ेगा। डिप्टी स्पीकर सर, किसी बजट की फाउंडेशन या उसकी आधारशिला का उसकी

रिसीटस से पता चलता है। वर्ष 2004–03 के बजट मे रेवैन्यू रिसीटस 11388 करोड़ रुपये थीं जिनमें अब 649 करोड़ रुपये की और बढ़ोत्तरी हो गयी है और अब ये 12037 करोड़ रुपये तक चली गयी हैं। कैपीटल रिसीटस मे भी 1427 करोड़ रुपये की जबदस्त बढ़ोत्तरी हो गयी है क्योंकि वर्ष 2005–06 के लिए 1082 करोड़ रुपये बढ़ाकर 2509 करोड़ रुपये बजट ऐस्टीमेटस मे किए गए हैं। जहां तक टोटल रिसीटस का मामला है वर्ष 2004– 05 में पिछले वर्ष के बजट मे 12470 करोड़ रुपये की टोटल रिसीटस थी और 2005–06 में इन रिसीटस मे 2077 करोड़ रुपये की इंक्रीज हुई है यानी अब यह 14547 करोड़ रुपये तक हो गयी हैं। डिप्टी स्पीकर सर, इस तरह से टोटल पैसा जो आया है उसमें भी रूपी अकाउंट में साफ नजर आ रहा है कि टोटल बजट का 34.04 परसैंट पैसा सेल्स टैक्स के माध्यम से, रिकवरी के माध्यम से और टैक्स कम्पलायन्स को मजबूत करने के माध्यम से आता हुआ दिखाई दिया है जबकि वर्ष 2004–05 में यह सिर्फ 25 परसैंट था। इसका मतलब पुरानी सरकारो की जो नीयत टैक्स कम्पलायन्स के प्रति थी वह साफ झलकती है। डिप्टी स्पीकर रनर, रुपी कम्म मे ही 2004 – 05 के बजट मे 39 परसैंट भरपायी की गयी थी लेकिन इस बार पब्लिक डैब्टस मे सिर्फ 24. 16 परसैंट जो पैसा है वह आता हुआ दिखाई दिया है। यह साफ दर्शाता है कि सरकार की नीयत इस बजट को कर्जो के माध्यम से पूरा करने की नहीं है बल्कि अपने साधनो से पूरा करने की है। डिप्टी स्पीकर सर, जो मेजर ऐलोकेशंज कसोलिडेटेड फंडज की हैं उसमें इरीगेशन हैड

के अंदर जहां 2००4– 05 मे 749 करोड़ रुपये रिवाइज्ड ऐस्टीमेटस के लिए खर्च हुए वहीं 2005–06 के प्रपोज्ड बजट मे 173 करोड़ रुपये ओर बढ़ाकर 922. 68 करोड़ रुपये कर दिए गए। यह 23 परसैंट की बढ़त है। पावर सैक्टर की तरफ अगर हम देखते हैं तो वर्ष 2004–05 का जो बजट था उसमे 1487 करोड़ रुपये रिवाइज्ड ऐस्टीमेटस में खर्च हुए जबकि इस बार के बजट ऐस्टीमेटस मे 221 करोड़ रुपये बढ़ाकर ये 1703 करोड़ रुपये तक ले गए। इस तरह से पावर सैक्टर में पिछले वर्ष के मुकाबले मे 15 प्रतिशत की इंक्रीज है। एजुकेशन में 1647 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2160 करोड़ रुपये किये गये हें। यह 16 प्रतिशत की बढ़त है। हैल्थ और फैमिली वैलफेयर में 393 करोड़ रुपये नै बढ़ाकर 466 करोड़ रुपये किये गये यानी इसमे 75 करोड रुपये पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल के प्रपोज्ड बजट मे बढ़ाए गए। इस तरह से यह 19 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी है। सोशल वैलफेयर मे 609 करोड़ रुपये में 128 करोड़ रुपये की और बढ़त करके 737 करोड़ रुपये बजट ऐस्टीमेटस में रखे गए। यह 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। ऐग्रीकल्वरल और एलाइड सर्विसेज मे 475 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 558 करोड़ रुपये किये गये। यह 18 परसैंट की बढ़त ऐग्रीकल्चर सैक्टर मे दिखाई दी जोकि बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनी तरह से पब्लिक वर्क्स डिपार्टमैंट के लिए 2004–05 में 442 करोड़ रुपये रखे गए थे जिसे इस साल 2005–06 मे 194 करोड़ रुपये बढ़ाकर 636 करोड़ रुपये कर दिया गया है यह व– प्रतिशत की इन्क्रीज की गई है। रूरल डिवैल्पमैंट प्रोग्राम मे 152 करोड़ रुपये

2004–05 में रखे थे जिसे 125 करोड़ रुपये बढ़ाकर शा करोड रुपये किया गया है यह 82 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी है। यह सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस तरह से सभी हैड्स मे कहीं 25 प्रतिशत, कहीं 44 प्रतिशत तो कहीं 82 प्रतिशत की इन्क्रीज है। उपाध्यक्ष महोदय, बजट की वार्षिक योजना का आकार उस प्रदेश के विकास की गति का आईना होता है। बजट अनुमानों से साफ दिखाई दे रहा है कि वार्षिक योजना तैयार करते समय विकास की गति को तेज करने और समाज के सभी वर्गों के उत्थान का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2004–05 की 2236 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना के स्थान पर इस वर्ष 3000 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना रखी गई है जो कि 34 प्रतिशत अधिक है। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। जहां तक वार्षिक योजना में डिफरैंट हैड में एलोकेशन का सवाल है, ऐग्रीकल्चर हेड में 2004–05 मे 117 करोड़ रुपया रखा गया था जबकि प्रपोज्ड आउटले में 2005–06 में 30 प्रतिशत पैसा पिछले वर्ष से ज्यादा रखा गया है। रूरल डिवैल्पमैंट के लिए 2004–06 में जहां 100 करोड़ रुपये का रिवाइज्ड आउट ले था उसके मुकाबले वर्ष 2005–06 में 70 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी करके उसे 170 करोड़ रुपये किया गया है। इरीगेशन और फ्लड कंट्रोल हैड के लिए वर्ष 2004–05 मे 298 करोड़ रुपये रखे गये थे जिन्हें इस साल 2006–06 मे 65 करोड़ रुपये बढ़ाकर 363 करोड़ रुपये का किया गया है जो कि 32 फीसदी इंक्रीज है। पावर सैक्टर मे जहां 330 करोड़ रुपये 2004–05 के रिवाइज्ड आउट ले मे रखे गए थे वहीं वर्ष 2005–06

मे इसमे 65 करोड रुपये की बढ़ोत्तरी करके 445 करोड़ रुपये रखे गए हैं जो कि 16 प्रतिशत ज्यादा है। ट्रांसपोर्ट के हैड मे वर्ष 2004–05 मे रिवाइज्ड आउटले 251 करोड़ रुपये रखे गए थे लेकिन इस वर्ष 2005–06 में 93 करोड़ रुपये बढ़ाकर 344 करोड़ रुपये इस साल के लिए रखे गए जो कि 375 परसैंट की बढोत्तरी है। उपाध्यक्ष महोदय, सोशल सर्विसिज में जनरल ऐजुकेशन, हैल्थ, टैक्नीकल ऐजुकेशन सैक्टर्ज आते हैं। इनमे वर्ष 2004–06 में रिवाइज्ड आउटले 977 करोड़ रुपये खर्च हुआ था जबकि वर्ष 2005–060मे इनमे 375 करोड़ रुपये बढ़ाकर 1352 करोड़ रुपये तक ले गए हैं, यह 364 परसैंट की इन्क्रीज है जो कि एक उपलब्धि है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर टोटल बजट अनुमानों का मूल्यांकन किया जाए तो आप पाएंगे कि कर्जे से नहीं बल्कि अपने साधनो से विकास करने की सरकार की नीयत झलकती है। इससे यह दर्शाता है कि हरियाणा की वर्तमान सरकार बुनियादी ढांचे में सुधार करने और संतुलित विकास करने की ओर अग्रसर होगी। हरियाणा सरकार द्वारा लिये गये अहम, फैसले इस बात को सिद्ध करते हें कि वर्तमान सरकार लोगों की आशाओं और आकाक्षाओ पर खरा उतरेगी। अपने 100 दिन के टाईम में जिस ढंग से इस सरकार द्वारा फैसले लिये गये हें उसमे सरकार की उपलब्धियो का एक शीशा नजर आता है पिछले 100 दिनों में वर्तमान सरकार की कुछ मुख्य उपलब्धियां हैं मैं सदन की जानकारी के लिए आपके माध्यम से उनके बारे मैं बताना चाहता हू। वैसे तो हर आदमी इन उपलब्धियों के बारे मे अखबारों और दूसरे माध्यमों द्वारा जानता

ही है। सदन के पटल पर भी ये उपलब्धियौ रखी गई हैं। लेकिन जिस ढंग से पिछली सरकार किसानों की हितैषी बनने का ढिंढोरा पीटती थी और ढंग से उसने किसानों के खिलाफ राजद्रोह के मुकदमे दर्ज किये तथा किसानों को बदनाम करने के लिए सरकार की तरफ से निर्णय लिये गये, यह कोई छोटी बात नहीं थी बल्कि यह एक बहुत बडी बात है। हमारी सरकार ने किसानों को राहत देने की जो बात की है। यह तो उनके जख्मों पर मरहम लगाने की बात है। हमने उनके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की और किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनके खिलाफ दर्ज सारे मुकदमें प्राथमिकता के तौर पर वापस लेने का फैसला किया। हरियाणा में मुआवजा देने के नाम पर गेहूं की फसल पर 50 रुपये और अन्य फसलों पर 25 रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है। गेहूं को 640 रुपये प्रति क्यिंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिसाब से खरीदा गया है। इसी प्रकार से सरसों को 1700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। इस प्रकार से अब सरसों की 2.90 मीट्रिक टन की खरीद की जायेगी जोकि अब तक की सर्वाधिक खरीद होगी। इसी तरह से फसल के लिए लेने वाले सरकारी ऋण पर ब्याज दर कम की गई, ट्रैक्टर की लाईसैंस फीस खत्म कर दी गई है। तथा अब खाद और जिप्सम पर भी कोई कर नहीं लगेगा। दूसरे करों में भी कोई वृद्धि नहीं की गई है। यह अब 12 प्रतिशत रहेगा। ट्रैक्टर के पुर्जो पर कर और भूमि उपकरण के लिए भूमि निर्धारण फार्म बनाया गया है उससे किसानो के एक बड़े वर्ग को फायदा होगा

जैसे गुड़गांव मे विकास योजना और शहरी किसानों के भूमि अधिग्रहण मे 15 लाख रुपये प्रति एकड़ भूमि का भाव निर्धारित किया गया है। एन०सी०आर० और हरियाणा के बड़े शहरो पंचकुला और चण्डीगढ़ मे 12. 5 लाख रुपये प्रति एकड़ का भाव रखा गया है और अन्य जमीन का 5 लाख रुपये प्रति एकड़ का भाव रखा गया है। कर्मचारियों को उन्नति और तकनीकी जानकारी देने के लिए हरियाणा मे पंचकुला में प्रशिक्षण कम्पनी की स्थापना की गई है। नहरी पानी के बटवारे के लिए समान वितरण प्रणाली के तहत नहरी पानी सभी क्षेत्रो मे उपलब्ध करवाया जायेगा। इस योजना के अन्दर लिफ्ट कैनाल सिस्टम और भाखड़ा मेन लाईन और हांसी ब्रान्च लिंक नहर का निर्माण करने की एक लिंक नहर योजना विचाराधीन हैं इस पर लगभग 250 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसी प्रकार सं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, 2, 8 व 10 को जोड़ने के लिए 135 किलोमीटर लम्बा वेस्टर्न पैरीफेरी एक्सप्रैस हाईवे बनाने की प्रक्रिया हरियाणा सरकार ने शुरू की है। इस एक्सप्रैस हाईवे के बनने से हरियाणा प्रदेश का चहुंमुखी विकास होगा। दिल्ली मैट्रो को गुड़गांव तक बढ़ाने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। प्रदेश में औद्योगिक निवेश का माहौल प्रदान करने के लिए नई औद्योगिक नीति लागू की गई है। जिसने एक उद्योग विकास के प्रति रास्ता हरियाणा में खोलने का काम किया है। जिससे लाखों लोगो को रोजगार मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय हम किसानो को हर कीमत पर बिजली उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध हैं। बिजली निगम धान की फसल लगाने के लिए

बिजली के व्यापक प्रबन्ध कर रहा है। सामान्य वर्षा की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र को कम से कम छ घण्टे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। हरियाणा सरकार की जो पौलिसियां हैं, सरकार ने जो फैसले लिए हैं, सरकार की जो उपलब्धियां हैं वह बहुत अच्छी हैं। अब बिजली के बकाया बिलों की समस्या का समाधान भी निकाला जाएगा। इसका समाधान सुझाने के लिए तथा बिजली क्षेत्र में अतिरिक्त वित्तीय संसाधन तलाशने के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियो की 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य सेवाओं मे सुधार अभियान हरियाणा सरकार की तरफ से चलाया गया है जिसमे हरियाणा प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओ का लाभ मिलेगा। परिवहन में यात्रियों की सुविधाओं के लिए बस स्टैंडों का आधुनिकीकरण करना तथा उनमें उपलब्ध जन सुविधाओ में सुधार की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षकों की भर्ती मे महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण करने ता निर्णय भी लिया गया है। इस तरह से शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता को भी चरणबद्ध ढंग से बढाया जाएगा। जे०बी०टी० शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता 10+2 की जगह बी०ए० या बी०एस०सी० कर पौ गई है। शिक्षा में श्रेष्ठता के लिए 'राजीव गांधी छात्रवृति' नाम की नई योजना शुरू की गई ताकि प्रतिभावान छात्रो को सरकारी स्कूलों की ओर आकर्षित किया जा सके। इस स्कीम के तहत स्कूलो के 50 हजार प्रतिभाशाली छात्रो को पुरस्कृत किया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, युवाओ को उच्च कोटि की शिक्षा देने के लिए राज्य में

ओक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी की पद्धति पर 'राजीव गांधी एजुकेशन सिटी' स्थापित की जाएगी। इसमे हरियाणावासियों के लिए 25 प्रतिशत सीटे आरक्षित होंगी। शैक्षणिक वर्ष 2005 –2006 से राजकीय महाविद्यालयों में जोब ओरियटिड नए पाठयक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, आबकारी नीति को पारदर्शी बनाकर अब ठेको की नीलामी खुली नीलामी से की गई है। हरियाणा सरकार इस बात के लिए बधाई की पात्र है। इसका परिणाम यह रहा कि ठेकों की नीलामी के इस वर्ष प्रदेश को पिछले साल की तुलना में 120 करोड़ श्य लाख रुपये ज्यादा राजस्व प्राप्त हुआ है। राजस्व मे यह वृद्धि 16.75 प्रतिशत हैं। इसी तरह से व्यापारियों को भी सुविधाए दी गई हैं। हरियाणा सरकार ने वैट प्रणाली को जनता, व्यापारी वर्ग और उद्योगपतियो के लिए सरल व तर्कसंगत बनाने का प्रयास किया है। जनहित को ध्यान में रखते हुए दवाईयो पर कर की दर 10 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दी गई है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बेचा जाने वाला मिट्टी का तेल, एवं तारकोल, कागज, खेलों का सामान, लैण्ड लाइन टेलीफोन, सिलाई मशीन ओर पत्थर की खुरदरी स्लैब पर पहले जो कर 10 से 12 प्रतिशत था, उसे घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है। हलवाईयो से लिया जाने वाला एकमुश्त भट्टी कर भी समाप्त कर दिया गया हे 1 इस प्रकार से अब जिन हलवाईयों की वार्षिक आय 5 लाख से कम है, उनसे कोई कर नहीं लिया जाएगा। इस तरह से उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने समाज कल्याण की तरफ भी एक साहसी कदम

उठाया है इससे सरकार की हमदर्दी कमजोर वर्गो की तरफ दिखाई देती है। दृष्टिहीन विएकलांग व्यक्ति जो केनर के पद पर कार्य कर रहे है, उन्हे दी जाने वाली राशि 1500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये मासिक कर दी गई है। दृष्टिहीन मानसिक रूप से विकलांग ओर बधिर विकलागो ओर शारीरिक रूप से विकलांगो को दी जाने वाली मासिक पैंशन 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये कर दी गई है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जातियों के परिवारों की लड़कियो के विवाह पर दी जाने वाली राशि 5100 रुपये की बजाय 15000 रुपये देने की एक योजना शुरू की गई है। जिसे 'इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन ' योजना कहा जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार प्रदेश में घटते लिंग अनुपात के प्रति भी चिन्तित है और इसके लिए भी बहुत सी स्कीमें हरियाणा सरकार ने बनाई हैं। हमारे मुख्यमंत्री महोदय भी खुद एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं इसलिए स्वतंत्रता सेनानियो और सैनिको को सुविधा देने के लिए सरकार ने स्वतत्रता सेनानियों की पैंशन 1400 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये प्रति माह कर दी है। सैनिको व भूतपूर्व सैनिकों द्वारा सी.एस.डी. से खरीदी जाने वाली वस्तुओं को कर से मुक्त रखा गया है। भूतपूर्व सेनिकों को आबकारी कर मे 25 प्रतिशत की छूट दी गइ है। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने अर्ध सैनिक बलों के सभी रैंको को सेना के रैंको के बराबर अनुग्रह अनुदान देने का निर्णय लिया हे। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को भी बहुत सी सविधाए दी हैं। हमारी सरकार ने कर्मचारियो को अपनी लडकी

और बहन की शादी के लिए मिलने वाले 30,000 रुपये के लोग को बढाकर एक लाख रुपये तक किया है और लड़के की शादी के लिए मिलने वाले 20 हजार रुपये के लोन को बढ़ाकर 60 हजार रुपये किया है। यह सुविधा अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के साथ–साथ द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी भी ले सकेंगे। इसका भुगतान अब 70 किस्तों की बजाय 100 मासिक किस्तो में होगा। हमारी सरकार ने कर्मचारियों की भलाई के लिए चिकित्सा खर्च प्रतिपूर्ति की एक अनूठी योजना भी लाग्रु की है। इसके अलावा 1 अप्रैल, 2005 से आगनवाडी के कार्यकर्ताओ का मानदेय 200 रुपये और आगनवाड़ी हैल्परों का मानदेय 100 रूपये प्रति मास बढ़ाया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह हरियाणा सरकार की वार्षिक योजना और नीतियां यह दर्शाती हैं कि हरियाणा की वर्तमान सरकार बुनियादी ढांचे को सुधारने के साथ–साथ स्वच्छ और कल्याणकारी शासन की तरफ अग्रसर है। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार द्वारा लाग अहम फैसले इस बात को सिद्ध करते हैं कि वर्तमान सरकार लोगो की आशाओं और आकाक्षाओ पर खरी उतरेगी। उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार का यह पहला बजट हे इसलिए पिछली सरकार की वार्षिक योजनाओ का यहां जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मेरी दिली इच्छा थी कि अगर आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और रोड़ी हल्के के विधायक भी इस अवसर पर सदन मे उपस्थित रहते तो वे स्वयं महसूस करते कि वे अपने आपको किस आधार पर किसान का बेटा होने का दावा करते थे और अपने दफे किस

आधार पर किसान हितैषी कहते थे? क्योंकि उनकी सरकार के समय मे जन विरोधी और किसान की कमर तोड़ने वाली वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थीं। मैं भगवान से' प्रार्थना करता हूं कि वे उनको अतिशीघ्र स्वास्थ्य लाभ देकर लम्बी उस दे ताकि वे खुद देख सके कि सही मायने में किसान हितैषी कौन है? उपाध्यक्ष महोदय, उनकी पांच साल तक सरकार रही, मैं उनकी सरकार के समय की पांच साल की वार्षिक योजनाओं का जिक्र करूगा। क्योंकि हमारी सरकार का यह पहला बजट है। इसलिए उनकी सरकार के समय की वार्षिक योजनाओं का जिक्र करना बहुत जरूरी है। हमे पिछली सरकार से जो व्यवस्था मिली है, जो ढांचा मिला है उसकी जानकारी उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को देना चाहूंगा। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) अध्यक्ष महोदय, 2000–01 में वार्षिक योजना का आकार 1315 करोड़ रुपये था लेकिन 2001 –02 मे 1.5 प्रतिशत बढ़ाकर 1638 करोड़ रुपये पिछली सरकार ने किया। उसके बाद 2002–03 में वार्षिक योजना का आकार 2.1 प्रतिशत कम करके 1600 करोड़ रुपये रखा गया। अध्यक्ष महोदय, वार्षिक योजना का आकार इससे पहले हमारे देश मे किसी भी राज्य मे नहीं घटाया गया। लेकिन पिछली सरकार के समय हमारे राज्य में यह कम किया गया। उसके बाद 2003–04 में 2.7 प्रतिशत बढ़ौत्तरी करके वार्षिक योजना का आकार 1850 करोड़ रुपये रखा गया और 2004 –05 में 20.8 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करके यह 2236 करोड़ रुपये रखा गया। अध्यक्ष महोदय, यदि पिछले पांच सोल की वार्षिक योजनाओ

का टोटल इन्क्रीज देखा जाये तो यह कुल 233 प्रतिशत ही है जबकि वर्तमान सरकार की वर्ष 2005–06 की वार्षिक योजना की एस्टीमेटिड इन्क्रीज ही न प्रतिशत है जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए हरियाणा सरकार और वित्तमंत्री चौधरी वीरेन्द्रसिंह जी बधाई के पात्र है। स्पीकर सर, समय के साथ–साथ प्रदेश मे पोपुलेशन भी बढ़ती रही है, इन्फलेशन भी बदता रहा है और कीमतें भी घटती बढती रही हैं। अगर इस फैक्टर को ध्यान मे रखते हुए वर्ष 2004–05 की वार्षिक योजना को देखा जाए तो यह 2236 करोड़ रुपये की थी और यदि उसकी एक्चुअल वैन्यू वर्ष 2000–2001 की वार्षिक योजना के 1815 करोड़ रुपये के मुकाबले मे आंकी जाए तो वर्ष 2004–05 की वार्षिक योजना भी बढ़ी हुई नहीं है बल्कि घटी हुई ही नजर आएगी। स्पीकर सर, पिछली सरकार अपने पांच साल के कार्यकाल के दौरान वार्षिक योजना के आकार को बढ़ा नहीं पाई जबकि कर्ज का बोझ 12 हजार करोड़ से 28 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया, रेवैन्यू एक्सपैंडिचर आठ हजार करोड़ रुपये से 13 हजार करोड़ रुपये हो गया, फिस्कल डैफिशिट कण्ट्रोल से बाहर चला गया, Debt of the State on an average has increased faster than the rate of GDP. Total outstanding arrear of revenue बढ़ता चला गया, टैक्स की कम्पलांयस सैटिस्फैक्टरी नहीं हुई, पिछली सरकार ने सारा टैक्स एकत्रित करने की बजाए अपने समर्थको के माध्यम से अपनी जेबें भरने का काम किया गया।

Mr. Speaker: Dr. Sahib, Please wind up.

डा० रघुवीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, यह पिछले पांच साल के फाईनैंस का ऐनालिसिज हरियाणा प्रदेश केलिए काले अध्याय 'है समान है। उस समय प्रदेश में चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी। प्रदेश में गलत कामो का बोलबाला था। अपहरण, डकैती और बलात्कार का बोलबाला था, भेदभाव की राजनीति से पूरा प्रदेश ग्रसित था और उस समय की सरकार की दमनकारी नीतियों की वजह से हरियाणा प्रदेश का हर नागरिक भय के वातावरण मे जीने के लिए मजबूर था वहीं दूसरी तरफ अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए पूरे प्रदेश में वील राईटिंग, कट–आउट्स और रोड होर्डिंग्ज लगा कर सरकारी खजाने का करोड़ो रुपया बर्बाद करने का काम हुआ था स्पीकर साहब, अगर में चौटाला साहब के पांच वर्षों के सारे कारनामों की चर्चा करूं तो शायद किसी और माननीय साथी को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। मेहम काण्ड बहुत ही चर्चित काण्ड था। मैं इस बात को इस लिए कह रहा हूं क्योंकि चौटाला साहब ने चंगेज खां के अन्दाज में सद्दाम हुसैन के नजरिये से हरियाणा प्रदेश के साथ खिलवाड़ किया। मेहम काण्ड के दौरान चौटाला साहब के जुमले आज भी लोगों के होठों पर कायम हैं। चौटाला साहब कहा करते थे, 'मैं तो भगवान से भी नहीं डरता', 'शमशान तक दोस्ती निभाता हूं'। चौटाला साहब यह बात बड़े गर्व से कहते थे कि 'उस इन्सान का क्या जीना जिसके भय से डर कर लोग नींद से न उठ जाएं', जिसके भय से डर कर चारपाई पर न उछलने लगें। (विघन) उन दिनों वे इस प्रकार की बाते आम कहा करते थे।

स्पीकर सर, मेहम काण्ड के प्यांयट को मैं टच करना चाहता हूं। उस चुनाव में आजाद उम्मीदवार अमीर सिंह की हत्या की गई। उसकी जांच के लिए केन्द्र सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति के०एन० सैकिया आयोग की जांच रिपोर्ट का मै जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा है कि needle of suspicion, points towards men and circumstances around Chief Minister Shri Om Parkash Chautala.

अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश चौटाला के शासनकाल मे जिस तरह से निर्दोष और शान्तिप्रिय लोगो पर गोलियों की बौछार हुई थी मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा 30 जनवरी, 2002 में छोटी–मोटी बातो को लेकर किसानों और सरकार के बीच समझौता हुआ था और उस समझौते को लागू करवाने के लिए 19 मई, 2002 को कण्डेला में एक पंचायत बुलाई गई थी। उस पंचायत में जब कैथल की तरफ से किसान शिरकत करने के लिए आ रहे थे तो शिमला गांव के किसान ' राम सरूप की नगरा गांव के अन्दर गोली मार कर हत्या कर दी गई। स्पीकर सर, उसकी पोस्ट मटिम रिपोर्ट को बदला गया और जब पोस्ट मटिम रिपोर्ट बदली गई तो आन्दोलन की लपटें गुलकनी और शाहपुर गावो तक चली गई। 29 मई को एक किसान राजबीर की हत्या हुई और 31 मई को फिर 6 किसानों को भोत के घाट उतार दिया गया। स्पीकर सर, उस समय जिस ढंग का वातावरण था मैं उसको व्यान कर रहा हूं। आज सब लोग यह अन्दाजा लगाए कि धरती आसमान मिलते हैं जब एक बूढ़े बाप के बेटे की लाश उसके घर से

निकलती है या जब एक जवान बहन जिसने अपने खान्विद के शरीर को भी नहीं देखा था, उसके खान्विद की लाश उसके आगन से उठी थी। स्पीकर सर, 6 किसानों की मौत हुई। कहीं उनकी पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट न बदल जाए इसलिए लोग उन शवो को पोस्ट मार्टम के लिए मैडिकल कॉलेज, रोहतक ले गए थे। स्पीकर सर, भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को उनका टेलीफोन गया। जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो बहुत दर्दनाक और मार्मिक सीन वहां पर था। सैकड़ों किसान वहां पर खड़े थे। 80–60 साल के बूढ़े लोगो की सफेद मूंछो में से आसू जा रहे थे। जब भूपेन्द्र सिंह जी अपने साथियो के साथ वहां पर जा कर गाड़ी से उतरे तो गुलकणी और शाहपुर गांवो के सरपंच रामदीया और टेकराम ने हुड्डा साहब को जफ्फी मे भर लिया और खाता मे लेकर दहाड़ मार कर रोने लगे और कहने लगे कि लूट लिया ओम प्रकाश चौटाला ने। स्पीकर सर, 6 किसानो की लाशों पर कफन ढके हुए थे। उस समय हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि ऐ किसान मैं तेरी लड़ाई लडूंगा, चौटाला की फैक्टरी में कोई ऐसी गोली नहीं बनी है जो किसान की छाती में लगेगी, अगर कोई गोली बनी है तो वह गोली भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और उनके साथियों की छाती मे लगेगी। स्पीकर सर, उसके बाद एक आन्दोलन शुरू हुआ। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी और चौधरी जय प्रकाश जी वहां पर आए थे। स्पीकर सर, वहां पर आनन्द सिंह डागी और शादी लाल बत्रा भी थे। इन्होने जींद मे पहुंचकर आन्दोलन शुरू किया तथा शहीद हुए किसानो के आश्रितो को

कांग्रेस पार्टी की तरफ से 1 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। उसके बाद भी जब चौटाला की जालिम सरकार नहीं झुकी तो 9 जून से 21 जून तक चिलचिलाती धूप में दिल्ली तक की पद यात्रा करने का फैसला लिया गया। जब पद यात्रा चरम सीमा पर थी तो 19 जून को सरकार समर्थको के बीच में एक समझौता हुआ ताकि 21 जून की रैली में लोग दिल्ली न पहुचे। स्पीकर सर, कितनी खेदजनक बात है कि उस समय एक आला आफिसर जेलों में बंद भारतीय किसान यूनियन के नेताओं को निकाल कर दिल्ली मे चौटाला की कोठी पर ले गया और उन पर समझौता करने के लिए दबाव डाला गया लेकिन उन नेताओं ने अपनी पार्टी के साथियो से सलाह मशविरा किए बिना हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। तब सरकार द्वारा कुछ और सरकार समर्थक किसानों से समझौता करवाया गया। इस समझौते का मीडिया के माध्यम से काफी प्रचार किया गया था, यह इसलिए किया गया था कि दिल्ली के राम लीला ग्राउन्ड मे 21 तारीख को होने वाली रैली मे लोग न पहुंचे। लेकिन इसके बावजूद भी लाखो लोगो वहां पर पहुंचे और हरियाणा सरकार की चुलें हिलाकर रख दी। पूरे उत्तरी भारत का किसान वाजपेयी और बी०जे०पी० के खिलाफ हो गया क्यो कि वह किसानो पर गोलियां चलाने वाले ओम प्रकाश चौटाला का समर्थन कर रहे थे।

श्री अध्यक्षः डा० साहब, अब आप वाईड आप करें।

डा० रघुबीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, इसी वजह से चौटाला को एक लायबिलिटी समझकर लोकसभा के चुनावों मे बी०जे०पी० ने चौटाला पार्टी से कोई समझौता नहीं किया। स्पीकर सर, मैं थोड़ी सी चर्चा कानून व्यवस्था पर भी करना चाहूंगा। चौटाला के समय हरियाणा मे जंगल राज था। आए दिन हत्याएं, चोरियां, राजनैतिक अपहरण, बलात्कार और डकैतियां होती थी। सबसे खेदजनक बात यह थी कि राजनैतिक संरक्षण प्राप्त कैदी जेलों में मोबाईल फोन से लोगों से फिरौती वसूलते थे। पुलिस अधीक्षक से लेकर के पुलिस महानिदेशक सभी आफिसर्ज चौटाला की बेतुकी हाजिरी भरते थे। चौटाला के बेटो को पायलट और एस्कार्ट गाड़ियां दी जाती थी, उनके लिए स्पैशल अल्फा कोड तय कर रखा था, उनके लिए रूट लगते थे। स्पीकर सर, एक खेदजनक बात मैं आपके माध्यम से सदन मे रखना चाहता हूं। स्पीकर सर, सांपला गढ़ी गांव सांपला के नजदीक चौधरी छोटूराम का गांव है। जिस महान शखसियत को किसानो की महफूजी के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया था उसके गाव से जब एक महिला अपने गुम पति को तलाश करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास फरियाद करने के लिए पहुची तो स्पीकर सर, बैरिगेट के अन्दर उस समय कई महिलाएं घुस गईं। उस समय उस औरत को पुलिस अधीक्षक ने धक्का मारा जिसके कारण उसका दूध मुआ बच्चा जो कि उसकी गोद में था, हरियाणा के मुख्यमंत्री की गाड़ी के बोनट पर जाकर गिरा। स्पीकर सर, तपतपाते हुए बोनट पर वह बच्चा जब चिल्लाया तो सबसे दुखद

बात यह हुई कि उस समय के हरियाणा के मुख्यमंत्री, नादिरशाह नजरिए के मुख्यमंत्री उस सारे सीन का लुतफ उठा रहे थे। उस आदमी ने एक बार यह नहीं कहा कि यह औरत क्या कहना चाहती है। स्पीकर सर, इससे दुखदायी बात और क्या हो सकती है? स्पीकर सर, चौटाला के शासन में न्याय के मन्दिर की अदालते भी सुरक्षित नहीं थी। जींद, झज्जर, रोहतक, पानीपत और गुड़गांव की अदालतों में गोलीकांड चौटाला के कार्यकाल में हुए थे। स्पीकर सर, हमारा सिर झुक जाता था जब हम यह देखते थे कि चार–चार बार विधायक बने स्वर्गीय चौधरी देवी लाल के साथी रहे इनैलो नेता चौटाला के बेटों के समारोह में सड़कों पर कुल मालाएं लेकर घंटों–घंटों इन्तजार करते थे। स्पीकर सर, मैं भेदभाव की कहानी भी आपके सामने रखना चाहता हूं। चाहे वह नोकरियो की बात थी, चाहे विकास के पैसे के बंटवारे की बात थी। चाहे पानी की बात थी, पूरे प्रदेश के साथ एक बहुत बड़ा भेदभाव हुआ खासकर विपक्ष के विधायकों के साथ तो बहुत बड़ा डिसक्रिमीनेशन हुआ। स्पीकर सर, बजट का 70 फीसदी हमेशा एक खास इलाके मे जाता था, 70 फीसदी नौकरिया एक? खास इलाके में जाती थीं, 70 फीसदी बिजली की सप्लाई एक खास इलाके में जाती थी और हरियाणा प्रदेश की नदियो के टोटल पानी का 70 फीसदी एक खास इलाके मे चल रहा था। अध्यक्ष महोदय, पिछली विधान सभा की अवधि मे 11 सत्र हुए। उनमें हमने एडजर्नमैंट मोशन के माध्यम से जब यह कहा कि पानी के बंटवारे पर सदन मे चर्चा होनी चाहिए क्योकि एस०वाई०एल० तो जब खुदेगी तब

खुदेगी लेकिन कम से कम जो इस समय प्रदेश में पानी है, उसका तो सही बंटवारा होना चाहिए लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारे ये सारे एडजर्नमैंट मोशज उस समय बिना किसी रीजन के रिजैक्ट कर दिए गए। इन सारी बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता इक्ट्रे हुए ओर उन्होंने इस बारे में एक संघर्ष करने की बात अपने दिमाग मे रखी तथा इस बारे में मीटिंग्ज बुलायी। उसके बाद हरियाणा कांग्रेस पार्टी के उस समय के अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 'जल युद्ध' के नाम से झज्जर के अंदर पहली बार एक बहुत बड़ी रैली रखी गयी। स्पीकर सर, इस रैली के डर से कि कहीं इस इलाके के स्वाभिमानी किसान, इस इलाके का मेहनतकश किसान इस भेदभाव के प्रति ये सारी बाते न जान लें और तेरी असलियत न पता लग जाए, उन्होंने तीस किलोमीटर दूर रोहतक मे प्रदेश स्तर की सरकारी रैली रखी और झज्जर की हमारी रैली को फेल करने के लिए सरकारी बाधाएं डाली गई, दबाव डाले गये लेकिन मैं मुबारिकवाद देता हूं उस इलाके की हरियाणा प्रदेश की मेहनतकश जनता को कि रोहतक की रैली के मुकाबले में दो या तीन गुना लाखों लोग उस रैली में इकट्ठे हुए।

श्री अध्यक्षः कादियान साहब, अब आप वाइंड अप करें।

श्री रघुबीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, इस बात को लेकर जब किसान आर–पार की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हो गया और जब किसान ने यह साबित कर दिया कि भूपेन्द्र सिंह हुड्डा बिना ताज के मुख्यमंत्री हैं तो चौटाला डर गया। स्पीकर सर,

भ्रष्टाचार पर अगर कोई किताब लिखना चाहे तो ग्रंथ के ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। उस समय गुड़गांव और फरीदाबाद में बिल्डरो से बिल्डिंग्ज और शापिंग माल्ज के नमो पास करने के लिए पैसे लिए जाते थे। संवैधानिक सत्ता के केन्द्र हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जनाजा निकाल दिया गया था। दुःख की बात है कि एच०पी०एस०सी० के मैम्बरान सरकारी गाड़ी में खुद आनसरशीट्स लेकर चौक करवाने के लिए जाते शे। एस०एस०एरन० बोर्ड मे हुई धांधली का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। स्पीकर सर, उस समय थाने और तहसील भी बिकते थे। एन०ओ०सी० और सी०एल०यू० के नाम से बड़ा भारी चढ़ावा चढ़ता था। छोटे बड़े उद्योगपतियो से चाहे वह राईस सैलर्ज हो या चाहे पैट्रोल पम्प डीलर्ज ऐसोशिएशन यो या चाहे कोई भट्टा ऐसोसिएशन हो, सबसे जजिया वसूला जाता था। स्पीकर सर, जिस ढंग से भूमाफिया को ओने पीने दामों में सडकों के ठेके, शराब के ठेके, खानों के ठेके दिये जाते थे वह बडे दुःख की बात थी। स्पीकर सर, मैं अर्ज करना चाहूंगा कि चन्दा इकट्ठा करने के लिए मशहूर चौटाला ने फिजी के अपदस्थ प्रधानमंत्री महेन्द्र चौधरी की मदद करने के नाम पर हरियाणा से करोड़ो रुपये का चंदा इकट्ठा करने का काम किया। स्पीकर सर, जो विकास के लिए राशि दी जाती थी, उसका दस फीसदी अफसरो के माध्यम से वह स्वयं उगाता था। चौटाला साहब दांत धिसाई के नाम से भी पैसा वसूलते थे उस समय लाखों रुपया चाय बगैरह पर खर्च किया जाता था। दक्षिणा के रूप मे भी पैसा लिया जाता था। स्पीकर सर, कारगिल की लड़ाई के योद्धाओं

के कहीं कोई बुत नहीं बने, कोई यादगार उनकी नहीं बनी। भगत सिंह चन्द्रशेखर, महात्मा गांधी, सुभाष चन्द्र बोस और जवाहर लाल नेहरु सरीखे नेताओं के बुत नहीं लगाये गये लेकिन हरियाणा ही नहीं बल्कि दिल्ली और चण्डीगढ़ में भी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के नाम से ट्रस्ट बनाकर अरबो– खरबों रुपयों की सम्पत्ति छीनने का काम हुआ। स्पीकर सर, हर महीने में एक हजार करोड रुपये का भ्रष्टाचार का कारोबार होता था। इसका 80 फीसदी बाप बेटों में जाता था और बीस फीसदी चेहते अधिकारियो और उनके समर्थको में जाता था। इसका नतीजा क्या हुआ 7 इसका नतीजा यह हुआ कि कभी बीड़ी उधार मागने वाला व्यक्ति, कभी मैक्सी कैब में किराया न देने वाला व्यक्ति, रिक्शा वाले से चार आने और दवत्री की लड़ाई लडने वाला व्यक्ति अरबों–खरबों रुपयों की सम्पत्ति का मालिक बन गया।

श्री अध्यक्षः कादियान साहब, अब आप वाईंड अप करें।

श्री रघुबीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, उसकी सम्पत्ति हरियाणा में ही नहीं बल्कि दिल्ली–चण्डीगढ़ से होती हुई आस्ट्रेलिया, कनाडा और अमरीका तक पहुंच गयी। इन देशों तक उसकी सम्पत्ति का विस्तार हो गया। यह बहुत बड़े दुख की बात है। उन्होंने दलितों ओर पत्रकारो को भी नहीं बख्शा। दुलीना और बरसौला में दलितों पर जुल्म हुआ। मीडिया प्रजातंत्र का चौथा स्तभ है। सिरसा के पत्रकार छत्रपति और कैथल के पत्रकार परमानंद गोयल की हत्या की गई जो कि चौटाला के माथे पर

इतना बड़ा कलक है जिसे गगा का सारा पानी भी नहीं धो सकता। रोहतक में पत्रकारों पर झूठे मुकदमें बनाए गए। शर्म की बात है कि जेल मे बंद खतरनाक अपराधियों के आगे दुम हिलाने वाले एक पुलिस अफसर के आदेश पर एक पत्रकार को रोहतक शहर की नाकेबंदी करके रात के दो बजे गिरफ्तार किया गया। मैं मीडिया के साथियों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने तमाम ज्यादतियो के बावजूद भी निभकिंता से अपनी कलम चलाए रखी। हमारी सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का पूरा सम्मान करती है।

श्री अध्यक्षः डा० साहब, अब आप वाइंड अप करे।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, रु कारगिल की लड़ाई में हरियाणा के हजारों बहादुर जवानो के बलिदान का जिक्र करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, हमें गर्व हे कि हमारे जवानों ने अपनी नवविवाहिता दुल्हनों और बूढ़े मां–बाप की चिता छोड़कर कारगिल की बर्फीली पहाड़ियो पर देश की सीमा की रक्षा हेतु सीने पर गोलियां खाई लेकिन चौटाला सरकार ने उनके बलिदान को यादगार बनाने की बजाए हरियाणा ही नहीं बल्कि दिल्ली और चंडीगढ़ मे भी स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के नाम से ट्रस्ट बनाकर अरबो रुपये की सम्पत्ति इक्ट्ठी की गई है।

Mr. Speaker: Dr. Sahib, please wind up. (Interruptions) I have got the responsibility. I know the Chief Minister is also sitting. (Interruptions) Why did't you realize at that time ?

डॉ० रघुबीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश चौटाला ने उस समय तो सामाजिक मूल्यों में गिरावट की सारी सीमाएं तोड़ ही दी जब उन्होंने सदन के नेता भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के विधान सभा क्षेत्र किलोई मे तब जलसा किया जब हुड्डा साहब हरिद्वार के पास पीली नदी के हादसे से बचकर दिल्ली के राममनोहर लोहिया अस्पताल मे जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। तब चौटाला ने किलोई हल्के ला डैड हल्का कहकर यह कहा कि हुड्डा कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। यह अलग बात है कि किलोई की स्वाभिमानी जनता ने उप चुनाव में चौटाला के उम्मीदवार की जमानत जब्त करवा दी और उसे मात्र तीन हजार वोट ही हासिल हुए। यहां मैं किलोई के साथ–साथ तोशाम और हिसार विधान समा सीटों के उप चुनाव जो कि स्व० सुरेन्द्र सिंह और रच० ओ०पी० जिंदल के एक विमान हादसे मे हुए दुखदाई निधान से हुए थे का जिक्र करना चाहूगा। हरियाणा के इतिहास में पहली बार इन उप चुनावो में सरकारी मशीनरी का प्रयोग नहीं हुआ। हुड्डा साहब ने तो पूरे उप चुनाव के दौरान अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं जाकर एक अनुकरणीय मिसाल कायम की। न ही वहां किसी तरह के माइक थे, न धूतू थे, न पोस्टर थे, न बैनर थे, न कुछ और था। लोगों ने भी अपने प्रेम और स्नेह को दर्शाते हुए उन्हे 1 लाख 3 हजार 635 वोट दिए। अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी की जींद मे हुई रैली जिसमें कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने प्रदेश की जनता का कांग्रेस को भारी बहुमत से सत्ता में लाने के लिए धन्यवाद किया था, का जिक्र

करना चाहूगा। उन्होने जींद रैली में कहा कि हरियाणा के विकास के लिए केन्द्र सरकार अपने खजाने की थैलियों का मुंह खोल देगी। श्रीमती सोनिया गांधी ने हरियाणा सरकार द्वारा थोड़े ही समय मे प्रदेश की जनता की भलाई के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की। अध्यक्ष महोदय दिल्ली के पास होने के नाते अच्छा प्रशासन देने के मामलो में हरियाणा दूसरे राज्यों को मार्ग दिखायेगा। मैं सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि हमारे मुख्यमत्री उनकी इच्छा को पूरी करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगे। अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश चौटाला ने सदन की मर्यादाओं को तहस नहस करने का भी काम किया था। लोकतंत्र में विपक्ष की प्रभावी भूमिका होती है लेकिन चौटाला ने विपक्ष को अपनी यह जिम्मेदारी भी नहीं निभाने दी। विपक्ष ने जब भी ऐडजर्नमैंट मोशज दिए, काल अटैंशन मोशंज दिये और उनके माध्यम से जनता पर हुई ज्यादतियों के मामले उठाने चाहे तो उनके प्रस्तावों को बगैर कारण बताएं खारिज कर दिया जाता था, बगैर किसी वजह के मैम्बर्ज को नेम कर दिया जाता था और जब कोई मैम्बर बोलने की कोशिश करता तो बगैर कोई रीजन बताए पूरे सैशन के लिए हाउस से निकाले जाने की प्रथायें मी डाली गयी थी

श्री अध्यक्षः डा० साहब, अब आप वाइंड अप करें।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश चौटाला के पांच वर्ष के शासन की कार्य प्रणाली पर

राजनीति शास्त्र के छात्रों की शोध करने का बहुत बड़ा विषय मिल सकता है, इस पर थीसिज लिखी जा सकती है। किलोई के उप चुनाव मे न कोई बैनर थे न पोस्टर थे न कटाउट थे, न कोई झंडे थे, न होर्डिंग थे, न कोई किसी तरह के माइक थे, न चंदा था, न चुटकी थी और न कैंडीडेट वहां गए। वहां की जनता बधाई की पात्र है कि उन्होंने भूपेन्द्र सिंह जी हुड्डा को इतने भारी बहुमत से चुनकर भेजा। पहले जब कोई चुनाव होता था तो तीन दिन पहले जीप पकड़ी जाती थीं।

Mr. Speaker: Dr. Sahib, please wind up now.

डॉ० रघुबीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, बेरी हल्के की पिछले पाच सालों की बहुत सारी समस्याए हैं उनकी लिस्ट में आपको दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार को गली सड़ी व्यवस्था विरास्त में मिली है जिसे सुधारने में समय लगेगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पर गीता का उपदेश दिया था। हरियाणा प्रदेश जहां दूध दही की नदियां बहती थी वहां शराब माफिया खान माफिया, भू माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया पैदा किये गये राजनेता और पुलिस अपराधियों से मिलीभगत देखने को मिली और एक ऐसा ताकतवर माफिया पनपा जिसने अपने धन और बाहुबल के दम पर प्रदेश की मेहनती, ईमानदार और स्वभिमानी जनता का जीना दूभर कर दिया।

Mr. Speaker: Thank you, Dr. Sahib, please take your seat. Thank you very much.

डॉ० रघुबीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार सभी माफियाओं को उखाड़ फैंक कर जनता को भ्रष्टाचार रहित, भयमुक्त, भूख मुक्ता और एक? पारदर्शी प्रशासन देने के लिए वचनबद्ध यह एक यहा है जिसकी सफलता के लिए सरकार तो हर सभव प्रयास कर रही है और करती रहेगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा हरियाणा प्रदेश की बहादुर जनता, को नौजवानो को, मजदूरो को, व्यापारियो को, उद्योग पत्तियो को, कर्मचारियों को और सभी विपक्ष के साथियो को कि वे इस यज्ञ में अपनी–अपनी आहुति दें तभी हमारे प्रदेश का चहुमुखी विकास संभव होगा। इसमें हम सबकी जिम्मेवारी भी है और नैतिकता भी है। हरियाणा विकास और जवाबदेह प्रशासन के मामले में देश के दूसरे राज्यों के लिए पथ–प्रदर्शन का काम करेगा।

Mr. Speaker: Thank you, Dr. Sahib, please take your seat.

डॉ० रघुबीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय मैं वित्त चौधरी बीरेन्द्र सिंह को और हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुडा को एक विजनरी बजट पेश करने के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं। वे एक अरमान को लेकर चले हैं। एक विश्वास हरियाणा की जनता में जगा है और उसे ऐसा लग रहा हे कि यह सरकार 20–25 साल तक चलेगी।

Mr. Speaker: Dr. Sahib, please take your seat.

डॉ० रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

Mr. Speaker: Thank you very much, Kadian ji. Now, I call upon Mr. Sushil Kumar Indora.

डॉ० सुशील इन्दौरा (ऐलनाबाद, एस०सी०): माननीय अध्यक्ष जी, में आपका आभारी हूं। और शुक्र गुजार हूं कि आपने मुझे इस बजट पर चर्चा में भाग लेने के लिए समय दिया। यह इस सरकार का पहला बजट है और में भी पहली बार इस चर्चा में हिस्सा ले रहा हूं। इसलिए मैं पिछली सरकार के बजट को ध्यान मे रखते हुए सदन मे अपनी बात रखना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे बहुमत से साथ कांग्रेस पार्टी ने पिछले चुनाव में जीत कर सरकार बनाई। लोगों ने इन में इसलिए विश्वास जताया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार उनके लिए अच्छे काम करेगी। कांग्रेस पार्टी के लोगो ने, नेताओं ने एक नारा दिया था कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ और यह कहा था कि हम भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे। माननीय बीरेन्द्र सिंह जी, वित्त मंत्री हरियाणा सरकार ने जो बजट पेश किया है उस बजट को जब मैं देख रहा था और पढ रहा था तो यह बात सत्ता पक्ष चाहे माने या न माने लेकिन यह बात अन्दरूनी तौर पर साफ झलक रही थी कि कहीं न कहीं वह पिछली सरकार चौधरी ओमप्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाली सरकार के कायल हैं। वे बाहरी तौर पर तो जनता के सामने निन्दा कर रहे हैं। लेकिन बजट बनाने में उनकी झलक

उन्होंने जरूर दी है। वित्तीय प्रबन्धन मे सुदृढ़ आर्थिक ढांचे के अन्तर्गत वर्ष 2003– 2004 और 2002–2003 में जो बताया गया है उस समय किसके नेतृत्व वाली सरकार थी? उस वक्त चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व की सरकार थी। हरियाणा सरकार ने अपने इस बजट में माना है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में अच्छा वित्तीय प्रबन्धन हुआ। इसकी तारीफ मैं नहीं करता बल्कि इसकी तारीफ स्वयं प्लानिंग कमीशन, भारत सरकार ने की अध्यक्ष महोदय, इसकी तारीफ योजना आयोग ने भी की, रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने भी की कि हरियाणा में वित्तीय प्रबन्धन बहुत अच्छा रहा। बजट एक ऐसा प्रस्ताव हे जिसके माध्यम से सरकार अपनी नीतिया, अपने कार्यक्रम जनता के सामने पेश करना चाहती है कि वह जनता को क्या देना चाहती है या जनता पर क्या खर्च करना चाहती है, उनकी नीतियां क्या हैं या किन नीतियो के तहत प्लान करके वे खर्चा करेगे और अगर कोई आपदा आ जाती है या कोई जरूरत पड़ जाए तो उसको नान–प्लान मे कैसे खर्च करेंगें यह सारी तस्वीर बजट के माध्यम से दिखाई जाती है। (दिव्य) हमने क्या दिया और आप क्या देगें तथा क्या दिया है आपने, इन सारी बातों का मैं जिक्र करूंगा अगर आप मुझे कहने का मौका देंगे। (विध्न) माननीय सुरजेवाला जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी तो मेरे लिए परमात्मा से भी बड़े हैं क्योंकि उन्होने ही मुझे पार्लियामैंट मे पहुंचाया और यहां विधान सभा में भी आने का मौका मुझे उन्हीं की वजह से मिला। हर आदमी का अपना नेता या गुरू होता है इसलिए मेरे लिए तो चौधरी ओम

प्रकाश चौटाला जी भगवान के समान है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि सरकार अपनी नीतियां बजट के माध्यम से दर्शाती है, प्रदेश के लोगों को बताती है कि किस किस मद पर कैसे कैसे खर्च करेंगे और कहां से सरकार पैसा जुटाएगी, कर्जा लेगी या कर लगाएगी, यह सारी बातें विस्तार से बजट के माध्यम से सरकार बताती है। पिछली बातों को देखे तो सत्ता पक्ष के लोगो ने, बुरा न मानना, मैं 9 तारीख को भी यहां था और आज भी यहां हूं, सिवाय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को गालियां निकालने के या उनके कार्यक्रमो को गलत बताने के अलावा यहां कोई काम नहीं किया। कोई संदेश इन्होंने ऐसा नहीं दिया जिससे जनता को ये पता चल सके कि इनकी सरकार प्रदेश के लोगो के लिए यह–यह कार्य करना चाहती है। लोगों को इनसे बहुत उम्मीदे हैं तभी उन्होंने इनको भारी बहुमत से जिताया है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि बजट के माध्यम से हरियाणा सरकार ने लोगो को एक ऐसा सपना दिखाया जिसे पूरा करने के लिए शायद बहुत मशक्कत करनी पड़े और शायद ये कर भी न पाए। बजट मे यथार्थ दिखना चाहिए और दिखना चाहिए कि उस सपने की नींव जो आप रखना चाहते हैं तो उस नींव में ईंट, गारा और मिट्टी लगाएंगे तो मजबूती आएगी या नहीं आएगी। पिछले बजट के प्लान के हिसाब से हम देखे तो पिछले रिवाइज प्लान मे 2237 करोड के मुकाबले में इस सरकार ने 3000 करोड़ का प्रावधान रखा है। 3000 करोड़ रुपये की इन्होंने प्लानिंग की है लेकिन कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनका बजट में कोई जिक्र नहीं है लेकिन उन्होने

होना ही है। अगर खर्च 3000 करोड से ज्यादा हो जाएंगे तो कहां से पैसा लाएंगे? अध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने सरकार सम्भाली थी तो उस वक्त प्रदेश की क्या हालत थी यह सबको मालूम है कि उस समय किस तरह से हमारे प्रदेश का आर्थिक ढांचा था? बड़ी खुशी की बात है और आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि पिछली सरकार के मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के कारण आपकी सरकार को प्रदेश की बहुत सुदृढ़ अर्थ व्यवस्था मिली है। अध्यक्ष महोदय मौजूदा सरकार ने जो घोषणाएं की हैं उनके बारे में मैं धीरे–धीरे बताउंगा। 2003–04 में नान–प्लान में जो खर्चा था वह 10563 करोड़ रुपये थे यानि की हमारी सरकार ने पहले जो खर्चा बढ गया था, उसको धीरे–धीरे कम करके काफी कम कर दिया था और अब नान प्लान में 11160 करोड़ रुपये खर्चा बनता है। यदि इसको पिछले प्लान के और इस प्लान के रिवाइज्ड एस्टिमेटस के हिसाब से देखें तो इसमे 1159 करोड़ रुपये फालतू खर्चा होता है जबकि पिछली बार 572 करोड़ रुपये था। इसी प्रकार से राजस्व घाटे की जहां तक बात है। जिस समय हमारी सरकार ने सत्ता संभाली थी उस समय यह 1998–99 मे 1540 करोड़ रुपये था और हमारी सरकार आने के बाद यह हमारा 2004–05 में घटकर 226 करोड़ रुपये रह गया था। 2005–06 का जो अनुमानित राजस्व घाटा है वह 948 करोड़ रुपये है यानि कि हमारी सरकार को जो 1540 करोड रुपये का राजस्व घाटा मिला था और जिसको कम करके हमने 226 करोड़

रुपये किया था, उसको यदि इुम मौजूदा सरकार का बजट देखे, सरकारी नीतियां देखें तो पता चलता है कि यह सरकार राजस्व घाटे को फिर से बढाकर वहीं पहुंचा देगी जो पिछली सरकारो के समय हो गया था। अध्यक्ष महोदय, यह तो मौजूदा सरकार का पहला बजट है यदि ऐसी ही सोच सरकार की रही तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था आने वाले पांच सालो मे चरमरा जायेगी और दोबारा से हमारी सरकार आने पर भी हम उसे नहीं संभाल पायेगे। जहां तक राजकोषीय घाटे का सवाल है, इस बारे मे मैं बताना चाहूंगा कि 1998–99 में राजकोषीय घाटा 2240 करोड़ रुपये था जिसे हमारी सरकार कम करके वर्ष 2004–05 मे 1026 करोड़ रुपये तक ले आई थी लेकिन मौजूदा सरकार ने जो प्लान बनाये हैं उनसे राजकोषीय घाटा 2323 करोड़ रूपये होने जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार कह रही है कि प्रदेश के विकास के लिए वित्त के बड़े अच्छे और सुदृढ़ प्रबन्धन किए गए हैं लेकिन आकड़े तो कुछ और ही बताते हैं। जहां तक ब्याज के भुगतान की बात है इस बारे मे मैं कहना चाहूंगा कि सरकार अपने आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए, प्रदेश की जनता को सुविधाएं देने के लिए लोन लेती है, सभी सरकारे लेती हैं और हर साल लेती हैं तथा उनका भुगतान भी किया जाता हे। 2003–04 मे हमारी सरकार के समय में ब्याज भुगतान 2113 करोड़ रुपये था, 2004–05 में यह 2166 करोड़ रुपये था और –यदि इस बजट में देखें तो यह बढकर 2354 करोड़ रुपये आने वाले समय में हो जायेगा। इसी रन अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से सरकार

हरियाणा के लोगों को सुविधाएं दे पायेगी, किस तरह से हरियाणा के लोगो की आकाक्षाओं पर यह सरकार खरी उतर पायेगी? जहां लक कर्ज की देनदारी का सवाल है 2003– 04 में हमारी सरकार के समय में कर्ज की देनदारी की सीमा 21616 करोड़ रुपये की थी, 2004– 05 में यह देनदारी की सीमा 22902 करोड़ की हो गई और आने वाले वक्त मे कर्ज की देनदारी की सीमा बढ़कर 25619 करोड़ रुपये हो जायेगी। ये लोग हमारी सरकार को कहते थे कि हमने प्रदेश को कर्जा लेकर देनदारी मे डुबो दिया। अध्यक्ष महोदय, यह इतनी ज्यादा देनदारी तो एक साल मे होने जा रही है अगर खुदा न खास्ता यह सरकार पांच साल तक चली तो पता नहीं प्रदेश के क्या हालात होगे? हुड्डा साहब, ध्यान रखिये कई दफा अपने लोग ही चकमा दे देते हैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि पांच साल तक यह सरकार चली तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था इस तरह के बजट से चरमरा जायेगी और हर आदमी कर्ज के नीचे पूरी तरह से दब जायेगा। जहां तक पैंशन एवं सलशज के खर्च की बात है, सरकार इसके लिए हमेशा प्रबन्ध करती है कि उसके इस्ताईज को सुविधाएं मिले। माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपने अभिभाषण मे कहा था कि कर्मचारियो के कार लोन बढ़ाए जाएंगे, कर्मचारियो के हाउस लोन बढ़ाए जाएगे और दूसरी सुविधाएं भी उनको दी जाएंगी। सरकारी कर्मचारियो को यह सब सुविधाएं दी जाती हैं क्योकि यह सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार द्वारा इन जिम्मेदारियों का प्रबन्ध इस तरह से किया जाता है कि आमदनी भी बढ़े और विकास कार्य भी हों। अगर खर्चा बढ़ता है तो

आमदनी बढ़ाना भी जरूरी है। अगर आमदनी बढ़ेगी तो खर्च को नियन्त्रित किया जा सकता है। राजस्व प्राप्तियो के मुकाबले मे अगर हम आमदनिया बढ़ी हुई दिखा दे तो उससे काम नहीं चलता। अगर हम तुलना करके देखे तो वर्ष 1998–99 मे 590390 राजस्व प्राप्तियां थीं और वर्ष 2004 –03 में 40.270 राजस्व प्राप्तियां थी और अब जो सैलरी देंगे और दूसरे खर्च करेंगे उसमें आधारभूत ढांचे पर तो कुछ भी खर्च नहीं होगा। यानि 1998–99 में हमारे पास इतना पैसा था कि अगर हम 1 क्र रुपये कमाए और उसमे से हम पैंशन दे दें, सैलरी दे दें और जो बच जाए उसको आधारभूत ढांचे पर खर्च कर दे तो भी दिक्कत नहीं थी लेकिन इसके मुकाबले में हमारे पास वर्ष 2005–06 में पैसा कम बचेगा। वर्ष 2004–03 मे जहां हम 50 रुपये आधारभूत ढांचे पर तथा 40% सेलरी और पैंशन पर खर्च कर सकते थे वहीं अब वह पैसा घट कर 60 मे से 58 रुपये रह गया है। हम इसमे और बढ़ौतरी कर देते हैं यदि हम लोगो के बीच में भाषण दे कर आते हैं, जनता मे कुछ कह आते हैं कुछ वायदे कर आते हैं और कुछ लुभावने वायदे कर आते है क्योंकि इन पर खर्च होने वाले पैसे को हम यहां पर नहीं दिखा पाते हैं। लेकिन इस बजट में जो दिखाया गया है, दर्शाया गया है वह सब सरकार की खर्च और राजस्व प्राप्तियां ही हैं। राज्य की अर्थ–व्यवस्था का सही रूप अगर हम मानते हैं तो राजस्व प्राप्ति में बढ़ौत्तरी खर्च के मुकाबले मे ज्यादा होगी तभी प्रदेश की अर्थ–व्यवस्था सुधरेगी। (विध्न) स्पीकर सर, इस बजट में पहली बार ऐसा हो रहा है। कि जो राजस्व प्राप्तियां 2004 –05 मे

1138.52 करोड़ रुपये थीं वह वर्ष 2005– 06 में 1237.2 7 करोड रुपये हो गई यानि कि इन्क्रीज 5.7% की है और जो खर्च बढ़ेगा, वह भी मैं यहां पर बता देता हूं। वर्ष 2004–05 में खर्च 11614.2 करोड़ रुपये था अब वह बढ़ कर 12985 .49 करोड़ रुपये हो जाएगा यानि कि खर्च मे इन्क्रीज 11.8% बढ़ गई। यह सरकार इसको कैसे सम्भालेगी 9 यह बजट में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि सरकार कैसे इस खर्च को सम्भालेगी? जहां तक जनता को सुविधाएं देने की बात है, आधारभूत ढांचे पर जो हम खर्च करते हैं वह हम जनता को सुविधाएं देने के लिए ही खर्च करते हैं। जैसे कि बिजली की व्यवस्था करने की बात है, पानी की बात है, सड़क की बात है परिवहन और यातायात के साधन सुचारू रूप से देने की बात है, कोई भी सरकार चाहे वह राज्य की सरकार है और चाहे वह केन्द्र की सरकार है, उसकी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं कि हम अपने देशवासियों को ये चीजें देंगे। हमारे पास आमदनी का अगर 100 रुपया आयेगा तो उसमे से फर्स्ट तो हम सैलरी और पैंशन का खर्च निकाल दें और उसमें से बाकी बचे पैसे को अगर हम इन्फ्रास्ट्रक्चर पर लगाएं तो हम काम कर सकते हैं। लेकिन अगर पिछली बार को देखा जाए तो परिवहन आदि पर 'हमारा जो खर्च होता हे वह तकरीबन 4590 होता है। स्पीकर सर, यह सारी बाते ऑन दि रिकार्ड की बाते हैं। सरकार के पास सारे रिकार्ड होते हैं। अब जो हम इन्फ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर पाएंगे वह हम 39% ही ज्यादा खर्च कर पाएंगे यानि कि 6% का डिफरैंस है जो यहां पर हो गया है। अगर 6% का डिफरेस हो जाता है तो

आप कैसे इस प्रदेश का विकास कर पाएंगे? स्पीकर सर, इसका मतलब यह है कि सरकार का ध्यान विकास की तरफ से हट रहा है और घोषणाओ की तरफ बढ़ रहा है। सरकार ने इस तरह की घोषणाएं की थीं कि ' कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ' आज गरीब की हालत आपके सामने है? भय और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात इस सरकार ने कही थी अध्यक्ष महोदय. जो मेरी जानकारी में है उसके मुताबिक माननीय मुख्यमंत्री जी के मोहल्ले में ही इन दिनो 10–10 चोरियां हुई हें। मेरे जिले में से भी एक 4 क्विंटल की तिजौरी ही चोर उठाकर ले गए। पता नहीं वे उस तिजोरी को क्रेन से उठाकर ले गए या क्रूस ले गए लेकिन ले गए हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस का राज आया तो हम हरियाणा में भय मुक्त राज देगे और ला एंड आर्डर सुधरेगा। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सदन मे बताना चाहूंगा कि मेरा एक दोस्त नरवाना मे इन्शयोरैंस कम्पनी मे लगा हुआ है वहां पर उससे कुछ लोगों ने उसकी कार छीन ली थी। उस दोस्त ने मुझे कहा कि आप जींद के एस०पी० को कह दो। जब मैंने वहां पर एस०पी० को फोन किया तो उसने मुझे कहा कि मुझे मालूम है कि उसकी कार चोरी हो गई है। अध्यक्ष महोदय, मैंने एस०पी० साहब को कहा कि आपने छीनी हुई गाडी को चोरी हुई कह कर इस केस की धारा ही बदल दी है। अध्यक्ष महोदय, एक गाडी चोरी हो गई हो और दूसरी गाड़ी छीनी गई हो और जिले के एस०पी० को यही नहीं पता हो इन दोनों में क्या फर्क है तो ये हालात तो

इनके राज मे है कि इतना सीनियर आफिसर इस तरह की बात करता है? इनके राज मे आज क्राईम रेट बहुत बढ़ा है।

शिक्षा मंत्री (श्री कुल चन्द मुलाना): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्यायंट आप आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, मै इनसे यह जानना चाहूंगा कि इनके राज मे कितना क्राईम रेट था और आज कितना क्राईम रेट है?

श्री अध्यक्षः मुलाना जी, क्यों पूछते हो। क्या यह किसी से छिपी हुई बात हे?

श्री फूल चन्द मुलानाः अध्यक्ष महोदय, इनके राज में तो जी०टी० रोड भी सेफ नहीं थी। आज तो क्राईम रेट घटा है। अध्यक्ष महोदय, एक शायर के शब्दो को मैं कोट करना चाहूंगा——

इनके राज के हालात बताने लगेंगे, तो पत्थर भी आसू बहाने लगेंगे।

कहां खो गई इनकी असलियत, उसे ढूंढने में जमाने लगेगे।।

श्री अध्यक्षः मुलाना साहब, आप बैठ जाए। प्लीज बैठिए।

डॉ० सुशील इन्दोराः मुलाना साहब, आज आपकी सरकार है और आप के पास सारे आकड़े है, आप अपनी सरकार के इन तीन महीनो के आकड़े और उस वक्त के आकड़ों को भी देख लें। आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। अध्यक्ष महोदय,

माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओर वित्तमंत्री जी ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से हुए नुक्सान के लिए मुआवजा देगे। स्पीकर सर, हमारे उपर अभी लांछन लगाया गया था कि हमारे समय में बहुत कम प्रतिशत राशि मुआवजे की बढ़ाई गयी थी। अध्यक्ष महोदय, हमारे से पहले की सरकारो ने इस राशि को कभी एक रुपया बढ़ाया था तो कमी 50 पैसे बढ़ाया था। अध्यक्ष महोदय, यह ऑन रिकार्ड की बात है और यह सरकार भी इसको जानती हे कि हमारे वक्त में जब ओलावृष्टि से फसलों का नुक्सान हुआ था तो चौधरी देवी लाल जी ने 17 अप्रैल 2001 को यह मुआवजा 600 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया था। उस वक्त तकरीबन 233 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया था। लेकिन आज यह सरकार हमारे उपर लांछन लगाती है कि हमने मुआवजा नहीं बढ़ाया था। आज यह सरकार किसानों की हितैषी होने का दावा तो करती है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ऊंगली कटा कर शहीद होने वाली बात का दावा तो कर सकती है लेकिन किसानो के बारे में कुछ नहीं कर सकती हे। अब इस सरकार ने बजट में कहा है कि गुड़गाव मे किसानो की जो लैंड एक्वायर की जाएगी उसके लिए उनको 15 लाख रुपए प्रति एक्क मुआवजा देंगे, एन०सी०आर० के एरिया में साढ़े बारह लाख रुपए प्रति एकड़ देगे और राज्य के अन्य क्षेत्रों के लिए पाच लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी सरकार के वक्त में 8 – 10–2001 को गुडगांव के सैक्टर 37 के लिए जब खांडसा गांव की जमीन के मुआवजे के लिए अवार्ड हुआ था तो उस वक्त वहां

पर 15 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया था। उसके बाद कितना इंफ्लेशन हुआ था यह सब तो आप जानते हैं। स्पीकर सर, उसके बाद फिर गुड़गांव जिले के सिरहोल गांव में 12 –3–2004 को जब अवार्ड दिया था तो उसमे भी 20 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया था। That was the decision not of the Government, that was the decision of the Land Acquisition Officer. उस वक्त 20 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया था और आज यह सरकार किसान की हितैषी होने का दावा करती है। ये आज गुड़गांव के हालात देखें तो इनको पता चलेगा कि किसानो को कितना पैसा मिला है? जहां करोड़ों की जमीन है और पहले की सरकार जहा पर 16 लाख और 20 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे चुकी है उसके बदले में आज ये 15 लाख रुपए देकर यह कहते हैं कि इनकी सरकार किसानों की हितैषी सरकार है।

स्पीकर साहब, अभी 9 तारीख को भी एक हादसा हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी सिरसा में भी गए थे, मैं उसके लिए इनका धन्यवाद करता हू। ये केवल छतरीया गांव मे और उतावड गांव मे गए थे। हालांकि हमारे यहां पर कई ऐसी जगह थी जहां पर कई बडे–बड़े हादसे हुए थे, मकान भी ढह गए थे और तूडी जल गई थी। स्पीकर सर, इतनी बुरी हालत हुई थी कि आज वहां पर नरमा कपास की फसल दोबारा से नहीं बोई जा सकती है। (विघन) अगर यह सरकार किसानों की इतनी ही हितैषी है तो इनको इस बारे मे कुछ करना भी चाहिए। (विघ्न) अगर सही

मायनों मे ये किसान के हितैषी है तो इनको इसी सत्र में ही इस बारे में घोषणा करनी चाहिए क्योंकि अब नरमे की बिजाई नहीं हो सकेगी। (विघन) नरमें की फसल का जो नुक्सान हो गया उसके लिए कम से कम बीस हजार रुपये किल्ला भी देने की अगर सरकार घोषणा करे तो हम उसका स्वागत करेंगे। (विघन) सत्ता पक्ष की तरफ से यह बात जरूर आती है चौधरी कि देवीलाल के बूत लगा दिए। अध्यक्ष महोदय, हर आदमी अपने नेता का मान–सम्मान करता है। श्रीमती सोनिया गांधी हमारे लिए भी सम्माननीय हैं हालांकि वे कांग्रेस पार्टी की नेता हैं लेकिन हम भी उनका मान करते हैं। मैं एक बात को जरूर कहूंगा कि हर सरकार अपने नेता का सम्मान करती है, हमारी पार्टी भी अपने नेता का सम्मान करती थी और ये भी अपने नेता का सम्मान करते हैं लेकिन कम से कम इनको कुछ तो ऐसा करना चाहिए की इनके नेता का मान सम्मान तो बढ़े। सिर्फ जींद मे एक महिला कालेज श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम से खोलने की ये बात कर रहे हैं जोकि बडे दुख की बात है। कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी मैजोरिटी से आयी है इसलिए इनको अपने नेता का उचित ढंग से सम्मान करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इतनी बडी पार्टी की वे नेता रही हैं, वे देश की भी प्रधानमंत्री रही हैं एवं वे इस देश की सम्मानित नेता रही हैं लेकिन अगर उनके नाम से सिर्फ एक छोटा सा महिला कालेज जींद मे खोला जाता है तो इसी से इनकी मंशा जाहिर हो जाती है इसी से पता चलता है कि ये कितने बड़े हित चिन्तक हैं।

Mr. Speaker: Mr. Indora, please take your seat. Your time is over now.

डॉ० सुशील इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, में हकीकत बता रहा हूं। चौधरी देवीलाल के बुतों के बारे में तो यहा पर कह दिया जाता है। में इनको एक बात और बता देना चाहता हू। सरकार ने फैसला लिया है कि स्वर्गीय राजीव गांधी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, के नाम से एक एजुकेशन–सिटी स्थापित किया जाएगा। (विघन)

Mr. Speaker: Hon. members take your seats. Let him proceed . Let him conclude. He is not going to say Irrelevant thing Let him conclude his speech. (Interruptions) Dr. Sahib, Please be relevant. Only 2 minutes are left. I am not going to extend your time, because everybody wants to speak on Budget.

डॉ० सुशील इन्दौरा: सर, मैं पांच या सात मिनट और लुंगा।

श्री अध्यक्ष: आप दो मिनट में अपनी बात खत्म करे।

डॉ० सुशील इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी के नाम रो एक एजुकेशन सिटी बनाने की बात इस बजट में कही गयी है लेकिन इससे बुरी और क्या बात होगी कि इसके लिए बजट में केवल पांच लाख रुपये का प्रावधान किया गया है? अध्यक्ष महोदय, ये उनके नाम से एक आक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं लेकिन बजट में इसके लिए केवल पांच लाख रुपये का

ही प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री बीरेन्द्र सिंह जी नहीं है उनको यह बात देखनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में बजट मे काफी ढूढता रहा क्योकि यह काफी बड़ी यूनिवर्सिटी होगी लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मैमोरैंडम, 2005 मे नॉन प्लान ऐक्सपैंडीचर स्कीम मे इन्होंने पेज नं० 226 पर यही लिखा है कि इस लिए केवल पांच लाख रुपये ही खर्च करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इससे सरकार की मंशा का पता चल जाता है। पता नहीं इतने रुपयों से ये कैसे आक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी यहां खोलेंगे?

Mr. Speaker: Mr. Indora Your time is over. Please conclude.

डा० सुशील इन्दौराः अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हर जिले में एक माडल स्कूल खोलने की बात बजट मे कही गयी है। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्बली कहा था कि एक स्कूल के लिए तीन करोड रुपये खर्च करेंगे। उन्होने केवल 16 जिलो का ही जिक्र किया था जबकि मैं समझता हूं कि हरियाणा में 20 जिले है। खुदा न खास्ता अगर कांग्रेस पार्टी मेवात जिले को जिला नहीं मानती है तो भी 19 जिले बनते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि ये माडल स्कुल खोलने को बात आज की नहीं है। इसका उदाहरण है कि वर्ष 2003—04 के बजट में भी पंचकुला में एक माडल स्कूल खोलने की बात कही गयी है।

Mr. Speaker: Thank you Mr. Indora.

डॉ० सुशील इन्दौराः सर, मैं पांच मिनट और लूंगा।

Mr. Speaker: No, no. Please take your seat.

डॉ० सुशील इन्दौराः सर, अभी तो एस०वाई०एल० का मुद्दा और है।

Mr. Speaker: I say no. Your time is over. Shri K.L. Sharma, you may start now.

श्री खैराती लाल शर्मा (शाहाबाद): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। वर्ष 2005–06 का जो बजट माननीय वित्त मंत्री महोदय ने 9 जून, 2005 को इस महान सदन मे प्रस्तुत किया, मैं उसका अनुमोदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सच बात तो यह है कि अगर विरोध करने के लिए ही इस बजट का विरोध किया जाए तो अलग बात है परन्तु ध्यान से पढ़कर समझने की कोशिश की जाए तो इससे बढ़िया और प्रशंसनीय बजट कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैंने पिछले भी 3–4 साल के बजट पढ़े हैं सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस चीज को ये बार बार कह रहे हैं कि 3 हजार करोड़ रुपये के वार्षिक प्लान से कैसे काम चलाएंगे तो ये पहले अपना पिछला बजट उठाकर देखें। इन्हे वर्ष 2004–05 के लिए वार्षिक प्लान के रूप में 2100 करोड़ रुपया मिला था। बाद में उसमें संशोधन करके इनको 2236.72 करोड़ रुपया मिला था। इस तरह से उससे 34 परसैंट ज्यादा पैसा हमने

लिया है और ये साथी बार बार कह रहे हैं कि यह पैसा कम पड़ जाएगा। यह बड़ी सोच की बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने भय भ्रष्टाचार मुक्त शासन तंत्र देने की बात की थी। विपक्ष के साथी आज यह कह रहे हैं कि हमारे मोहल्ले से साइकिल चोरी चली गई, हमारे वहां एक दुकान से गल्ला चोरी हो गया, मैं इन साथियों को बताना चाहूंगा कि जब किसी सरकार की ला एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो वह चीज कहनी चाहिए जिसके पीछे कोई बात नजर आती हो। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने इलाके की बात कहना चाहता हूं। मेरा इलाका आपके इलाके के साथ–साथ लगता है। पिछले सात आठ साल से जी०टी० रोड़ के साथ लगता हुआ एरिया जेसे शाहबाद मारकंडा का एरिया पिपली का एरिया और उधर अम्बाला तक का एरिया अपराध की स्थली के रूप में पनप गया था। यहां तस्करी और नशीले पदार्थों की बिक्री होती थी। पिछले आठ साल के अदर किसी सरकार के कान मे जूं नहीं रेगी, किसी ने कुछ नहीं किया। जो जी०टी० रोड पर ढाबे थे वहां जाकर सरकार के एम०एल०ए० हार डलवाया करते थे। चण्डीगढ़ पुलिस ने वहां जाकर छापे मारकर ऐसी तस्करी करने वाले लोगो को पकड़ा। अभी थोड़े दिन पहले पेपर में था कि कोई मि० यादव, एस०पी०, चण्डीगढ़ के हैं, उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार को हमने इस बारे में दो बार पहले भी इन्फार्म किया था। अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि मैं एक डैथ केस के सिलसिले में शमशान भूमि में गया था वहां एक बुढिया रोती हुई मिली और मुझे कहा कि

परमात्मा ने आपको मौका दिया है आप कुछ कर सकते हें उसने मुझे रिक्वैस्ट की कि आप इस तस्करी की बीमारी को और नशे की बीमारी को दूर कीजिए। उसने कहा कि इस बीमारी से मेरे दो बेटे थे, दोनो गुजर चुके हैं अब मुझे कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है। मैंने इसके लिए आई०जी०, सी०आई०डी० श्री परमिन्द्र सिंह राठी से टैलीफोन पर बात की। आई०जी०, अम्बाला से भी मिला और मुख्यमंत्री जी से भी मिला। मैं इनको बधाई देना चाहता हू कि पिछले दो महीने से वहा पर इस तस्करी पर पूर्ण विराम लगा हुआ है। वहां पर एक भी तस्कर नहीं पकड़ा गया। ऐसा हुआ है। लेकिन मैं इसके साथ एक बात कहना चाहूगा कि यह सोच लेना कि यह काम बन्द हो गया है, ठीक नहीं होगा। इसके लिए हमे और वाच करना होगा क्योकि दो महीने का कोई शफीशियंट टाईम नहीं है। हां अगर 6 महीने तक अंकुश लगा कर रखे तो ठीक रहेगा। जो आफिसर्ज वहां पर लगाकर रखे हैं वे वहीं रखे जायें तो शायद वे लोग अपना स्थान बदल लेगें। वरना वे वहां पर फिर से पनप सकते हैं। (विघन) यह अगर ली एण्ड आर्डर को कंट्रोल करने की बात नहीं है तो और क्या हो सकती है? बजट के पैरा 9 में पैंशन की बात कही गई है। स्पीकर सर, आपको याद होगा, चुनाव के समय में जब हम गांवो मे जाते थे तो बड़ी भारी भ्रान्ति फैलाई गई थी। लोगो को कहा जाता था कि अगर काग्रेस की सरकार आ गई तो वृद्धा पैंशन और जो सौ काल्ड कार्यक्रम हैं जो वे कहते थे कि हमने शुरू किए हैं, उन पर विराम लग जायेगा और वृद्धा पैंशन बन्द कर दी जायेगी। लेकिन जैसे ही हमारी

कांग्रेस की सरकार आई तो आते ही न केवल वृद्धा पैशन बल्कि उस के साथ–साथ विकलांगों, विधवा और निराश्रितो को दी जाने वाली पैंशन की पुष्टि भी की गई। इससे एक तो हमारा नैतिक कार्य पूरा हुआ तथा जिन आखों में विश्वास अविश्वास मे बदल गया था और इन बातो को सुन करके जिनको अविश्वास की एक परछाई नजर आती थी कि शायद कांग्रेस के टाईम में कहीं हमारी पैंशन कट न जाये उनको भी अब कृतज्ञता के भाव नजर आने लगे हैं। स्पीकर सर, थोड़े दिन पहले की बात है कि एक बुजुर्ग आदमी हमारे पास आया था। उस समय आप भी वहीं थे मैं भी वहीं था क्योकि उस दिन कुरुक्षेत्र मे महाराणा प्रताप जयन्ती मनाई जा रही थी। एक व्यक्ति स्टेज पर चढ़कर अपनी खुशी का इजहार करता हुआ दुहाई दे रहा था। उसके वर्डिग थे कि ' पहले भूपि फिर भूपेन्द्र और अब भूप' बना हरियाणा का। आपने अगर उस आदमी के भावों को पढ़ा होता, उस बुजुर्ग की लैंग्वैज को अगर समझा होता। तो आपको पता लगता कि जो इन लोगों द्वारा बाते कही गई थीं, उनका असर आज लोगों के अन्दर क्या आया है? जब आखें दुआ के लिए उठती हैं तो इसे आप समझ सकते हैं। उस व्यक्ति की आखे भी दुआ के लिए ही उठी थी और उसी का परिणाम हुआ कि तीन उपचुनावों में रिकार्ड कायम हुआ। जो पहले कभी नहीं हुआ था और न ही आगे कभी आने वाले समय में टूटता हुआ नजर आता है। स्पीकर सर, बजट में पैरा 14 मे गरीब ओर किसान की हितैषी सरकार की बात कही गई है। स्पीकर सर, इसके बारे मे मैं एक बात कहना चाहूगा कि जो आर्थिक सर्वेक्षण

दिया हुआ है, सरकार ने उसमे मैंनशन किया है कि अन्त्योदय अन्न योजना केन्द्र सरकार ने चालू की है उसके अन्दर अत्यंत गरीब परिवारो के लिए 35 किलो गेहूं दो रुपये प्रति किलो के हिसाब से दिया जायेगा। जो परिवार पावर्टी लाईन से नीचे हैं, उन परिवारों को इस योजना के तहत अन्न देने की बात कही गई है। इसके साथ यह भी कहा गया है कि इसमें जो 3.90 करोड़ का खर्चा होता था और जो लाभ मिलता था, वह लाला लोग ले लेते थे लेकिन अब वह भी सरकार द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। जिनको लाल और गुलाबी कार्ड दिए गये हैं उनको 6353 मीट्रिक टन गेहूं का आबंटन प्रति मास हरियाणा में होता हे। 1,92008 अल्योदय परिवारो को गुलाबी कार्ड दिए जा चुके हैं। स्पीकर सर, इसके बारे में भी मेरा कहना है कि अन्धा बांटे रेवड़ी मुड़–मुड कर अपनो को दे तो यह बात इसमें होती है। आप भी गावों में जाते हैं और हम भी गावों में जाते हैं तो वहां एक ही बात सुनने को मिलती है कि गुलाबी कार्ड उन्हीं व्यक्तियों को दिए गये हैं जो इसके पात्र नहीं है। स्पीकर सर, अगर कोई अच्छी योजना है, गरीब लोगो की योजना है तो सरकार उसको चलाए। जिन गरीब लोगो तक लाभ पहुंचाने के लिए योजना बनाते हें अगर उस योजना का लाभ उन गरीब व्यक्तियो तक नहीं पहुंच पाये और भाई–भतीजावाद को सामने रखकर सो–काल्ड अपने लोगो की बात की जाए तो वहां पर कैसे लोगों का भला हो सकता है? मेरी मुख्यमंत्री महोदय और वित्त मंत्री महोदय से गुजारिश है कि जब वे कुरूक्षेत्र में गए थे तब भी हमने यह बात कही थी कि इसका

सर्व कराया जाए क्योंकि तब ही पता लगेगा कि किन लोगो को ये दिये गये हैं, कौन इसके पात्र हैं, किसको इनकी जरूरत है, किसको इनसे फायदा हो सकता है? अभी यहां किसान कै हित की बात की जा रही थी। अभी भाई इन्दौरा जी बता रहे थे कि हमारी सरकार किसान के हित भी सरकार थी लेकिन यह बात तो सामने आ चुकी है। यह कहने का फैसला हमने और आपने नहीं करना, यह फैसला किसान के बेटे ने कर दिया कि किसान के हितैषी कौन है? किसान का हितैषी वह कैसे हो सकता है क्योंकि जिसको किसान ने कुर्सी पर बिठाया उन्होने उसी किसान पर देशद्रोह का मुकद्दमा चलवाया और उन पर गोलियां चलवाई। भारतवर्ष कै। संस्कृति रही है कि अगर किसी ने किसी महिला या माता पर आख उठाई तो उसको बक्शा नहीं जाता। रावण जैसे व्यक्ति को यहां बख्शा नहीं गया, लेकिन हमारे यहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने किसान की बेटी और बहू को नहीं बक्शा और उनको जेल मे भेजने का काम किया। ऐसा व्यक्ति किसान का सिपाही या हितैषी कैसे हो सकता हे? इन्दौरा जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। मेरे इलाके मे एक गांव चडनी है जब मैं वहां एक रैली मे गया तो वहा एक व्यक्ति महमा सिंह जो पहले आपके साथ जाया करता था, हरे रंग का साफा पहना करता था, 4–4 ट्रक खाने के बनवाकर आपकी रैली मे जाया करता था मुझे मिला इस बार वह सफेद साफा और गले में कांग्रेस का पट्टा डालकर बैठा था। मैंने उससे पूछा कि आपका हरा साफा कहां गया तो उसने कहा कि मैंने उस हत्यारे का हरा साफा फाड़कर फैंक दिया।

भूपेन्द्र सिंह हुडा जी की सरकार ही सही मायनों मे कांग्रेस की हितैषी सरकार है। उनका अंगवस्त्र मैंने पहन लिया है और में यहां आपके सामने बैठा हूं। इस तरह से कांग्रेस की हितैषी सरकार मेरे कहने या आपके कहने से नहीं है बल्कि हरियाणाा की जनता ने, किसान के बेटे ने इस बारे मे फैसला कर दिया है कि किसान का हितैषी कौन है। बजट के पैरा नं० 17 पर सिंचाई और सतलुज यमुना लिंक कैनाल की बात की गई है। इससे पहले वाले येरा में जमीन के मुआवजे की बात आई हे। अध्यक्ष महोदय आपको याद होगा जब शुरू मे यह सरकार बनी ही थी और आपने इस गरिमामय पद को सम्भाला ही था तभी टेलीफोन पर इन्फर्मेशन आई कि हमारे इलाके मे बहुत भारी वर्षा के साथ ओलावृष्टि हुई है। बाद में पता लगा कि बहुत भारी मात्रा में हमारा नुकसान हो गया। आप रात को ही वहां चले गए और सुबह आए। सैशन चल रहा था, मैं भी वहां गया। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि हम तो मुआवजा मांगते नहीं। और हमारे टाईम में ज्यादा मुआवजा दिया गया है। इस बार जब हम मुआवजे की लिस्ट मुख्यमत्री जी के पास लेकर गए और डिस्कस किया तो पता लगा कि इनके सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड से जब किसी की भरपाई नहीं हो पाएगी। तो उस किसान की भरपाई कैसे हो पाएगी? यह उस वक्त पहला सैशन था, और उस वक्त मुख्यमंत्री अभी ओथ लेकर बैठे ही थे लेकिन उन्होने उसी समय फैसला लिया कि भरपाई का पैसा पूरा करने के लिए 50 प्रतिशत कम से कम गेहूं की फसल के लिए वृद्धि की जाएगी और 25 प्रतिशत दूसरी फसलों के लिए वृद्धि की

जाएगी यह रिकार्ड की बात है जो आपकी समझ मे नहीं आएगी। पता नहीं कब का आप 6000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा सुना रहे हैं? आप कभी 600 से 6000 की बात करते हो। आपको 4 दिन पहले की बात तो समझ मे नहीं आती, पता नहीं कौन सी पुरानी बातों को कहते जा रहे हो। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तमंत्री जी को बधाई देना चाहता हू। कि इन्होंने बजट मे प्राकृ तिक आपदाओं से निपटने के लिए 124.37 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। प्राकृतिक आपदाओं के लिए यह पर्याप्त राशि है और इस राशि के एक साल में जो भी आपदाएं आयेगी उनसे निपटा जा सकेगा। इसके साथ–साथ मैं सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के बदले मे मिलने वाले मुआवजे का जिक्र करना चाहूंगा। मेरे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि उनकी सरकार के समय मे गुड़गांव मे 15 लाख या 20 लाख रुपये भूमि अधिग्रहण करने पर प्रति एकड़ सरकार ने किसानों को दिया। इस बारे में मैं विपक्ष के साथियो को बताना चाहूंगा कि किसी बिजनैस सैंटर के अधिग्रहण पर 20 लाख रुपये मुआवजं के दिए होंगे लेकिन बाकी जमीन के अधिग्रहण के मापदण्ड स्थापित नहीं किए। जबकि हमारी सरकार ने अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के मुआवजे के मापदण्ड स्थापित किए हैं। केवल एक शहर के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के –लिए किए हैं। अगर गुडगांव की बात आती है तो गुड़गांव मे भूमि अधिग्रहण करने पर न्यूनतम 15 लाय रुपये प्रति एकड़ मुआवजे के दिए जायेगे। इसके अतिरिक्त पंचकुला तथा चण्डीगढ़ के निकट के क्षेत्रो समेत शेष एन०सी०आर० में 12. 5 लाख रुपये

प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जायेगा और राज्य के अन्य क्षेत्रों में पाच लाख रुपये भूमि अधिग्रहण करने पर मुआवजे के दिए जायेंगे। इस तरह के मापदण्ड हमारी सरकार ने स्थापित किए हैं। जो बहुत ही सराहनीय कार्य है। इंदौरा साहब, आपकी सरकार ने गुड़गांव में किसी बिजनैस सैंटर को 15 या 20 लाख रुपये मुआवजा दिया होगा लेकिन आपकी सरकार के बाकी क्षेत्रो के लिए मापदण्ड नहीं थे कि गुड़गांव मे जो भी जमीन एक्वायर की जायेगी उसको 15 या 20 लाख रुपये मुआवजे के दिए जायेगे। आपकी सरकार के समय मे यदि कहीं पर पांच लाख रुपये भी डी०सी० रेट के हिसाब से दिए हों तो आप बतायें कहीं नहीं दिए गए। इंदौरा साहब, कमियां छुपाने से छुपती नहीं हैं। जबकि हमारी सरकार ने जो सलम एरियाज हैं यदि वहां भी भूमि अधिग्रहण की जायेगी तो उनके लिए भी पांच लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब मुआवजा देने के मापदण्ड निर्धारित किए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त एक बहुत ही अच्छी बात छुपे शब्दों में वित्तमंत्री जी ओर मुख्यमंत्री जी ने मानी है कि यह सरकार समझौते और बातचीत की नीति मे विश्वास रखती है। पिछली सरकार ने लोगों को बरगलाया कि वे उनके बिजली के बिल माफ कर देगी। पांच साल तक उनका राज रहा लेकिन उन्होने बिजली के बिल माफ नहीं किए। पिछली सरकार ने लोगों को खूब मुर्ख बनाया लेकिन हमारे वित्तमंत्री जी ने पूर्ण ढ़के –छुपे शब्दो मे इस बारे में कहा है। मैं उनकी लाईने पढ़कर सुनाता हूं। उन्होने कहा है कि ' वर्तमान सरकार समझौते और बातचीत की नीति मे विश्वास रखती है।

सरकार ने किसानो के बिजली के बकाया बिलो के संवेदनशील मुद्दे के समाधान के लिये मेरी अध्यक्षता में (मेरी यानि उनकी अध्यक्षता में) एक समिति गठित की है। हमारी सरकार सत्ता के विकेन्द्रीकरण के सिद्धांत में विश्वास रखती है। ग्राम विकास समितियो जैसी असंवैधानिक संस्थाओ को भंग करके पंचायती राज संस्थाओ जैसी संवैधानिक संस्थाओ की स्वायत्ता बहाल की गई है''। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी कुरुक्षेत्र मे बताकर आये हैं कि किसानों के बकाया बिजली के बिलों की किस्ते बना दी जायेंगी। जो भी किसान अपने बिल की एक किस्त का भुगतान करेगा उसकी एक किस्त उसके साथ माफ कर दी जायेगी। अध्यक्ष महोदय, यह प्रैक्टिकल बात है और बड़े सुचारू ढंग से की जाने वाली बात है। इस स्कीम से किसानो ढो माफी भी मिलेगी और समस्या का भी समाधान होगा। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ वित्तमंत्री तो ने कुरुक्षेत्र मे एक और बात यह भी कही थी कि कोई किसान यदि यह कहे कि हमने तो पहले गरे बिल भरे हैं तो हमे तो बिल मरने का जुर्माना हो गया। इस बारे में वित्त मंत्री जी ने यह माना था कि जिन्होने बिल भरे हैं उनको भी कसीडर करके उनकी भरपाई की जायेगी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की कथनी और करनी मे कोई अंतर नहीं हे जबकि पिछली सरकार सिर्फ एनाउसमैट्स करती थी, उन्हें पूरा नहीं करती थी जबकि हमारे वित्तमंत्री जी ने पूरा करके दिखा दिया। अध्यक्ष महोदय, अब मैं सतलुज यमुना लिंक नहर के बारे में बात करना चाहूंगा जो कि हमारी सिंचाई नीति का केन्द्र बिन्दु हैं।

अध्यक्ष महोदय, सिंचाई की बात पिछले अधिवेशन में भी चली थी। जो सबसे बड़ी बात हमारे इलाके की है वह यह है कि हमारे इलाके शाहबाद को दादूपुर–नलवी नहर ट्रीट करती है। पिछले अधिवेशन मे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण मे भी इसकी चर्चा की गई थी कि शाहबाद के इलाके से दादूपुर– नलवी नहर गुजरती है। अभिभाषण मे कहा गया था कि उनकी सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि इस नहर को वह बनवायेगी। स्पीकर सर, इसके लिए टाइड बान्ध बनाने की भी बात थी। हालांकि अभिभाषण मे पूरी तरह से उसका जिक्र नहीं किया गया है। परन्तु मैंने दादूपुर नलवी नहर के लिए न्यू एक्सपैंडिचर मे देखा है उसमे लिखा हे कि Dadupur-Nalwi irrigation scheme, an amount of Rs. 43.04 crores has been proposed for 2005-2006. This also includes establishment expenditure of Rs. 11.04 crores. स्पीकर सर, इसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है। इस स्कीम के लिए वर्षों से केवल घोषणाए ही घोषणाए होती चली गई और हर कोई इस नहर को बनाने की बात कहता रहा, हमें लाली पॉप देता रहा तथा हम लोग देखते रहे। पहली बार यह योजना अमल मे आ रही है और हमारी सरकार ने इसको अपने प्लान मे लिया है। अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं। इसका पहला जो ओरिजनल ऐस्टिमेटस बना था वह 167 करोड रुपये का था। अब इसके बारे में लिखा हुआ है कि इसके टेण्डर लगाए जा चुके है और भुगतान चालू कर दिया गया है। मैं इनसे यह पूछना चाहता हू क्या कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है? इसमें शुमार किया

गया है और किसी जगह पर भी कहीं एक एकड़ का भुगतान हुआ है इसमे केवल ऐसा लिखा हुआ है इसके अन्दर वास्तव में कुछ किया हुआ नहीं है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मन्त्री महोदय से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर इसमे से ऐस्टेब्लिशमैंट का खर्चा निकाल दिया जाए तो यह 32 करोड़ रुपया बचता है। मेरे हिसाब से यह 32 करोड़ रुपये इस स्कीम के लिए थोड़े कम है। मेरी यह गुजारिश है कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और यदि इसको जल्दी से जल्दी कम्पलीट करना है तो इसके बजट को थोडा सा और बढ़ाए। माननीय मुख्यमन्त्री तथा वित्तमन्त्री महोदय से मेरी यह अपील है कि इस पर जरूर गौर फरमाएं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक राज्य के प्रत्येक जिले मे मॉडल स्कूलो को खोलने की बात का सम्बन्ध है, इन्दौरा साहब कह रहे थे कि तीन करोड़ रुपया खर्च किया गया है। यदि उन्होंने यह किताब लेकर पढ़ा होता तो उनको जवाब मिल गया होता। इसका .जवाब इसमें लिखा हुआ है। मॉडल स्कूल खोलने के साथ ही साथ उन्होने लिखा हुआ है। मॉडल स्कूल सब जगह पर हैं, इसमें इसका पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। ये कह रहे हैं तीन करोड रुपये का स्कूल बनाया गया है। मैने सारा भाषण पढ़ कर देख लिया है इसमें कहीं पर यह नहीं लिखा है कि तीन करोड़ रुपये के स्कूल की एनाउसमैंट पित्त मन्त्री महोदय ने की है। इसमे यह लिखा हुआ है कि One such school at Panchkula started functioning from 2003-2004 academic session. It is proposed to set up 18 model schools. One school of each district will get

@ Rs. 15.00 Lacs for furniture and setting up of computer lab and to provide infrastructure thereof. यानि की कम्पयूटर लैब और फर्नीचर के लिए यह राशि रखी गई है। मॉडल स्कूलो को शेप देने के लिए मेरे ख्याल से यह बहुत राशि है लेकिन यह इन्हें पता नहीं है कि जो तीन करोड़ रुपये की राशि है वह सारे स्कूलो के लिए हैं और उन्होने इसे सारे स्कूलो की बजाए एक स्कूल के साथ जोड़ लिया और इसके बारे में कहना शुरू कर दिया। स्पीकर सर, स्वास्थ्य सेवाओ की बात बहुत बड़ी बात है। यहां पर इसका भी पूरा ब्यौरा दिया गया है। स्पीकर साहब. मैंने पहले भी रिक्वैस्ट की थी। हमारी हैल्थ मिनिस्टर साहिबा बैठी हुई हैं। मैंने उनसे भी और वित्तमंत्री भी जब कुरूक्षेत्र गए थे उनसे भी तब रिक्वैस्ट की थी। पिछले 7–8 सालो से हम अस्पतालों के आधुनिकीकरण की बात कर रहे हैं, आधुनिक उपकरण प्रोवार्ड्ड करने की बातू कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे ठोल गांव में पिछले 10 सालों से हॉस्पिटल की बिल्डिंग बना रखी है। स्पीकर सर, वहां के लोग हर सरकार के वक्त में कहते हैं कि बिल्डिग हमने बना दी और जगह भी दे दी है। मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से और मुख्यमत्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर यह सरकार वहां पर थोड़ा सा सामान सौर एक डाक्टर दे दे तो आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने कहा है कि 40 हजार की आबादी पर ही प्राईमरी हैल्थ सैन्टर खोल देंगे तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पिछली सरकारो के वक्त से हमारी यह माग रही है और आज की सरकार

से भी हमारी मांग है कि वहां पर अगर कोई कमी है तो थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दें। वहां पर लोगों की पिछले 10 सालों से पी०एच०सी० बुनवाने की मांग है और लोगों ने वहां पर बिल्डिंग भी बनवा रखी है। अगर वहां पर थोड़ी बहुत आबादी कम है तो इसमे उन लोगो का क्या कसूर है? मेरा हैल्थ मिनिस्टर से निवेदन है कि सरकार अपनी नीतियों मे ढील देकर लोगो की इस मांग पर गौर कर।

स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देवी): शर्मा जी, वहा पर हम सब–सैन्टर खोल देंगे।

श्री खैराती, लाल शर्मा: मंत्री जी, आपके आश्वासन देने का बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, आप बहुत ही लिबरल हैं और बहुत ही अच्छे मूड मे हैं। मेरी एक बहुत ही पुरानी डिमान्ड है और आप आज देख ही रहे हैं कि जी०टी० रोड पर आज इण्डस्ट्री किस तरह से पनप रही है। आपने तो यह डिसाइड किया है कि गांवों के इन्टीरियर मे भी इन्डस्ट्री खोलेगे और वहां के लोगों को पूरी सुविधा मिलेगी। लेकिन स्पीकर सर, मेरी कास्टीचुएंसी एक ऐसी कांस्टीचुएंसी है जिसको जी०टी० रोड पर होते हुए भी आज तक इण्डस्ट्रियल टाऊन डिक्लेयर नहीं किया गया है। आज मुख्यमत्री जी मूड में दिख रहे हैं और मुझे लगता है कि आप मेरी दूसरी डिमाण्ड भी पूरी कर देगे। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

उद्योग मंत्री (श्री लक्षमण दास अरोड़ा): शर्मा जी, आप जो हुक्म करेंगे हम वैसा ही कर देंगे।

श्री खैराती लाल शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हू कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और वित्तमंत्री जी तथा मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता. हूं कि उन्होंने इतना अच्छा बजट पेश किया है। अब यह बजट किसी के समझ में नहीं आए और अगर कोई इसको बुरा कहता रहे तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। जिसकी समझ मे आएगा तो वह इसको बहुत ही बढ़िया कहेगा। डिप्टी स्पीकर सर, इसके साथ ही मैं सरकार को इस बजट को पेश करने के लिए बधाई देता हूं और अपना स्थान लेता हूं। जय हिन्द।

श्री राम कुमार गौतम (नारनौंद): डिप्टी स्पीकर साहब, वित्तमंत्री जी ने बजट को संवारने की कोशिश की है लेकिन उनकी यह कोशिश बहुत ही मामूली सी कोशिश है। जितने दिन हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला का राज रहा है उसके बारे में हमारे कांग्रेस के भाई, हम भी और हरियाणा की सारी जनता यह महसूस करती है कि ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा को बुरी तरह से रौंदा है, बहुत ही बुरी तरह से बर्बाद किया है लेकिन इस बजट में कोई ऐसी बात दिखाई नहीं देती और न ही 100 दिन की इस सरकार की मंशा झलकती है कि इस सरकार ने यह किया है। इन्होने एक भी कदम उस लाईन पर चलाया हो, जो इन्होंने चुनाव से पहले कहा था तो आप मुझे बताएं। क्रप्शन जहां थी, ज्यू

की त्यूं ही है। तहसील मे थानो में और सभी दफ्तरों में ज्यू की त्यूं ही क्रप्शन आज भी है। वही पीले कार्डज हैं और वही गुलाबी कार्डज हैं। कोई फर्क आया हो तो आप मुझे बताएं। यह ठीक है कि कई अच्छी बाते इस सरकार ने की हैं मैं उसकी तारीफ भी करता हूं। यह नहीं कि विरोधी हैं तो विरोध ही करेंगे। अच्छी बात की हम तारीफ भी करते हैं। (विघ्य) चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी मेरी बात सुन रहे हें मैं इनको बताना चाहूंगा कि आज बिजली की समस्या ज्यों की त्यों ही है। डिप्टी स्पीकर सर, एक बात मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहूंगा कि हमारे जो बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार थे, हमारे जो वर्षों से चाहने वाले थे, उन्होने भी हमारे को वोट नहीं दिए। वे कहते थे कि इस बार कांग्रेस की हकुमत आएगी और कांग्रेस की सरकार औथ लेते ही हमारे को नौकरी मे ले लेगी। इन्होने पहले बार–बार कहा था कि पिछली सरकार ने 27 हजार कर्मचारी नौकरी से निकाल दिए। मैंने पिछले सैशन में भी उस समय कहा था कि बहुत खुशनुमा माहोल है आप इनको वापस नौकरी पर ले लो। लोगों ने इसके बाद मुझसे कहा कि आपने तो शुरू में ही हुड्डा साहब की तारीफ करनी शुरू कर दी। देंने उनसे कहा कि वह फ्रीडम फाईटर का पोता है उसके दादा फ्रीडम फाईटर रहे हैं वह बड़ी लड़ाई लड़कर आया है इसलिए मैंने क्या गलत कहा है? मैंने तो उसी दिन कहा था कि इतना खुशनूमा माहौल है इसलिए आज एक फैसला होना चाहिए कि जिनके घरो मे चूल्हे नहीं जल रहे हैं जो लोग एम०आई०टी०सी०, कोनकॉस्ट या पुलिस विभाग से निकाले गये हैं उनको फिर से

नौकरी पर लेने के लिए आज ही घोषणा होनी चाहिए और कोई समय इसके लिए निश्चित होना चाहिए। लेकिन अभी तक भी सरकार ने इस बारे में कलम नहीं टेकी। इसके लिए कोई न कोई तो समय निश्चित होना चाहिए। इसके अलावा क्लीन एंड बेनेवैलेन्ट गवर्नमेट यानी स्वच्छ और कल्याणकारी शासन की बात की जा रही है लेकिन एक बात मुझे बताओ कि अगर इन्होंने स्वच्छता की तरफ एक कदम भी बढ़ाया हो तो आप मुझे बताएं। आप बताएं कि करप्शन कहां खत्म हुआ 7 करप्शन तो आज भी यूं का यूं ही है। उपाध्यक्ष महोदय, ओम प्रकाश चौटाला ने जिस तरह से प्रदेश की सारी नदियों पर कब्जा कर लिया था, सारे पहाड़ों पर कब्जा कर लिया था और सारी खानो पर कब्जा कर लिया था तो वैसी की वैसी पोलिसी आज भी हैं यूं ही सारा अमला–असल है, इसमे बाल भी फर्क नहीं हुआ हे। मुझे बताएं कि सरकार ने इस बारे में क्या किया है ? क्या सरकार ने इस बारे में कोई व्हाईट पेपर जारी किया है ? इसलिए सरकार बताएं तो सही कि उसने किया क्या है? (विघन) उपाध्यक्ष महोदय, हरिजन भाईयों ने, बैकवर्ड क्लासिज के भाईयों ने एवं 36 –बिरादरी के भाईयों ने कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में गजब कर दिया लेकिन सरकार ने हरिजन भाईयो के लिए बजट मे केवल 51 करोड़ रुपये रखा है जबकि बैकवर्ड क्लासिज के भाईयों के लिए न के बराबर पैसा रखा है और इकोनोमिकली वीकर भाईयों के लिए बजट मे कोई पैसा रखा ही नहीं गया है। मुझे बताएं कि सरकार ने इनके लिए कौन सी ऐसी बात की है जिसको हम यहां पर कहें? अगर ये ओम

प्रकाश चौटाला को हथकड़ी लगाकर लाते या उसकी सारी जायदाद कुड़क कर देते तब तो सारे लोग इनके गीत गाते और ये सारे भाई भी खुश हो जाते लेकिन इन्होने कुछ नहीं किया। यहां पर तो सब कहते हैं कि चौटाला ने यह कर दिया वह कर दिया। अरे चौटाला ने तो कर दिया लेकिन सरकार ने इन सौ दिनों मे क्या किया? उपाध्यक्ष महोदय, सब जानते हैं कि चौटाला ने नाश कर दिया लेकिन इन सौ दिनों मे आपने एक कदम भी नहीं उठाया। उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार जो 60 एम०एल०एज० के लिए बजट था वह 10 करोड़ 21 लाख 37 हजार रुपये का था ओर दरर मंत्रियों के लिए 11 करोड़ 15 लाख 44 हजार रुपये का बजट था अब यह बजट बढ़ाया गया है। पहले मंत्रियों का डिसक्रिशनरी कोटा 1. 52 करोड़ रुपये था अनैर अब की बार मत्रियो का डिसक्रिशनरी कोटा 3. क्त करोड़ तक बढ़ा दिया गया है। 60 एम०एल०एज का पहले बजट 10 करोड़ 21 लाख 37 हजार था इस बार इसको 12 करोड़ 18 लाख 35 हजार किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रियों के पिछली बार दो करोड रुपये बढ़ाये थे और अब कि बार सात करोड रुपये से इकट्ठे ही 11 करोड़ रुपये बढ़ा दिए गए। (विघन) मेरा कहने का मतलब यह है कि एम०एल०एज० की ग्रांट भी होनी चाहिए। पंजाब में 40 लाख रुपये और दिल्ली में 70 लाख रुपये एम०एल०एज० को ग्रांट दी जाती है। हुड्डा साहब, आप बड़े प्यारे आदमी हो इसलिए आप आज ही इस बारे में अनाउंस करें क्योंकि आज एम०एल०ए० को कोई पूछता नहीं है ये बेचारे लांडे बुचे हांडै गामा मे, कोई पूछता नहीं

है। इनकी ग्रांट कम से कम चालीस या पचास लाख रुपये तो होनी ही चाहिए। एम०पी० को भी दो करोड़ रुपये की ग्रांट मिलती है इसलिए एम०एल०ए० के लिए चाहे आप 50 लाख रुपये दें या एक करोड़ रुपये दें लेकिन कुछ न कुछ तो आप अनाउंस करें। (विघ्न) मेरे कहने का मतलब यह है कि आज की यह सरकार बड़े चाव से आयी है, लोगो ने बहुत प्यार से इसको चुना है इसलिए इनको कुछ न कुछ तो करके दिखाना चाहिए। मैं तो ईमानदारी से कहता हूं कि जिस तरह से चौटाला साहब को लोगों ने डले मारे, अगर आपने भी कुछ नहीं किया तो आपको भी कुछ दिन बाद उसी तरह से लोग मारेंगे। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः आपका टाईम खत्म हो गया है। अब आप बैठिये।

श्री नरेश मलिकः उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी की बात साबित होने लग रही है कि चौटाला साहब को प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश इतनी गाली देने लग रहा है कि हम सारे तो मर लेगे लेकिन चौटाला नहीं मरेगा।

श्री उपाध्यक्षः ठीक है, अब श्री धर्मबीर गाबा जी बोलेगे।

श्री धर्मबीर गाबा (गुड़गांव): उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया। पहले महामहिम का अभिभाषण और उसके बाद वित्त मंत्री का भाषण ये दोनों हमारे लिए ऐसे अक्ष होते हैं, आईना होते हैं कि

गवर्नमैंट क्या पॉलिसी अख्तियार करने जा रही है, क्या बजट होगा, कितना पैसा डिवैलपमैंट के लिए रखा जाएगा यह सारा आइना होता है इसलिए हम इस पर डिसकस करते हैं। सरकार को इस बात की प्रायोरिटी देनी चाहिए कि जहां पर पैसा कम है वहां पर वह इसे बढ़ाये। बजट मे यह भी आइना होता है कि गवर्नमैंट की क्या पॉलिसी रहेगी। लोगो की भलाई के क्या काम किये जाएंगे, इस बात का सबूत बजट होता है। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री जी को इसके लिए गाईडैंस भी मिली है और डैडीकेशन भी पूरी है एवं कैपेबिलिटी भी है। आज इन्होंने जो बजट पेश किया है उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन पर मैं वित्तमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और साथ ही सुझाव भी देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा कि जो फाइनैंस मिनिस्टर साहब ने बजट मे प्रोविजन रखी है चाहे वह एजूकेशन के लिए है, चाहे ट्रांसपोर्ट के लिए है, प्लान जो 3 हजार करोड की है, उसमे से 46 परसैंट पैसा सोशल ऐक्टीविटीज के लिए रखा है। 2003–04 में 1024 करोड़ रुपया इस काम के लिए रखा गया था लेकिन अब 2160 करोड़ रुपया रखा गया हे। यह भलाई का काम है। ऐग्रीकल्चर और रूरल डिवैलपमैट के लिए 636 करोड़ रुपया रखा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं कहना चाहता हूं। हम कहते .हैं कि अमेरिका में सड़कें ठीक हैं और अमेरिकन यह कहते हैं कि हम अमीर इसलिए हुए हैं कि हमारी सड़कें अच्छी हैं। सडके ठीक हों तभी इकोनोमी बढ़ती है, मंडियों में एप्रोच होती है, इंकम बढ़ती है, मुल्क खुशहाल होता है इसलिए मैं समझता हूं कि

जितनी प्रायोरिटी आप ट्रांसपोर्ट और रोड्स को दे रहे हें इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। चुनाव के समय हमने बहुत बड़े–बडे नारे लगाए थे। आज मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और विपक्ष के साथियों को बताना चाहता हूं कि ये जो गुडगांव मे सरकार द्वारा अधिगृहित की जाने वाली जमीन के मुआवजे की 13 लाख रुपये की बात करते हैं कि 15 लाख रुपये मिलते हैं मैं विपक्ष के साथियो को बताना चाहूंगा कि आपने घर जलते देखे हैं। हमारा घर जला है आपने सिर्फ तपिश महसूस की होगी लेकिन जले तो हम है। इससे बड़ा अनर्थ और कोई नहीं हो सकता कि कॉल सैंटर्ज के अंदर लोगों को पीटा जाए कि हमारी ही टैक्सी रखो नहीं तो और टैक्सी नहीं रख सकते। गुड़गांव के अंदर हालत यह हो गई कि एक घास काटने वाला ठेकेदार भी उन्हीं का आदमी होगा। यह हालत कर दी थी। आप हलवाइयो से जाकर पूछो। जो बडे–बड़े हलवाई हैं उनके मुंह पर मिठाई का डिब्बा मारा जाता था कि यदि मिठाई खिलानी है और सही माने में मिठाई देनी है तो डिबे को नोटों से भरकर लाओ। इंदौरा साहब जाकर पता कर सकते हैं गुड़गांव मे शाम स्वीट्स है और ओम स्वीट्स हैं,, में नाम बता रहा हू। आप उनसे जाकर पूछ लेना कि कितने लाख रुपये उन्होंने दिए हैं। मैं बाकायदा नाम बता रहा हूं। आप 15 लाख रुपये की बात कर रहे हैं। दूसरी जो हमारे को फैसिलिटीज मिली है वह टोटल मिलाकर 22 लाख रुपया बनता है हम किसान से वायदा करके आए थे कि अगर कांग्रेस की हकुमत आती है तो काग्रेस आपको दिल्ली के मुकाबले मे जमीनों का

कम्पनसेशन देगी। दिल्ली मे 25 लाख रुपया मिलता है और हम हरियाणा में 22 लाख रुपये मुआवजे दे रहे हैं। इससे गुड़गाव का किसान तो बहुत खुश है। यह बात मानकर चलनी पड़ेगी कि हमने वायदा किया था कि हम आपको भयमुक्त शासन देगे, क्या आप समझते हैं कि आज ऐसा नहीं है? आप गलत कहते है। आज हम भयमुक्त न होते तो जितनी जोर से बात आज हम कह रहे हैं कह नहीं सकते थे। आज लोग सड़क पर भी ऐसे ही कहते हैं। ये बात ठीक है कि अभी थोडा वक्त और लगेगा। मैं फाइनैंस मिनिस्टर महोदय से अपील करना चाहता हूं कि वित्तमत्री जी, मैंने आपका बजट देखा है उसमें 40 लाख रुपये पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए रखे गये हैं। मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि जब तक आप पुलिस को पी०सी०आर० नहीं देंगे। तब तक बात नहीं बनेगी आज हर डिस्ट्रिक्ट मे चाहे वह फरीदाबाद हो या गुड़गांव उसमे जब तक आप नये थाने नहीं बनाते हैं, नये पी०सी०आर० नहीं देते हैं और 50–50 या कहीं पर 150 पुलिस वाले नहीं देते हैं तब तक बात बननी मुश्किल है। अगर ये चीजें आप कर देते हैं तो यह दो महीने मे ही सब ठीक हो जायेगा। इस चीज की बडी सख्त जरूरत है। क्योकि गुड़गांव एक बढ़ता हुआ प्राकृतिक शहर हे इसलिए उसको आज नये थानों की जरूरत है। चाहे पालम विहार हो, चाहे सैक्टर 56–57 हो, वहां पर आज इस चीज की बहुत जरूरत है। मेरी आपसे दरखास्त है कि इस पर आप गौर जरूर कीजिए, यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा आज हमारे लिए जिन्दगी और मौत का एक और जो सवाल है वह है वाटर सप्लाई। मैं

धन्यवाद करता हूं सी०एम० साहब का जिन्होने वहां पर दूसरे ट्रीटमेन्ट प्लांट का उद्‌घाटन किया है 28 तारीख को। अगर हमे 20 मिलियन गैलन पानी मिलता रहेगा तो हमे आशा है कि जो पानी हमे मिलता था वह 40 मिलियन गैलन हो जायेगा जिससे उस इलाके के लोगो की पानी की समस्या दूर हो जायेगी। वह पानी तभी मिलेगा जब कैप्टन साहब, अगर आप उस नहर को 60 क्यूसिक पानी देंगे। अगर इतना पानी नहीं देंगे तो यह बेकार हो जायेगा। हमारी पार्टी ने लोगों से वायदा किया था कि 200 लीटर पर कैपिटा पानी देंगे। उसके लिए अगर आप हमें इतना पानी देते हैं तो कम से कम हम लोगो से यह तो कह सकते हैं कि कम से कम 100 लीटर पर कैपिटा पानी तो उनको मिल ही जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है और यह बात मैं फख से कहना चाहता हूं कि दो चीफ मिनिस्टर साहब बनने के लिए चुनाव लड़ते हे जिन्होंने चुनाव में करोड़ो रुपये खर्च किए वह चुनाव हार जाता है और आज विधानसभा में शक्ल दिखाने के काबिल भी नहीं हैं जबकि एक ऐसा चीफ मिनिस्टर है जो यह कहता है कि एक पैसा किसी से भी नहीं लूंगा क्योकि मेरा खर्चा नहीं है। वह यह कहता है कि मैं मुनादी भी नहीं करूंगा। सबसे बड़ी बात जो इन्होंने की वह यह कि इस भले आदमी ने किसी से एक पैसा नहीं लिया और उसके बाद भी एक अच्छे मार्जिन से रिकार्ड से चुनाव जीत कर आये। जिसने करोड़ों रुपये खर्च किए वह हार गया। यह फर्क है सोच का, यह फर्क है पर्सनैलिटी का। आज इस सदन में ऐसा बजट पेश हुआ है जिसमें प्लानिंग के लिए तीन हजार करोड़ रुपये

का प्रावधान रखा है। उसमे भी उन्होंने प्रोयोरिटी दी है सोशल वर्क को वाटर सप्लाई को, रोड को, ट्रान्सपोर्ट को। लेकिन एक होम महकमा ऐसा है जिसको आप नजर अन्दाज नहीं कर सकते क्योंकि आप सब, सी०एम० साहब और हम सभी जनता से वायदा करके आये हैं कि हम जनता को भयमुक्त हकुमत देंगे लेकिन जब तक प्रदेश की पुलिस को नई टैक्नालोजी के साथ, ट्रान्सपोर्ट के साथ हथियारों से लैस नहीं करेंगे तब तक ऐसा संभव नहीं होगा जो पैसा इसके लिए बजट मे रखा है क्या यह पैसा सैफीशियंट है ? तब तक हम वह बात पूरी कर नहीं सकते जिसका वायदा हम जनता से करके आये हें। यह मेरी आपसे रिक्यैश्ट है। मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगा कि जो 80 और 90 करोड़ रुपये अर्बन डिवलपमैंट के लिए रखे हें उसमें हर साल 18 करोड़ रुपये लगाने का प्रावधान है। क्या आप समझते हैं कि इतने पैसों में जो 60 म्युनिस्पिल कमेटीज हैं उनका डिवलपमेंट हो जायेगा आप डिवलपमेंट भी चाहते हैं लेकिन पैसा भी पूरा नहीं रखना चाहते। चाहे अबर्न डिवलपमेट हो, चाहे पंचायत हो, चाहे म्यूनिस्पिल कमेटीज हो ये ऐसे इन्टीव्यूशंज हैं जो मैं समझता हूं कि डैमोक्रेशी की बुनियाद है इसलिए इनको डिवैलप करने के लिए आप पैसा दीजिए। 60 म्यूनिस्पिल कमेटीज में 16 करोड़ रुपये से कुछ नहीं बन पायेगा। आज सबसे बड़ी दिक्कत अबर्न एरियाज के अन्दर है तथा क्योंकि मैं और सदस्य भी ऐसे ही कांस्टीच्यूशी को रिप्रैजंट करते हैं इसलिए हमें पता है कि आज सबसे बड़ी दिक्कत वहां सीवर की है इसके जो पुराने पाईप हैं उनको बदलना है।

जब तक पैरो नहीं देगे वै बदल नहीं जा सकते। उसके बाद रोड की बात आती है पानी के पाईप की बात आती है। मेरी आपसे एक और प्रार्थना है कि जो पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट है इसको पैसा ज्यादा दिया जाए पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेन्ट को पैसा देना बहुत जरूरी है क्योंकि शहरो में बहुत बुरा हाल है। मैं समझता हूं कि आपके डर से कुछ डिवैल्पमैंट अब जरूर हो रहा हे लेकिन आज भी इसकी ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस ओर ध्यान दिया जाए। इरीगेशन के लिए भी बजट में बहुत पैसा .रखा गया है। मेरी भी ऐज एम०एल०ए० चौथी टैन्योर है और हर बार हमने यह सुना है कि पानी का वितरण बराबर किया जाएगा लेकिन किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। शायद यह पहली बार है कि हर हालत में यह काम हो रहा है कि पानी के वितरण मे बराबर का हक सबको मिल रहा है। इसमे सबसे बड़ी खुशी की बात यह हुई कि बजट मे लमसम 2200 करोड़ रुपये इरीगेशन के लिए रखे गए हैं। मेरी कैप्टन साहब से प्रार्थना है कि हरियाणा मे जितनी नहरें हैं, वे कैपैसिटी से भी आधा पानी ले रही हैं इसलिए जब तक आप उनकी सफाई नहीं कराएंगे तब तक उनमें पानी पूरा नहीं आएगा और जब तक उनमें पूरा पानी नहीं आएगा तब तक टेल एण्ड तक पानी कैसे पहुंचेगा 7 इसके बारे मे आज हाउस में भी काफी शोर हुआ है। तब तक नहरें कैपेसिटी पूरी नहीं लेगी जब तक इनकी सफाई नहीं करवाएंगे इसके बाद ही टेल एण्ड तक पानी पहुंच पाएगा। इसलिए मैं कैप्टन साहब से कहना चाहूगा कि इस काम को वे प्रायोरिटी पर लें। हमारे

हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या पावर की है। मुझे खुशी है कि इस बार बजट मे 1647. 41 करोड़ रुपये पावर के लिए रखे गए हैं। पावर की आज बहुत जरूरत है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। कि जो इडस्ट्रीयल पोलिसी 6 जून को आई तो 6 जून को मुख्यमंत्री महोदय ने मारूति की दूसरी फैक्ट्री का फाउंडेशन स्टोन रखा। शर्मा जी भी बैठे हें वे इसको गोर से पढे। इसमें इंडस्ट्री डिपार्टमेट, गवर्नमैट आफ हरियाणा ने 88 ऐसे प्वायट और दिखाए हें जिसमें इंडस्ट्री को वे डिवैल्प करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इससे एक इंडस्ट्री जोन हरियाणा में हो जाएगा। कल ही शायद ट्रिब्यून अखबार में मुख्यमंत्री महोदय की स्टेटमैंट आई थी कि इंडस्ट्री लगाने के लिए हम लोगों को इन्वाइट करना चाहते हैं, हम इन्वैस्टमैंट चाहते हैं, हम हर हालत में इंडस्ट्रियल पीस चाहते हैं। खास तौर से गुड़गांव के बारे में लिखा हुआ था कि हम इंडस्ट्री पीस चाहेगे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा गुड़गाव में इंडस्ट्रीज एस्टेबलिश कर सकें। मैं समझता हूं कि सारे माहौल को देखकर एक अच्छा बजट रखा गया है चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे इरीगेशन हो, चाहे पावर हो, चाहे एजूकेशन हो, चाहे अर्बन डिवैल्पमैंट हो या पचायत डिपार्टमेट हो, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं जिसको टच न किया गया हो। मैं वित्त मंत्री महोदय से एक बात कहना चाहता हूं। जैसा कि बजट में भी कहा गया है। अगर सरकार इस पर अमल करती है तो यह भी एक इतिहास बन कर रह जाएगा कि ऐसा बजट कभी हरियाणा मे पास हुआ था और हर हालत में यह

कुल फलैज्ड तरीके से पास हो जाएगा। मेरी आपसे इतनी प्रार्थना है कि इस बजट में जो जो बातें कही गयी हैं उन पर जरूर अमल किया जाए। धन्यवाद।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक (गोहाना): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं हमारी सरकार की तरफ से जो बजट पेश किया गया है उसका अनुमोदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे से पहले सभी साथियो ने, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि विपक्ष के साथियो ने भी कोई खास मुद्दे इस बजट की आलोचना के लिए नहीं दिए तथा डायरैक्टली और इनडायरैक्टली सभी ने बजट का समर्थन किया है। 100 दिन के हमारे कार्यकाल में आम आदमी यह महसूस करता है कि आज मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं बिलकुल आजाद हूं और अपनी बात कह सकता हूं। जो पहले चौटाला साहब के राज में घुटन महसूस करते थे वह घुटन आज नहीं है। कहते हें कि जब शुरू मे आजादी मिली, उस समय हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पण्डित जवाहर लाल नेहरू किसी गांव मे गये थे, वहां उन्हें एक साधारण आदमी मिल गया। उस साधारण आदमी ने प्रधानमंत्री जी से पूछा कि कहते थे आजादी मिलेगी, क्या आजादी मिल गयी? नेहरू जी ने कहा कि भैया यही तो आजादी है कि आप अपनी बात बोल रहे हो और देश के प्रधान मंत्री से बात कर रहे हो। इसी तरह से हमारी सरकार में सभी को अपनी बात कहने का हक है और सभी लोग

खुश हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी सरकार हो उसकी क्षणने बड़ी दो बातो की जिम्मेवारी होती है। एक तो कानून व्यवस्था को ठीक करके जनता की जानमाल की हिफाजत करने की और दूसरी प्रदेश के नागरिकों को आगे बढ़ने के अवसर दिलाने की। ये दोनो बाते अब हम सबके सामने हैं। यदि इस समय चौटाला साहब यहां सदन मे होते तो बहुत अच्छी बात होती और उनको यहां आना भी चाहिए क्योकि आलोचना तो आदमी को ऊपर उठाने के लिए होती है। लेकिन मैं तो डाक्टर सुशील कुमार इंदौरा जी की बदकिस्मती मानता हूं कि चौटाला साहब यहां पर हैं नहीं और उनके ऊपर उनकी सरकार द्वारा की गई कारगुजारियों की बौछारे हो रही हैं। यदि चौटाला साहब यहां होते तो इंदौरा साहब बच जाते। उपाध्यक्ष महोदय, यह भी इनकी बहुत अच्छी बात है कि ये अपने नेता का पूरा बचाव करने में लगे हैं।

श्री सुखबीर सिंह (सोहना): उपाध्यक्ष महोदय, डाक्टर इंदोरा साहब को संजय की भूमिका निभा रहे हैं। जिस तरह महाभारत में संजय युद्ध की सारी जानकारी धृतराष्ट्र को दे रहा था उसी तरह सदन की सारी जानकारी इंदौरा जी चौटाला साहब को देते हैं।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): उपाध्यक्ष महोदय, डाक्टर इंदौरा जी एक इन–डिफैंसिव केस लड़ रहे हैं, ये यह भी जानते हें कि ये यह केस लड़ने से पहले ही हार रहे हैं। लेकिन हम इनकी काबिलियत की दाद देना चाहेंगे कि ये बहुत

काबिल वकील है। ये यह जानते हुए भी यह केस लड़ रहे हैं कि this is a lost case before it has even started.

डा० सुशील इंदौरा: उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि जो हमने भुगता वह ये लोग न घुसते। (शोर एव व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे साथी भुगतने की बात कर रहे हैं इस बारे में मैं सदन को बताना चाहूंगा कि भुगतने का तो इनके यहाँ रिकार्ड है कि किस तरह से पिछली सरकार के समय मे मन्त्रियो को और विधायकों को तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर ले जा करके उनके हाथ–पांव तोड़े जाते थे।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा): उपाध्यक्ष महोदय, मे मेरे विपक्ष के साथियो को आश्वासन देता हूं कि हमने पिछली सरकार के समय मे जो भुगता था, वह अब विपक्ष के साथियो को नहीं भुगतना पड़ेगा। इनको बोलने के लिए पर्याप्त समय दिया जायेगा। अब ये चिंता न करें। जितना ये बोलना चाहे उतना बोल लें।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक: उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के विधायक चौटाला साहब को भगवान के बराबर कहते थे और डाक्टर इंदौरा जी ने तो उन्हें भगवान से भी ऊपर कहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सोनीपत जिले के उस समय के विधायको की बात बताना चाहूंगा कि इनकी सरकार के समय में एक मास्टर

इनके विधायक के पास गया कि मेरा तबादला करवाओ। वह विधायक विभागीय अधिकारियो के पास तबादले के लिए गया। अधिकारियो ने कहा कि तबादले तो बंद हैं और मुख्यमंत्री ही तबादला कर सकते हैं। मास्टर जी ने विधायक को कहा कि मुख्यमंत्री जी के पास चलते हैं। मैं विधायक का नाम नहीं लूंगा लेकिन उस विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री जी तो भगवान हैं और भगवान के पास जो कोई चला जाता है तो वह वापिस नहीं आता। (हंसी) उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि अपने नेता की प्रशंसा करो लेकिन प्रशंसा उस हिसाब से करो कि सुनने वाले को भी ठीक बात लगे। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारी तो यह बदकिस्मती है कि चोटाला साहब यहां नहीं बैठे हुए और हम अपने दिल के अरमान उन्हें नहीं कह सकते तथा इंदोरा साहब, आपकी बदकिस्मती यह है कि जैसा रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कहा कि आप ऐसा केस लड़ रहे हैं जिसके न तो फैक्टस सही हैं और न ली सही है। लेकिन मैं मुद्दे पर आना चाहता हूं। उपाध्यक्ष जी, माननीय चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने बजट पेश किया है। यह बजट बहुत ही सरल और सिम्पल बजट है यह बजट ऐसा कम्पलीकेटिड बजट नहीं है जिसके अन्दर कोई उल्ट फेर हो। सीधे–साधे आम आदमी का जो बजट होता है उस किस्म का यह बजट है और केवल 51 करोड़ 67 लाख का मामूली घाटा इन्होंने दर्शाया है। इन्कम कैसे होगी, खर्च कैसे होगा यह सब इसमें दिया हुआ है। मेरी समझ मे यह बात नहीं आई कि माननीय आपोजीशन के सदस्य किस ढंग से बजट का विश्लेषण कर रहे हैं और यह कह

रहे हें कि इसमे यह ठीक नहीं है इसमे वह ठीक नहीं है। इस बजट के अन्दर दोनो मद बहुत ही साफ तरीके से दिए हुए है। खर्च और आमदनी का भी इसमे पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। बजट का दूसरा और कोई तरीका होता ही नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रदेश की तरक्की के लिए दो ही रास्ते हैं एक तो खेती और दूसरा उद्योग। इन दोनों को प्रोत्साहन देने के लिए इस बजट के अन्दर पूरे ढंग से पैसे का सिस्टम बनाया हुआ है। खेती के लिए जमीन को बढ़ाया नहीं जा सकता उसके लिए पानी के साधन की जरूरत है। पानी के बारे में मैंने 9 तारीख को कहा था। इन लोगों को इस चीज को महसूस नहीं करना चाहिए। कोई भी माननीय साथी कहीं से भी एम०एल०ए० बन कर आया हो जो लड़ाई हम 40 साल से पंजाब से लड़ रहे हैं वहीं लड़ाई हमें अपने हरियाणा के साथियों के साथ भी लडनी पड़ रही है, यह कितनी बुरी बात है? हम कहते हैं कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है और हम छोटे भाई हैं उन्हें न्याय करना चाहिए लेकिन यहां पर अपने ही प्रदेश मे हम लोग पानी के बराबर वितरण को लेकर ठीक ढंग से नहीं चल पा रहे हैं। प्रदेश का मुख्यमन्त्री प्रदेश की सरकार का मुखिया होता है और उसके लिए सारा प्रदेश बराबर होता है। अगर किसी हल्के से सत्तादल का एम०एल०ए० नहीं भी है तो भी उस इलाके के साथ उन्हें न्याय करना पड़ता है, यह उसकी डयूटी है। लेकिन इन्होने इस बात को माना ही नहीं कि पानी के बंटवारे के अन्दर कोई भेदभाव है, कोई इम्बैलैन्स है। उपाध्यक्ष महोदय, कप्तान साहब बैठे हुए हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। बार–बार

अखबारों ने भी इस बात को दिया है कि इन्होंने इस चीज को माना है कि पानी के बंटवारे मे भेदभाव हुआ है। यह भेदभाव थोड़ा सा नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं, कि अगर इसके फैक्टस देखें जाएं तो हैरानगी होती है कि जो टोटल पानी हमें मिलता है वह हमें एक तो मेन भाखड़ा लाईन से मिलता है और दूसरे हमें यमुना वाटर सर्विस सिस्टम से पानी मिलता हे। कुछ ऐरिया मे हमे लिफ्ट कैनाल से भी पानी मिलता है। महेन्द्रगढ़, भिवानी, रिवाड़ी और गुडगाव के एरियाज में जो भाखड़ा मेन लाईन सिस्टम की सप्लाई है वह हरियाणा का केवल 4090 हिस्सा है, 6090 हिस्से की सप्लाई यमुना वाटर सर्विसिज सिस्टम से है और यमुना वाटर सर्विस का पानी 60% भाग के लिए केवल 2.4 से 3.01 है। 60% हरियाणा की खेती की जमीन के लिए 2.4 से 3.01 हैं और 40% भूमि के लिए जो पानी अवेलेबल है वह 4.29% से 8.0 है, मतलब यह है कि 70% पानी का फर्क है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर थोड़ा बहुत अन्तर हो तो बात समझ में आती है। 70% पानी का जो उनका हक है उससे ज्यादा पानी उनको रजा रहा है लेकिन यहां पर पूरा पानी नहीं आ रहा है। इस इलाके के साथ भेदभाव है। जिस इलाके के साथ अन्याय है उस इलाके की जमीन भी थोड़ी है होल्डिंग भी छोटी है और पानी नहीं है। में तो यह कहूंगा कि हरियाणा में जो क्राईम बडा है वह सरकारों ने जो ज्यादती की है, इस कारण से ही बढ़ा हैं। एक बी०ए० पास लड़के को अगर रोजी रोटी मिल जाए तो वह क्राईम नहीं करना चाहेगा। उनके लिए तो सारी चीज मजबूरी हो गई हे। एक–एक एकड़ की

होल्डिंग हो गई है। मंत्री जी ने इस इलाके के साथ एक नई लिंक कैनाल बनाने के लिए अपनी प्रपोजल तैयार की है। मैं समझता हूं कि कप्तान साहब बहुत जल्दी इस पानी को इस इलाके मे लेकर आएगे। बहुत सारा फर्क तो सरकार की मंशा से पड़ जाता है। आम आदमी को जब हम बताते हैं कि ये हालात थे तो वह अफसोस मनाता हे कि हो क्या रहा था। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे इलाके नहरों मे 32 दिनो के बाद 16 दिनों की बजाए केवल 8 दिन ही पानी आता था और दूसरे इलाकों मे 32 दिनों के बाद 16 दिनो की बजाए श्य दिन पानी आता था। इस सब के बावजूद वहां पर झगड़े होते थे। आज हमारे इलाके मे जो मुख्य समस्या है वह टेल की है। मैं वहां के किसानों की बात खासतौर पर बता रहा हूं कि जितनी भी नदी नालों की टेले हैं वहां पर रोज किसानो के झगड़े होते हैं। मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि वहां पर ये यह सुनिश्चित करे कि पानी टेलों पर पहुंचे क्योकि पानी की चोरी की वजह से टेलों तक पानी नहीं पहुच पाता है उस पर भी चौक लगे। आप वहां से ब्यौरा मंगवा ले कि कितने केसिज ऐसे हैं जो पानी की वजह से झगड़े के कारण हुए हैं तो आपको ज्यादातर केसिज उन्हीं के मिलेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि कृ षि की और उद्योगो की वजह से प्रदेश की उन्नति हो सकती है इसके अलावा कोई तीसरा साधन नहीं है। हम पार्लियामैंट में भी बहुत शोर करते थे कि बड़ी इण्डस्ट्रीज हरियाणा में लगाई जाएं। तो इस विषय मे एक ही जवाब आ जाता था कि जो नैशनल

कैपिटल रीजन है उसमें बड़ी इन्डस्ट्रिज नहीं लग सकती है। स्पीकर सर, राई मेंएक इन्टरनेशनल सब्जी मंडी बनाने का प्रस्ताव था उसके लिए जमीन भी एक्वायर हो गई थी और उसकी चार दीवारी भी हो गई थी। वहां पर 20 हजार लोगो को रोजी रोटी मिल सकती थी लेकिन हरियाणा में चौटाला साहब की सरकार आ गई। डिप्टी स्पीकर सर, छोटी–छोटी होल्डिंग के जो किसान हैं वे सब्जियां उगाते हैं। जो सब्जी हिन्दुस्तान में 50 रुपए किलो है उसके बाहर विदेशो में ड्राई एरिया होने की वजह से 500 रुपए किलो के दाम मिलते हैं। चौटाला साहब ने आकर एक ही लाईन मे सारी बीमारी का इलाज कर दिया, जो दिल्ली की बीमारी थी, जो दिल्ली के रिहायशी इलाकों मे छोटी–छोटी इण्डस्ट्रीज थी जिनको हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस देकर यह कहा था कि उन इण्डस्ट्रीज को दिल्ली से बाहर निकालो क्योकि ये दिल्ली मे पोल्युशन फैलाती हैं, उनको चौटाला साहब ने हरियाणा में बुला लिया कि यह बीमारी हमको दे दो। उन्होंने वहां से उस मण्डी को कैंसिल करके इन इण्डस्ट्रीज को कहीं दो सौ गज का और कहीं पर तीन सौ गज का प्लाट दे दिया। डिप्टी स्पीकर सर, वह मण्डी भी गई और वहां पर इण्डस्ट्रीज भी नहीं लगी। यह तो सरकार की मंशा की बात है कि वह किस ढग से काम करेगी। लेकिन इस पांच साल के असे मे यह नहीं है कि हम आलोचना के लिए आलोचना करना चाहते है। ये खुद अपने दिल पर हाथ रख कर देंखें क्योंकि लोगों का फैसला कभी गलत नहीं होता है। एक आध केस में गलत हो सकता है। लेकिन पिछली सरकार का तो

बुरी तरह से जनता ने सफाया कर दिया। यह आम तौर पर यूं ही नहीं होता है इसका कोई न कोई कारण जरूर होता है। (विघ्न) 1996 में हमारी ही कोई कमी रही होगी तभी हमारी सरकार नहीं आयी। विधायक जी, किसी भी घटना के बगेर ऐसी चीज नहीं होती है। मेरी भी कोई कमी रही होगी, मेरी सरकार की कोई कमी रही होगी, उसको आज हम छिपाएं और लोगों को बुराई दें कि लोगों का निर्णय गलत है तो ठीक नहीं है। जो डैमोक्रेटिक सैटअप की हाईएस्ट अथोरिटी है हम उनको गलत कैसे बता सकते है? उनका निर्णय हमेशा सही होता है और हमें उनके निर्णय को मानकर चलना चाहिए। हमने तब भी उनके निर्णय को सिर माथे पर रखा था लेकिन आप तो आज भी नहीं मान रहे हैं और यहा पर बैठे–बैठे कुचर–पूचर करते रहते हैं। (विघन) हम तो खुद मानते हैं लेकिन आज भी इनके अंदर यह बात मानने की हिम्मत नहीं है कि ये चौटाला साहब की गलती को उसके सामने कह दे इसीलिए ये लोग मरे हैं। डिप्टी स्पीकर साहब जिस राजा से उसका डाक्टर या उसके दोस्त डरने लग जाते हैं उसका तो हमेसा नाश ही होता हे क्योकि डाक्टर या साथी तो उसको ठीक ही सलाह देते हैं। (विघ्न) हमारे एक भाई जिनका मैं नाम नहीं लूंगा पिछली बार विधायक थे। डांगी साहब भी उनको जानते हैं उनका हाथ तोड़ दिया गया था जब वह मुझे मिले तो मैंने कहा कि सुना है कि चौटाला साहब के लड़कों ने आपका हाथ तोड़ दिया है वह कहने लगे कि सुना तो मैंने भी है यानी उनकी यह हिम्मत नहीं थी कि वह कह दें कि मेरा हाथ तोड़ा गया है मतलब

कहने का यह है कि उस समय कोई भी आदमी चौटाला से खुश नहीं था। ये लोग भी उस समय चूप रहते थे क्योंकि इनकी मजबूरी थी। आज भी इनकी मजबूरी है यह बात मैं मानता हूं। लेकिन इस सरकार में वह बात नहीं है आज हर एक आदमी को पूरा अधिकार हें कि वह अपनी मर्जी से अपनी बात कहे। जो यह बजट पेश किया गया है यह बहुत ही सराहनीय है क्योंकि इसमे कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है ओर ठीक ढंग से संतुलित करके विकास के लिए पैसा बढ़ाया गया है। किसी प्रकार का कोई विशेष घाटा इसमे नहीं दिखाया गया है और जो थोड़ा बहुत घाटा दिखाया भी गया है वह ऐडमिनिस्ट्रेशन को चुस्त दुरूस्त करके पूरा किया जाता है। कोई गलत बात बजट में नहीं कही गयी है। इसलिए मैं इस सरकार को, मुख्यमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को इसके लिए मुबारिकवाद देता हूं। सारे हरियाणा में इस बात की बहुत ही बढ़िया प्रतिक्रिया आयी है। कि सरकार ने बहुत ही अच्छा बजट बनाया है। डिप्टी स्पीकर सर, मैं एजुकेशन के बारे में कहना चाहूंगा। मुलाना साहब यहां पर बैठे नहीं हैं। एजुकेशन में जो आज स्थिति है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। हम जब धन्यवादी दौरे पर जहां–जहां गए तो हमने देखा कि हर गांव मे एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जहां स्कूल में स्टाफ पूरा हो। यदि हम गलती टीचर्ज की बता दे तो फिर ठीक नहीं होगा। मेरे हल्के मे शामडी गांव है यह बहुत बड़ा गांव है और इसमे तीन पंचायत है। इस गांव मे एक प्लस दु का स्कूल है। जब हम इसमे गए तो हमने देखा कि उस स्कूल मे केवल एक ही लैक्यरर है।

जिस तरह से मेड बकरियो को रोके रखते हैं उसी तरह से उस स्कूल मे बच्चों को वह लेक्चरर रोके रखता है। इसके बाद यदि हम यह कहें कि रिजल्ट खराब क्यो आया तो यह ठीक नहीं है। जिस प्रदेश में शिक्षा ठीक होगी, लोग शिक्षित होगे वहां पर उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा इसलिए सबके लिए शिक्षा का प्रावधान करना हमारी डयूटी है। मेरी शिक्षा मंत्री से प्रार्थना है कि प्राथमिकता के आधार पर स्कूलो में टीचर्ज नियुक्त होने चाहिएं। आई०ए०एस० या एच०सी०एस० मे तो सिफारिश चल सकती है लेकिन डाक्टर्ज, ड्राईवर्ज या मास्टर्ज में कभी सिफारिश नहीं चल सकती हे क्योकि इनके हाथों में दूसरो की जाने होती हें। जो आदमी खुद ठीक नहीं होगा तो उससे दूसरो को नुक्सान ही होगा। इसलिए हमारी शिक्षा को ठीक ढंग से आगे बढ़ाने के लिए बढ़िया किस्म के टीचर्ज की भर्ती करना जरूरी है। आज सारे स्कूलो की बिल्डिंग्ज खराब हैं उनके लिए भी बजट मे जो प्रावधान किया गया है तो मैं समझता हूं कि उससे भी काफी सुधार होगा। इसी तरह से होस्पीटल्ज की बात है चाहे वेटैनरी होस्पीटल्ज हो या सिविल होस्पीटल्ज हो, उनमें भी डाक्टर्ज की कमी है। मैं एक जनरल बात कहना चाहता हूं क्योंकि जितने शहरो के नजदीक स्कूल्ज हैं या वैटनरी हॉस्पटिल्ज हैं, सिविल डिस्पैंसरीज हैं वहां तो सरप्लस स्टाफ है लेकिन जो शहर से दूर हैं वहां मास्टर नहीं है और डाक्टर नहीं हैं। इसलिए भर्ती के समय कोई न कोई कंडीशन इस किस्म की रखी जाए कि इतनी नोकरी तो देहात मे करनी ही करनी है। हम मशरूम ग्रोथ की तरह स्कूल अपग्रेड करते

जा रहे हैं आज से 15 साल पहले में इंग्लैंड में गया था। मैं उस समय वहां ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मे भी गया था। वहा मुझे इंडियन स्टूडेंट्स भी मिले जिनकी पुश्ते दो सौ साल पहले वहां माइग्रेट करके गई थीं। उन्होने हमें बताया कि पिछले कई सालो से न तो हमने कोई नया स्कूल खोला हे न कोई स्कूल अपग्रेड किया हे। वे कहते हैं कि नया स्कूल इसलिए नहीं खोला क्योंकि आबादी नहीं बढ़ी। और अपग्रेड इसलिए नही करते है कि वे कहते हैं प्राइमरी एजुकेशन तो सबको मिले लेकिन हायर एजूकेशन केवल उन लोगो को ही मिले जो उसके काबिल हो। हम कन्वोकेशन में देखते हैं कि वहां गाउन पहनाते हैं। जो एम०ए० कर लेते हैं उनके लिए डिफरैंट ड्रेस है। इसका मतलब यह है कि यह आदमी बहुत बढ़िया है, चरित्रवान है अगर किसी गलत काम मे फंस जाए तो उसकी डिग्री भी विदड्रा हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि एजुकेशन पर हमे यहां पर जोर देना पड़ेगा। तबादलो के लिए तीन महीने हो गए हैं लोग हमारे पीछे भाग रहे हैं हम उनको बहकाते हैं। वे पूछते हैं कि तबादले कब होगे, अब हमने कह दिया है कि 20 तारीख के बाद होगे। हम लोगों से पैंडा छुड़वाते फिर रहे हैं। ट्रांसफर के जिए हमें बाकायदा कोई न कोई परमानेंट पॉलिसी बनानी चाहिए वरना लोग हमसे नाराज होंगे। इसलिए भर्ती के समय यह कंडीशन जरूर लगाई जाए कि इतनी सर्विस कम से कम देहात मे जरूर होनी चाहिए। वह नहीं होगी तो हमारे लिए परेशानी की बात आ जाएगी। इस बात के लिए सरकार बधाई की पात्र है कि किसानो

के लिए सरकार ने जो वायदे अपने घोषणा पत्र में किए थे उनको पूरा करने के लिए सरकार ने शुरुआत की है। उस समय घोषणा पत्र बनाने वाली कमेटी मे मैं भी मैंबर था। जो घोषणा पत्र में किसानो से वायदे किये थे, उनको पूरा करने के लिए सरकार ने शुरूआत की हुई है। उनमे से कुछ वायदे इम्प्लीमैंट हुए हैं जैसे ट्रैक्टर की रजिस्ट्रेशन फीस सरकार ने खत्म कर दी है। चौटाला साहब कहा करते थे कि में किसानों का चीफ मिनिस्टर हूं लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए बल्कि उन्होने वह फीस बढ़ा दी थी। हमारी सरकार ने आते ही वह फीस खत्म कर दी है। 1947 के बाद से मैंने किसी के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलता नहीं सुना है। अंग्रेजों के टाइम में तो केसिज प्रीवि कौंसिल तक जाते थे। 1947 के बाद मैंने तो कोई ऐसी रूलिंग नहीं देखी कि जहां किसी हिन्दुस्तानी पर राजद्रोह का मुकदमा चला हो, लेकिन चौटाला साहब ने अपने साथी जिनके कंधे पर ये बंदूक रखकर चलाते थे उनके खिलाफ ही देशद्रोह के मुकदमें दायर कर दिए। मान साहब यहां बैठे हुए हें इनकी क्या गलती थी? इनके खिलाफ भी पूरा तूफान खड़ा कर दिया और गलत मुकदमे बनाये गये। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि किसानो के ऐसे–ऐसे केसिज थे कि ओलावृष्टि में मुआवजे में कितना पैसा मिला कि एक रुपया दिया था, उसमे से भी कह रहे थे कि 12 आने लौटा दो और चार आने ले जाओ तो यह हालात थी। यह ठीक है कि गिरदावरी करते वक्त नीचे के एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर छोटी मोटी कमी रह जाती है लेकिन यह सरकार आने के बाद किसानों की मुआवजे की राशि

को बढ़ाया गया है। उनको मुआवजा मिला भी है। एक आध जगह कमी आई है। मेरी कान्सटीच्यूएंसी के गांव खानपुर, गामड़ी और चार–पांच दूसरे गावों मे पटवारी की कमी पाई गई थी इसलिए उसको सस्पैंड किया गया। उसने क्या किया कि औलावृष्टि में गेहूं की फसल भी 50 प्रतिशत खराब और सरसों की फसल भी 50 प्रतिशत खराब दिखा दी जबकि सभी लोग जानते हैं कि सरसों की फसल पर तो एक ओला लगते ही सारी झड़ जाती है। इसलिए यह तो सैंट–परसेंट खराब हो गयी। इस तरह से यह क्लीयर जाहिर हो गया कि गिरदावरी गलत की गयी है। इसलिए एक दम एक्शन लिया गया और अब यह ठीक होने की उम्मीद है। बहुत सारी बाते हैं जैसे मॉडल स्कूल खोलने की बाते बहुत से साथियों ने कहीं है, मै उनको रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन एक चीज मैं कहता हू कि हमारी पापुलेशन देन कन्ट्रोल के लिए हमें सोचने की जरूरत है। पापुलेशन की स्थिति इतनी गम्भीर है कि अगर इस को ढंग से नियंत्रित नहीं किया गया तो बडा नुकसान हो सकता हे। मैंने आकडे देखे हैं। 1951 में हरियाणा की हमारी जनसंख्या को देखें तो एक किलोमीटर वर्ग एरिया मे 128 आदमी रहते थे और आज 478 आदमी रहते हैं जबकि अमेरिका मे 30 आदमी रहते हैं, कनाडा में 3 और चाईना बनैसे देश मरे जिसे ज्यादा आबादी वाला देश कहते हैं, वहां 133 आदमी रहते हैं। आज हमारी जो प्रोग्रेस है, डिवलैपमेट हे उसको आबादी खा जाती है इसलिए विकास के साथ–साथ इस संबंध में भी हमे थोडा ध्यान देने की जरूरत हे। मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि देहात की जो

जमीन है वह तो बढ़ नहीं सकती। लेकिन उसका इण्डस्ट्रिलाईजेशन किया जा सकता है। देहात की जमीन का इण्डस्ट्रिलाईजेशन होगा तो उससे वहां रोजगार के अवसर बढेगे। जितना हम देहात में होस्पिटल और स्कूलो का दायरा बढायेगे उतना ही जो देहात के लोगों कां पलायन शहरो की तरफ हो रहा है वह नहीं होगा। पलायन का कारण यह है क्योंकि देहात मे वे फैसिलिटीज नही मिल पाती जो शहरों में मिलती है। अगर देहात का शहरो की तरफ पलायन रोकना है तो देहात में सारे इन्फ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जाये। देहात के लोगो को वे सारी फैसिलिटीज दी जायें जो शहरों में हैं ताकि बैलेस बना रहे। इससे जो मुलाजिम शहर की तरफ दौडते है वे भी कम होगें इस तरह से टोटल पलायन रूक जायेगा।

श्री उपाध्यक्षः मलिक साहब, वाईंड अप कीजिए।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिकः उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अपनी कान्स्टीच्यूएन्सी की बात जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि फिर पता नहीं बोलने का मौका मिले या न मिले। कई बाते हैं लेकिन सभी बातें सारे स्टेट से संबंधित हैं। लोग हमे कहते हैं, हम आपको बताते हैं इस तरह से ये बातें सरकार तक पहुंच जाती हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि गांव में आबादी मे छोटे–मोटे झगड़े चलते रहते हैं चूंकि मैं तो वकील रहा हूं इसलिए मुझे पता है कि जिसके पास लाठी है वह जबरदस्ती गतवाड़े पर घर पर कब्जा कर लेता है ओर फिर कहते हैं कि सबूत क्या है कि जी सबूत क्या

होगा हम तो कदे तैं यहीं रहा करते थे। उनका एक परमानेन्ट रिकार्ड आबादी देह है, उनके नक्शे हैं। चौधरी बंसीलाल जी जब पहले मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने इस बारे एक कार्यक्रम बनाया था परन्तु वह फाईनल नहीं हो पाया। ऐसे कार्यक्रम को टाईम बाउंड प्रोग्राम किया जाये ताकि लिटीगेशन का काम कम हो। देहात के आदमी के पास जमीन नहीं है उसके पास केवल एक घर है लेकिन वह उस घर को रहन नहीं रख सकता और इसलिए वह बैंक से लोन नहीं ले सकता क्योंकि उसके पास उस घर के कागजात नही है। सब आदमियो के पास एग्रीकल्वर लैंड नहीं होती वे लोन लेने के लिए बेचारे धक्के खाते हैं, बैंक वाले उन्हें एक्सप्लायट करते है कि तेरे कागज मे यह कमी है, वह कमी है. तू ये ले आ. वह ले आ। इसलिए टाइम बाउंड प्रोग्राम करके 6 महीने के अन्दर सबकी अपील शपील निपटा दी जाएं। सबके हाउसिज के बकाया नक्शे बन जाएं और उस नक्शे की अटैस्टेड कापी जिस प्रकार से जमाबदी, खसरा और गिरदावरी की कापी तहसील में होती है। उसी प्रकार इनकी कापी भी तहसील में, बी०डी०ओ० के दफ्तर मे और गांव के संरपच के पास हो ताकि सारी परेशानियों दूर हो सकें और ठीक ढंग से काम हो सके। अब रजिस्ट्री करवाते हैं तो गोल मोल करवाते हैं उनकेन कोई एरिये का पता है और न उसका कोई खसरा नम्बर है ऐसे ही गाड़ी चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, हम बहुत दिनों से आस लगाए बैठे थे और आम आदमी भी यह समझता था कि एस०वाई०एल० कैनाल का पानी आएगा और गाड़ी चलेगी। लेकिन एस०वाई०एल० केनाल

के पानी ने लोगो को प्यासा मार दिया क्योकि पानी आज तक नहीं आया। वह पानी आए, इसके लिए हमारी सरकार पूरे ढंग से कोशिश कर रही है और वह पानी मिलेगा। इसके साथ– साथ जो दृ॒सरे साधन हैं जैसे और रजवाहे तैयार कराए जा सकते हैं, जैसे यमुना का पानी है, जहां केसाऊ बांध है जब तक इन साधनों को बाकायदा यूटीलाइज नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी मैं तो यहां तक कहूंगा कि यमुना को पक्का करें ताकि 35 प्रतिशत पानी सेव हो जाए। जैसा कि इरीगेशन डिपार्टमेंट के लोग कहते हे कि अगर यमुना को पक्का कर दिया जाए तो 35 प्रतिशत पानी की सेविंग हो सकती दै और हम उस पानी को यूटीलाइज कर सकते हैं। अगर ऐसा नही होगा तो बरसात का पानी आएगा और समुद्र में चला जाएगा इसलिए इस पानी को सेव करने के लिए आपको रजवाहे बनाने पड़ेंगे। इस में पानी को रोंके तब यह सिस्टम कामयाब हो सकता है वरना थोड़ा दबाव देंगे तब तो पानी आ जाएगा। थोडी सफाई करवाएंगे, थोड़ा डंडा चलाएंगे और अगर पानी की चोरी नहीं होगी तब तो पानी आ जाएगा और पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन इसका परमानैंट हल डैम बनाने से है। इसके साथ साथ व्यास नदी पर पौंग और पडोह दो डैम बनाने की बहुत पुरानी प्रक्रिया बहुत लम्बे अर्से से पैण्डिंग है उसको टाइम बाउंड प्रोग्राम के तहत कम्पलीट करें ताकि उससे लोगों को इमीडिएट लाभ हो और लोगों को नजर आए कि यह काम कर दिया गया है। इसके साथ–साथ बिजली के बारे में मैं कहना चाहता हूं जब बिजली हरियाणा मे आई, मेरे ख्याल से

1970– 71 में सारे हरियाणा के अन्दर इलैक्ट्रिफिकेशन हुआ था लेकिन उसके बाद से खम्भे और तारे आज तक नही बदली गई और वे यूं कि यूं चल रही हैं। जिसके कारण दुर्घटनाए होती हैं। तार बहुत नीचे आऐ हुए हैं। एक–एक गांव का जिक्र करना यहां मुनासिब नहीं हे लेकिन यह बहुत जनरल बात है। बहुत लम्बा आदमी हो तो उसके हाथ इन तारो तक चले जाएंगें। खम्भे इतने टूटे हुए हैं कि लोगो ने लकड़ी बाध कर उनको स्पोर्ट दी हुई हैं इसलिए इनको बहुत ही जल्दी बदलवाया जाए क्योकि इससे बहुत दुघर्टनाएं हो जाती हैं, मवेशी मर जाते हें। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस मामले में बहुत इमीडिएट स्टैप उठाने की जरूरत है। उपाध्यक्ष महोदय, एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि गांवों की आबादी बहुत बढ़ गई है, मेरी कास्टीच्यूएंसी में 7–8 गांव ऐसे हैं जहां हाई टैंशन वायर मकानों के ऊपर हैं।

Mr. Deputy Speaker: Malik Sahib, please wind up. Please take your seat.

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक: उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी कांस्टीच्यूसी की बात जरूर कहना चाहूंगा। टयूबवैल के केबल कनैक्शन के लिए चौटाला साहब ने 20 हजार रुपये फिक्स कर रखे थे और 7 हजार रुपये प्रति खम्मा फिक्स कर रखे थे तथा 2 हजार रुपये सिक्योरिटी के लिए फिक्स कर रखे थे। वह सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भी नहीं थी बल्कि नम्बर दो की ब्लैक मनी थी। वह न सिक्योरिटी थी और न उसका कुछ और नाम था।

उसको वैसे ही जमा करवा लेते थे इसलिए उसको भी हटवाया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के की कुछ बातों का जिक्र आपके माध्यम से यहा करना चाहूंगा। जो बहुत जरूरों हें। मरे हल्के का ज्यादातर इलाका देहात का हें और कैप्टन साहब के सिंचाई विभाग से संबंधित हैं। मेरे हल्के में मोईहुडा माईनर है जिसकी लम्बाई को 450 फिट आगे बढ़ाना है उसकी वायबिल्टी सा है और इस बारे में सर्वे भी कर लिया गया है। वहां आगे रोड आ गई है उसके बीच से यह माईनर निकालना है। इसके अलावा एक रिठाल डिस्ट्रीव्यूट्री एक्टैंशन की कैपेसिटी और लम्बाई को बढ़ाना है। रिठाल डिस्ट्रीव्यूट्री आलरेडी है। लेकिन रिठाल डिस्ट्रीव्यूट्री एक्सटेंशन उसी में से निकाली गई है उसकी थोड़ी सी लम्बाई को बढ़ाने से घीलोड और आवली गांवो मे पानी जा सकेगा ' उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से घीलोड माईनर में जो बैरल सिस्टम लगाया हुआ है। उसके बारे मे विभागीय अधिकारी यह कहते हैं कि बैरल सिस्टम जब तक रहेगा आगे पानी नहीं जायेगा क्योंकि बैरल सिस्टम में गाद जम जाती है और पानी ठीक ढंग से फलो नहीं करता इस कारण टेल तक पानी नहीं पहुचता। विभागीय अधिकारी बताते हैं कि टेल तक पानी तभी पहुचेगा जब ट्रोफ (trough) सिस्टम लगेगा। इसलिए घीलोड माईनर पर आर०डी० 219 पर trough सिस्टम लगवाया जाये और उस माईनर की सफाई भी करवाई जाये तथा जो किनारें टूटे हुए हैं उनकी रिमोडालेंग भी की जाये। मेरे हल्के के लाठ गांव के रकबे के लिए भालोठ सब ब्रांच की आर०डी० 53 से पानी जाता है। उसमें से पहले गांव

वाले पानी की चोरी करते हें जिसके कारण उस गांव में पिछले कई सालो से पानी नहीं गया है। मेरे गांव से डेढ़ कि०मी० की दूरी पर लाठ गांव है उस गांव के लोग कहते हैं कि पिछले 50 सालों से एक बूंद पानी भी उनके यहां नहीं आया है। इस लिए इन गांवों के लिए भी पानी का उचित प्रबन्ध किया जाये। इसके अतरिक्ति जो सिकन्दरपुर माजरा माईनर कप शेप में बनाया हुआ है उसको कप शेप के स्थान पर वर्टीकल वाल शेप में बनाया जाये। जब तक इसका सैसान वर्टीकल वाल मे नहीं बनेगा और पानी की चोरी नहीं रूकेगी तब तक आगे पानी नहीं जायेगा। इसलिए इस तरफ भी कैप्टन साहब ध्यान दे। इसके अतिरिक्त कटवाल माईनर की रिमोडलिग करके उसकी कैपेसिटी भी बढ़ाने की आवश्यकता है। इसकी कैपेसिटी बढ़ाने से भैंसवाल कलां जो कि बहुत बड़ा गांव है, उसको फायदा होगा। इसके अलावा भैंसवाल कलां गांव में फरमानाकला माईनर है, भाई सुखबीर सिंह जी बैठे हुए हैं उनको भी पता है कि उसकी भी रिमोडलिग करने की आवश्यकता है। वह माईनर इनके गाव तक भी जाता हैं। इसकी रिमोडलिग होने से भैंसवाल कलां और फरमाना कलां दोनो गांवों की पानी की भरपाई हो जायेगी। इसके अतिरिक्त सरगथल माईनर भी दो बुर्जी आगे बढ़ाया जाये और गुहणा माईनर की कैपेसिटी 32 क्यूसिक से 38 क्यूसिक की जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मै मत्री जी को बताना चाहूंगा कि यह सब मैं पूरी स्टडी करके बता रहा हूं ताकि कंक्रीट ढंग से बात हो। वैसे कहेगे तो बात नहीं बनती। इसके अतिरिक्त खूबडू से इसराना डिस्ट्रीव्यूट्री है जिसमें पिछली

सरकार के समय मे 2० प्रतिशत अतिरिक्त पानी छोड़ने का प्लान बनाया गया था और इस डिस्ट्रीव्यूट्री पर एक करोड़ रुपये खर्च किये गये थे लेकिन आज तक पानी नहीं पहुंचा और वे लोग एक करोड़ रुपये भी खा गये। (विघ्न) इसी तरह से एक रामगढ़ माईनर है। रामगढ़ माईनर मन्जूर की गई है यह 15 गांवों में पानी देगी। लेकिन हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि यह माईनर मन्जूर हुई पड़ी है। यह माईनर केवल मन्जूर ही मन्जूर है मौके पर वह बनी नहीं है इसलिए इसको इम्पलीमैंट करने की बात है। इस तरह से भी बहुत सी इम्पोर्टेन्ट चीजे हैं। कप्तान साहब, मेरी कास्टीचयूएंसी के ऐरिया में हमें जो पानी मिलता है वह दो जगह से मिलता है एक तो भालोठ सब- ब्रान्च है ओर दूसरे जे०एल०एन० फीडर है। जे०एल०एन० फीडर का पानी तो आता है गोहाना सें लेकिन उसका एस०डी०ओ० पानीपत मे बैठता है। (विघन) बहन जी, आप वाला भी वहां पर इसराना में गड़बड़ करता है यह सही बात है। लेकिन असली बात यह हे कि वहां पर पानीपत के अन्दर दो एस०डी०ओज० हैं। गोहाना के अन्दर जे०एल०एन० फीडर का कोई काम होता है तो लोग गोहाना से पानीपत जाते हैं जबकि उनका ऐरिया गोहाना का है। यह बात समझ में नहीं आई कि उनको उल्टा पानीपत किस लिए भेजते हैं जबकि पानीपत के लिए अलग एस०डी०ओ० हे। इसलिए मेरी आपके माध्यम से इरिगेशन मिनिस्टर महोदय से प्रार्थना है कि जे०एल०एन० फीडर का जो एस०डी०ओ० पानीपत मे बैठता है उसका ऑफिस गोहाना मे शिफ्ट किया जाए ताकि वह वहां पर

सारे सिस्टम को ठीक रख सके (विघन) उपाध्यक्ष महोदय, में सड़को के बारे मे एक बात कहना चाहता हूं। सड़कों का बहुत बुरा हाल हे। हम यह सुनते थे दिन चौटाला साहब पता नहीं बैंक ‘से पैसा लेकर आएंगे या कहीं और से पैसा लाएंगे और सड़कों का काम करेगे। उनकी सरकार तो चली गई लेकिन सड़कों का कोई काम नहीं हुआ है। सड़कों की हालत इतनी खराब है कि सड़को में खड्डे नहीं हैं बल्कि खड्डो में सडक है। हमारे यहां की सड़कों की हालत बहुत बुरी है। पता नहीं उस ऐरिया को खासतौर से छांट रखा था। (विघ्न) जैसे कोई गांव नेशनल्न हाईवे पर पड़ता हो तो दूसरी बात है लेकिन हमारे यहां पर जनरली सड़् कों की वर्स्‌ट कण्डीशन है। 4—5 रोड्‌ज तो ऐसी हैं जो 1994 में मन्जूर हुई थीं लेकिन अभी तक बन्की नहीं। 1994 मे भेंसवाल से तिहाड सड़क मन्जूर हुई थीं लेकिन उसके बाद हमारी सरकार चली गई थी। परन्तु यह सड़क भैंसवाल सीमा तक तो बन गई लेकिन आगे तिहाड़ तक काम पूरा नहीं हुआ और वह सड़क यूं की यूं ही पड़ी हुई है। (विघन)

श्री उपाध्यक्षः मलिक साहब, अब आप अपनी सीट पर बैठें।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिकः उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दो—तीन बाते ओर कहनी हैं। उसके बाद मैं आपको दोबारा सारे सैशन मे तंग नहीं करूगा और मेरे सारे मामलों की छुट्‌टी हो जाएगी। इसमे एक बात तो यह है कि वह सड़क बीच मे बननी

छोड़ रखी है। वह सड़क गांव की सीमा तक तो बनी हुई है और सड़क आगे भी मन्जूर है लेकिन वह 1112 साल से बनी ही नहीं यानि क्री यूं कि यूं ही पड़ी हुई है। इसलिए इसको बनवाया जाए। एक सड़क लात गांव से गुहणा वाया भैंसवाल बननी है वह भी नहीं बनी, वहां पर भी शुरू से ही इस किस्म की बात है। मेरा नस निवेदन है कि वह सड़क शीघ्र बनाई जाए। न्यात से गामडी, मोई हुडा से काहनी, बिधल से जौली और कैलाना खाल से खानपुर तक सड़क बननी हैं। खानपुर की सड़क की तरफ सरकार का ध्यान इसलिए दिलाना चाहता हूं क्योंकि इसका सब को पता है कि वहां पर उत्तरी भारत की लड़कियों की सब से बड़ी संस्था है और वहां पर बाहर से चारो तरफ से लड़कियां आती 'हैं। वहां जितने साधन होंगे लड़कियों का उतना ही भला होगा। यह गांव बीच मे पड़ता है और लोग कहते हें कि वे वहां पर जा नहीं सकते, लड़कियो को वहां पर कैसे भेजें। वहां पर कोई बस नहीं जाती है। वहां के लोगो के पास इतना पैसा नहीं है कि वे लड़कियों को 'होस्टल मे दाखिल करें। इसलिए आपसे मेरी यह प्रार्थना हे कि इन सब सड़कों को बनाया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं शिक्षा का जिक्र करना चाहूंगा। शिक्षा मन्त्री माननीय मुलाना साहब आ गए हैं मैं इनसे कुछ स्कूलो को अपग्रेड करने की बात कहना चाहूंगा। कटवाल, मोई हुड्डा और खेड़ी धनकन मे 10+2 और दोधवा मे 8वीं से 10वीं तक स्कूल बनाने की बात है। मुलाना साहब, मेरा आपसे कहना है कि वहां स्कूलों में टीचर्ज नहीं हैं, वहां पर बहुत बुरी हालत है इसलिए आप इस बारे में भी गौर

करे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो वहां पर कह कर आया था कि जब मास्टर्ज आएंगे तब ही वे स्कूल मे आएंगे। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, हैल्थ मिनिस्टर जी भी यहां पर बैठी हैं में उनसे भी एक दो बाते कहना चाहूंगा। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए।)

Mr. Speaker: Dharampal Ji, You have already taken 50 minutes. Please wind-up.

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां रिवाड़ा गांव मे एक चौरिटेबल हॉस्टिपल बना रखा है और उस पर 20—30 लाख रुपए गवर्नमैंट ने भी खर्च किये हुए हैं। उसको अगर गवर्नमैंट टेकओवर कर ले तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि वहां पर एक ही डाक्टर है और वह भी कभी आता है और कमी नहीं आता है। अगर गवर्नमैंट उसको टेकओवर कर ले तो गवर्नमैंट को वहा पर बिल्डिंग भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा मोई गाव मे भी एक प्राईमरी हैल्थ सैन्टर बनवाने का कष्ट करें। सरगथल, रिठाल और विधल तीन गांवों मे भी वैटनरी डिस्पेंसरी खोलने का कष्ट करे। स्पीकर सर, मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूं कि चौधरी छोटू राम जी का जो सामान लाहौर में था अगर मैं अब इसकी बात करूंगा तो फिर चौटाला साहब की बात आ जाएगी। मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता हू। क्योकि वे अपने शासनकाल में शासन चलाने के लिए और लोगों को एक्सप्लायट करने के लिए लाहौर गए और पता नहीं वहां कहीं से

कुछ सामान खरीद कर ले आए लेकिन वह सर छोटू राम जी का सामान नहीं था।

Mr. Speaker: This is not the subject of the budget. Please sit down.

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि चौटाला साहब सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए इतने नीचे स्तर के प्रयास कर सकते हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि हमें अपने तौर पर लाहौर जाना चाहिए और सर छोटू राम जी का सामान लाने का प्रयास करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

कुमारी शारदा राठौर (बल्लभगढ़): स्पीकर सर, मैं 9 जून को पेश होने वाले बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुंई हूं। इस बजट के लिए में वित्तमंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं जिन्होंने बहुत ही शानदार और कर मुक्त और रोजगारोनुमुखी बजट पेश किया है। अध्यक्ष महोदय मैं उनको इस बात के लिए भी बधाई देना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी ने चुनावो से पहले अपने घोषणा पत्र मे जो–जो बाते कहीं थी उनके अनुरूप ही उन्होंने इस बजट को पेश किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं महिला प्रतिनिधि होने के नाते हरियाणा की महिलाओ की तरफ से भी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होने अपने इस थोड़े से शासन काल मैं हरियाणा की महिलाओं के विकास के लिए कई

बिन्दुओ को इस बजट में लिया है और महिलाओ के लिए कई योजनाएं शुरू करी हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले काफी समय से पिछली सरकारों ने हरियाणा में लिंग अनुपात के अन्दर जो अन्तर आ रहा है, उसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए थे। लेकिन हमारी सरकार ने आते ही इस तरफ ठोस कदम उठाए हैं। आज हरियाणा में 1000 लड़को के मुकाबले में लगभग 851 लड़कियां हैं। जिससे स्थिति बड़ी भयावह होती जा रही है। इससे एक सामाजिक विषमता भी पैदा होती है। इसके कारण ही बलात्कार जैसी घटनाएं, महिलाओं की खरीद फरोख्त या सन्तानोत्पत्ति के लिए महिलाओं को किराए पर लाने और शादियों के लिए दूसरे प्रदेशों से लड़कियां लाने जैसी समस्याएं पैदा होने लग रही हैं। लेकिन हमारी सरकार ने पी०एन०डी०टी० ऐक्ट जैसी योजना को एक अच्छे ढंग से दोबारा बनाकर उसमें धार्मिक, सामाजिक संगठनो को भी शामिल करके इस भयावह होती जा रही बुराई से मुक्ति पाने की कोशिश की है। सरकार ने महिलाओ को आगे लाने के लिए और लड़कियों की पैदाइश को प्रोत्साहन देने के लिए एक स्कीम और बनायी है जो लाडली स्कीम के नाम से जानी जाएगी। इस स्कीम में दूसरी लड़की के पैदा होने पर बेटी के मां बाप को पाचं हजार रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, इससे लड़की की पैदाइश को बढ़ावा मिलेगा। इसी तरह से इस स्कीम के तहत जिनके परिवारो में एक मात्र संतान बेटी ही है ऐसे परिवारो को पेशन देने की भी सरकार की योजना है जोकि बहुत ही सराहनीय हे। इसी तरह से अनुसूचित जाति और गरीबी खा रेखा से नीचे

जीवन यापन करने वाले इन परिवारों की कन्याओ के विवाह के लिए जो पहले 5100 रुपये दिए जाते थे, उसके स्थान पर अब हमारी सरकार ने 15 हजार रुपये देने का प्रावधान किया है ताकि लड़कियों को उनका उचित अधिकार मिल सके। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमत्री जी ने, हमारी सरकार ने महिलाओ को प्रोत्साहन देने के लिए महिला सहकारी वि हास बैंक की भी एक योजना बनायी है। इनमे महिलाएं ही कर्मचारी रखी जाएंगी जिससे महिलाओं के लिए रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे। इसी तरह से जींद मे महिला कालेज की बात आयी। इंदौरा जी ने कहा था कि इदिरा गांधी के नाम पर केवल एक ही कालेज की स्थापना की गयी है। इदौरा जी, आपको इस बारे मे हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे नेता के लिए हमारे दिलों मे 'कितना सम्मान है। हम आपकी तरह नहीं हैं कि चौधरी देवीलाल के नाम पर सिरसा में धक यूनिवर्सिटी खोल दी जिसके कारण हजारों छात्र सड़कों पर आ गये। आपने तो चौधरी देवीला न के नाम पर छात्रो की भावनाओ का भी ख्याल नहीं रखा। आपने उस यूनिवर्सिटी का नाम ताऊ देवीलाल के नाम से इसलिए रखा ताकि आप बार बार वोट बटोरते रहें लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम अपने नेता के नाम से वोट बटोरने जैसा काम नहीं करते। हम लोग उनके नाम पब? कुछ करके दिखाने का काम करते हैं। इंदौरा जी, आपने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचायी है और आप हमारे नेताओं का सम्मान नहीं करते। हमें आपसे इसके लिए कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है इसलिए आपको इस बारे में माफी मांगनी

चाहिए। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, हम् री सरकार ने 13 हजार टीचर्ज की जो भर्ती की घोषणा की है उसमें भी 33 परसैंट महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सराहनीय है इसके लिए हरियाणा की सम्पूर्ण महिलाओ की तरफ से मैं आदरणीय मुख्यमत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं। पिछली सरकार ने महिलाओं के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, एडवर्स सैक्स रेशो से संबंधित जो समस्याएं हें उनको उठाने के लिए और महिलाओ को प्रोत्साहन देने के लिए एवं लड़कियों की पैदाइश को प्रोत्साहन देने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी का खासतौर पर धन्यवाद करना चाहूगी। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से जो लाटरी चल रही थी उसको मुख्यमंत्री जी ने आते ही बंद कर दिया, इसके लिए भी हरियाणा की महिलाएं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हें। क्योंकि लाटरी से कहीं न कहीं महिलाएं ही खामियाजा भुगत रही थीं। अध्यक्ष महोदय मैं हरियाणा के युवाओं की तरफ से वित्त मंत्री जी का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी क्योकि यह जो बजट है यह रोजगारोनुमुखी बजट है। इंदौरा जी, आपकी सरकार ने बेरोजगारी को दूर करने के नाम पर बेरोजगारी भत्ता देकर बेरोजगारो को लोलीपोप के रूप में रोजगार देने की बात कही थी। आपने उनको रोजगार के नाम पर लोलीपोप पकड़ा दिया था। इन्होने बताया था कि बजट में हमारी सरकार ने बेरोजगारी भत्ते के रूप में 45 करोड़ रुपये रखे थे लेकिन मात्र 3–4 करोड़ रुपये ही बेराजगारी भत्ते के रूप में दिये गये। हमारे

हरियाणा के युवाओं के साथ इससे बड़ा भद्दा मजाक ओर कोई नहीं हो सकता। मैं वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूं कि हमारी सरकार से इस भत्ते की पात्रता के मानदण्डों को तर्कसंगत बनाया है और 105 करोड़ रुपये की राशि बजट में बेरोजगारी भत्ते के रूप मे रखी गई है जो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। मैं इसके लिए हरियाणा के युवाओं की तरफ से उनका धन्यवाद करना चाहती हूं। जो नयी इंडस्ट्री खुलने जा रही हे उनमें भी हरियाणा के कम से कम 10 लाख युवाओ को रोजगार मिलेगा। इससे भी काफी हद लेक हम बेरोजगारी दूर करने मे कामयाब हो सकेंगे। पंजाब के गांवो के लगभग हर घर से कोई न कोई नौजवान विदेशो मे रोजगार कर रहा हे जबकि हरियाणा से विदेशों मे रोजगार पाने वालों की संख्या बहुत ही कम है। हमारी सरकार ने विदेशों में रोजगार दिलाने के लिए विदेशी रोजगार ब्यूरो बनाने की योजना बनाई है। एक उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी इस ओवरसीज इम्प्लायमैंट के लिए बनाई है इससे हरियाणा के युवको को विदेशों में रोजगार के अवसर मिलेंगे। आजकल जो भूमंडलीकरण का दौर है इसमें हमारे नौजवान भी बाहर जाकर सीख पाएंगे और इससे प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। इसके लिए नौजवान रोजगार सेवा योजनाएं औद्योगिक नगरो जैसे फरीदाबाद, गुड़गांव, यमुनानगर, सोनीपत मे स्थापित करने की योजना बनाई गई है इससे भी रोजगार को बढ़ावा देने मे मदद मिलेगी। हमारी कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता सेनानियो का सम्मान करने वाली पार्टी है। मुख्यमंत्री जी जो स्वयं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से है

इन्होने सत्ता संभालते ही स्वतंत्रता सेनानियो को जो सम्मान पेशन मिलती थी, उसको 1400 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये कर दिया है। मैं समझती हूं कि इससे बड़ी श्रद्धांजली देश के उन सपूतो को नहीं दी जा सकती जिनकी वजह से आज हम आजाद हिन्दुस्तान मे जी रहे हैं। पिछली सरकार ने कारगिल शहीदों के नाम पर जो छोटी और ओछी राजनीति की, वह सबको मालूम है। उन्होने विभित्र योजनाएं देने की घोषणा की जो सिर्फ वोट बटोरने तक सीमित रही। वे योजनाएं न जाने कहां गुम हो गई? चौटाला जी ने अपने शब्दों के जाल में न जाने कहां उनको छुपा लिया? शहीदो के परिवार उन योजनाओं का लाभ पाने के लिए भटकते रहे। हमारी सरकार ने किसानों को सहायता देने के लिए और कृ षि क्षेत्र में विकास के लिए ट्रैक्टर पर रजिस्ट्रेशन फीस भी खत्म की है। सरकार ने आपदा राहत कोष की राशि 124.37 करोड़ रुपये बढ़ाई है इससे किसानों को बहुत फायदा हुआ। ओलावृष्टि से भी फसलों को बहुत नुकसान हुआ। गेहू की फसल के लिए 50 प्रतिशत और अन्य फसलों के लिए 25 प्रतिशत की मुआवजा राशि में वृद्धि देकर हमारी सरकार ने किसानों को आर्थिक रक्षा प्रदान करने की कोशिश की है, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहती हूं। पिछली सरकार ने किसानों पर तरह तरह से मुकदमे चला दिए और दमनकारी नीति अपनाई। हमे खुशी हे कि अब कोई ऐसा रास्ता अख्तयार नहीं किया जाएगा जिससे किसानों को नुकसान हो। बिजली के बिलों के भुगतान के हल के लिए सरकार

ने कमेटी गठित कर दी है और इसके लिए जल्दी ही आसान तरीके निकाले जाएंगे।

Mr. Speaker: Madam Rathore, please wind up.

कुमारी शारदा राठौरः स्पीकर सर, किसानों के बकाया बिजली के बिल अब आसानी से जमा हो पायेगे और किसानों को राहत मिलेगी। सरकार ने इसके लिए 1706. 21 करोड़ रुपये की सहायता देने की बात कही है। जिसमें से 1256 करोड़ रुपये की सब्सिडी रखी गई है। अभी बात हो रही थी, इन्दोरा साहब कह रहे थे कि हमारी सरकार के वक्त मे भी 15 लाख रुपये गुड़गांव में किसानो को मुआवजा दिया है। लेकिन ऐसे भी कई केसिज गुड़गांव में आये हैं कि किसानो की जमीन को औने–पौने दामो में खरीदवाकर पिछली सरकार की मिलीभगत से और साठगाठ रमे वह जमीन बिल्डिरों को रिलीज करवाई गई। बाद में बिल्डिरो ने उस जमीन को सोने के भाव बेचा जबकि किसान अपने मुआवजे की राशि बढवाने के लिए कोर्ट कचहरी के धक्के खाते रहे और दर– दर भटकते रहे। हमारी सरकार ने उस जमीन का एक फ्लैट रेट निर्धारित करके किसानो को दर– दर भटकने से और बिल्डिंरों के चंगुल से बचाया है। अब उनका शोषण नहीं हो पायेगा। हमारी सरकार ने सिंचाई के पानी के समान बंटवारे की बात कही है। मुझे लगता हैं कि हम निकट भविष्य मे पानी का समान बंटवारा कर पायेगे। जिससे सभी जिलो के किसानो को फायदा पहुंचेगा। वर्तमान समय मे जो जल संसाधन हैं उनको

विकसित किया जा रहा है और उनकी भी वृद्धि की जा रही है इनमें सुधार की योजना है, इससे भी किसानों को काफी फायदा मिलेगा। मैं कहना चाहूंगी कि किसानो के साथ–साथ हमारी सरकार कर्मचारियो के लिए भी बहुत उदारतापूर्ण की नीति अपनाए हुए है। हमारी सरकार कर्मचारियों की मांगों के लिए और कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करती है। कर्मचारियो की बेटी के विवाह पर सरकार द्वारा जो पहले 25 हजार रुपये लोन के रूप मे दिये जाते थे, आज उस राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है। इसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है। जो कर्मचारी रिट्रैंच किये गये थे, जिनकी छंटनी हुई थी, उन कर्मचारियों के प्रति भी सरकार उदारतापूर्ण रवैया अपनाये हुए है। आज सुबह भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पिछली सरकार द्वारा गलत तरीके से की गई भर्ती के कारण ही कुछ कर्मचारियों को इस सरकार द्वारा निकाला गया है लेकिन नई भर्ती मे सरकार उनको कुछ वेटेज जरूर देगी और सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। इस तरह से कर्मचारियों के लिए सरकार उदारतापूर्ण नीति अपनाये हुए है। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैं फरीदाबाद जिले से संबध रखती हूं इसलिए फरीदाबाद के बारे मे कुछ कहना चाहती हूं। फरीदाबाद जिला एक समय में एशिया में नम्बर एक ओद्योगिक नगर हुआ करता था। जब कांग्रेस का राज था तब हम नम्बर एक पर पहुंच गये थे। हमारा जिला हिन्दुस्तान की एक प्रमुख औद्योगिक नगरी थी लेकिन जब सरकार बदली तो सब कुछ बदल गया। पिछली

सरकार ने तो हमारे जिले फरीदाबाद को फकीराबाद मे परिवर्तित कर दिया था वहां लगभग एक हजार उद्योग धन्धे बन्द हो गये या उनका प्लायन हुआ। फैक्ट्ररियो पर मोटे–मोटे ताले लग गए। यह सब गलत नीतियों के कारण और पूर्व मुख्यमत्री एव उनके दोनों बेटों की वहज से हुआ क्योंकि उनकी नीति यह थी कि फरीदाबाद तो सोमनाथ का मन्दिर है इसे जितनी बार लूटा जाये उतना कम है। वहां व्यापारी और उद्योगपति अगर एक रुपया कमाते थे तो मुख्यमंत्री और उनके दोनों बेटे 75 पैसे ले जाते थे और बाकी 25 पैसे अधिकारियो और चेले चपाटे ले जाते थे ऐसे माहौल मे उद्योगपति कहां रह पाते इसलिए उनका वहां से प्लायन हो गया। इसी वजह से हरियाणा की आर्थिक स्थिति को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा।

Mr. Speaker: Madam Rathore, please wind up.

कुमारी शारदा राठौरः स्पीकर सर, हमारी सरकार ने नई उद्योग नीति इसी महीने घोषित की है। उसमे बहुत सारे रोजगार के अवसर तो हैं ही साथ ही पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए भी योजनाएं हैं। इसमें उद्योगो को लगाने के लिए बढ़िया इन्फ्रास्ट्रक्चर देने की योजनाएं हैं जो बाहरी निवेशक आयेंगे तो उनके लिए अच्छा औद्योगिक वातावरण पैदा करने की भी हमारी सरकार की योजनाएं हैं। जिससे पूरे हरियाणा के निवासियो को फायदा मिलेगा और हरियाणा जो उद्योग के क्षेत्र मे पिछड़ गया था, फिर से एक बार नं० 1 पर आ सकेगा। इसके लिए सरकार ने

कलस्टर डिवैल्पमैट प्रोजैक्ट बनाया है। जिस तरह पानीपत में वस्त्र उद्योग को विकसित किया जाएगा, उसी तरह गुड़गांव मे आटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को विकसित किया जाएगा और फरीदाबाद में छोटे इजीनियरिंग वर्क्स को बढ़ावा दिया जाएगा उससे मुझे लगता है कि फरीदाबाद फकीराबाद से पुनः फरीदाबाद बन जाएगा और जिन मजदूरों की फैक्ट्रियां बद होने से रोजी–रोटी छिन गई थी, एक बार फिर उन मजदूरों के चहेरे पर खुशी की हम रोशनी देख पाएंगें। पिछली सरकार मे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई थी। सरकारी स्कूलो से लोगो का विश्वास उठ गया था। इसका नतीजा यह हुआ कि छोटे–छोटे प्राइवेट स्कूल खुल गए थे और लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ाने लगे। 2 साल पहले चौटाला जी ने घोषणा की थी कि प्राइमरी लैवल से हम अंग्रेजी शिक्षा पढ़ाना शुरू करेगे। वह योजना केवल योजना ही रह गई क्योकि उस योजना का योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वयन नहीं हुआ। आनन–फानन में 2800 टीचर्स की भर्ती की गई लेकिन इसका बजट मे कोई प्रावधान नहीं रखा गया। 2600 टीचर्स भर्ती तो हो गए लेकिन उनकी तनख्याहो की हालत यह रही के वे तनख्वाहों के लिए भटकते रहे लेकिन उन्हें तनख्वाह नहीं मिल पाई। अब उनको तनख्वाहें देने का प्रावधान हमारी सरकार कर रही हे। मुख्यमंत्री महोदय ने प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चो को जो अनिवार्य शिक्षा देने की घोषणा की है वह शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा प्रयास है। मैं समझती हूं कि हरियाणा

जेसे प्रदेश में शिक्षा के प्रचार और प्रसार की बहुत आवश्यकता है। हम अभी शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को पिछड़ा हुआ समझते है, आज के दौर मे जब दूसरे प्रदेश के बच्चों के साथ हमें प्रतिस्पर्धा करनी होती है और जब हम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की बात करते हैं तो हमे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना ही होगा। शिक्षा पर ज्यादा बजट खर्च करने की और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। इसके लिए वित्त मंत्री ने शिक्षा मे गुणवत्ता लाने के लिए 'राजीव गांधी एजुकेशन सिटी' नाम की योजना बनाई है। विभिन्न विषयों मे शिक्षा और श्रेष्ठ माहौल यह सिटी दे पाएगा। इसमें हरियाणा के बच्चों के लिए जो 25 प्रतिशत आरक्षण रखा गया है। उससे हमारे बच्चो को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अभी 13 हजार टीचर्स की भर्ती की घोषणा की गई हे। पिछली सरकार मे कई स्कुलों में ताले लग गए थे। उस समय जो स्कूल बन्द हो गए थे, इन टीचर्स की भर्ती से वे ताले खुलने का काम जल्दी हो सकेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। शिक्षा मे गुणवत्ता लाने के लिए जो जे.बी.टी. टीचर्स की क्वालिफिकेशन को बी०ए० किया गया है यह एक प्रशसनीय कदम है इसके अलावा 50 हजार छात्रो को राजीव गांधी छात्रवृत्ति देने की योजना से सरकारी स्कूलों के प्रति लोगो का विश्वास बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा और प्रतिस्पर्धा की भावना हमारे छात्रो मे पैदा होगी। हर जिले मे सरकारी माडल स्कूल खोलने की योजना का काम भी एक सराहनीय कदम हे। मैं कहना चाहती हूं कि सरकार ने स्थानीय निकायों को जो वित्तीय सहायता देने की घोषणा की

है उससे इनको अपना काम चलाने में सहायता मिलेगी। हमारा जो फरीदाबाद का म्यूनिसिपल कारपोरेशन है तो अब उसको भी सहायता मिलेगी। इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत कुछ जिलों को चुना गया है इस मिशन के तहत हमारे जिले को पहली योजना मे ही चुना गया है, इसके लिए में फरीदाबाद के निवासियों की तरफ से सरकार का धन्यवाद करती हूं क्योकि 47 करोड़ की अतिरिक्त सहायता हमारे शहर के नवीनीकरण के लिए मिलेगी। पंचायतों को अधिक प्रशासनीय और वित्तीय अधिकार देने की बात बजट में कही गई है, इसके लिए भी मैं सरकार का धन्यवाद करती हूं। राजीव गांधी ने जो पंचायती राज का सपना देखा था, सही मायनो में कांग्रेस की सरकार पंचायती राज संस्थाओं को उनके वित्तीय और प्रशासकीय अधिकार देकर राजीव गांधी के उस सपने को साकार कर रही है। अध्यक्ष महोदय, में सदन का अधिक समय न लेते हुए कुछ बातें और कहना चाहूंगी कि वित्त मंत्री जी ने बजट बनाते हुए हर वर्ग के हित्तो को ध्यान में रखा है। इससे बेहतरीन बजट और कोई नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, मेरे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि इन सब योजनाओ को लाग करने के लिए साधन कहां से जुटाए जायेगे, पैसे का इंतजाम कहा से किया जायेगा और आने वाले समय में हमें लोन मिलना बंद हो जायेगा जिससे हमारी स्टेट कर्जदार हो जायेगी। वे इस तरह की फिजूल कों बातें कर रहे थे। मै इनको बताना चाहूंगी कि आर्थिक मजबूती के लिए फिस्कल रिस्पोंसिबिल्टि बिल और फिस्कल मैनेजमैंट बिल हमारी सरकार ला

रही है जिससे हरियाणा प्रदेश को आर्थिक मजबूती मिलेगी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री जी ने एक रिसोर्सिज मोबीलाईजेशन कमेटी का गठन किया है जिसके मुख्यमंत्री जी स्वयं अध्यक्ष हैं। इससे भी हमारे संसाधनों में इजाफा होगा। अध्यक्ष महोदय, इस बजट मे जो भी योजनाएं दी गई हैं। हमे पूरा विश्वास हैं कि इस बजट के द्वारा हम उनको लग करने में समर्थ होंगे। वित्तमंत्री जी –का मैं दोबारा से धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा बजट प्रदेश की जनता को दिया है।

श्री अर्जन सिंह (छछरौली): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे आखिर में बोलने के लिए समय दिया है फिर भी जैसा कहते हैं कि देर आये दुरुस्त आये। अध्यक्ष महोदय, जहां तक बजट की बात है हम भी बजट की प्रशंसा करते हैं कि वित्त मंत्री जी ने बहुत अच्छा बजट प्रदेश के लोगों को दिया है लेकिन बड़े दुख की बात है कि इसमे यमुनानगर जिले का कहीं कोई जिक्र नहीं है। मेरा वित्तमंत्री जी से अनुरोध है कि हमारे यमुनानगर जिले की तरफ भी ध्यान दें ताकि यमुनानगर के लोग यह महसूस ना करें कि उन्हे शेष हरियाणा से अलग थलग रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के साथी बजट की तारीफ कर रहे हैं। मै तो यह कहना चाहूंगा कि सरकार ऐसे काम करे कि हम भी तारीफ करें। यदि सरकार अच्छे काम करेगी तो अच्छे काम का मैसेज जनता तक अपने आप जायेगा। जनता भी आपकी

तारीफ करेगी और हम भी तारीफ करेंगे। जो आज सरकार मे हैं वे पांच साल तक अपोजीशन मे रहे और जो अपोजीशन मे बैठे है वे सरकार मे थे। पिछले सालों में यहां क्या हुआ उसको अब दोहराने की जरूरत नहीं है। सरकार को अब ऐसे काम करने चाहिएं जो दूसरों को अच्छे लगें। डाक्टर इंदौर। साहब कुछ समय पहले सत्ता में थे और आज ये सरकार से मांग कर रहे हैं। क्या ये 6 साल तक सत्ता में नहीं रहे? ये जो बात आज कह रहे हैं वे काम पिछले पांच छः साल में कर लेने चाहिए थे। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त पिछले सैशन मे एक बात आई थी कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वालों को पीले कार्ड ईश करने के लिए दोबारा से सर्वे किया जायेगा। उस समय यह बात भी आई थी कि बुढ़ापा पैंशन के लिए भी दोबारा सर्वे करवाया जायेगा। मैं मुख्यमंत्री जी से जानकारी चाहूंगा कि कब तक यह कार्य सरकार कर रही है? इसके अलावा पिछले सैशन में मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा और की थी कि सभी विधायकों को पी०ए० रखने के लिए भत्ता और एक–एक कम्प्यूटर दिया जायेगा। हमें बड़ी खुशी हुई थी कि हमें भी कम्प्यूटर सीखने का अवसर मिलेगा और हम सदन मे पूरी जानकारी के साथ आयेंगे।

परिवहन मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि हर विधायक को एक व्यक्तिगत सचिव देने के लिए बिल का मसौदा तैयार होकर इसी सत्र मे पास हो जायेगा।

श्री अर्जन सिंह: अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि...

Mr. Speaker: Now, the House is adjourned till 9.30 a.m. tomorrow, the 14th June, 2005 and Shri Arjan Singh will continue his speech tomorrow.

18.30 hrs

(The Sabha then *adjourned till 9.30 a.m. on Tuesday, the 14th June, 2005).